चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 21 नवंबर – 27 नवंबर 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

अंबानी बनाएंगे पाकिस्तान के लिए मिसाइल

पाकिस्तान के लिए एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का निर्माण अब भारत में होगा. इसे रिलायंस डिफेंस बनाएगी, जिसके मालिक अनिल अंबानी हैं. मोदी सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की सारी सीमाएं लांघ गई है. राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हथियार के दलालों के साथ मोदी सरकार के साठगांठ और मेक इन इंडिया के नाम पर हथियार दलालों और उद्योग घरानों को मालामाल करने के खेल का हम पर्दाफ़ाश कर रहे हैं. इसका शर्मनाक पहलू ये है कि हथियार सौदे में चल रहे घपले को सरकार देशभक्ति के नाम पर अंजाम दे रही है. एक तरफ़ पाकिस्तान और आंतकवाद का डर दिखा कर देश में अति-राष्ट्रवाद का माहौल तैयार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ़ ऐसी कंपनी से हथियार ख़रीद रही है, जो न सिर्फ़ काली-लिस्ट में शामिल है, बल्कि वो कंपनी जो हथियार भारत को दे रही है, वही हथियार पाकिस्तान को भी सप्लाई कर चुकी है. एक तरफ़ हम पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं और दूसरी तरफ़ ऐसी ब्लैक-लिस्टेड कंपनियों को स्थापित करने पर तुले हैं, जो पाकिस्तान को हथियार बेच रही हैं. हम पाकिस्तान को हथियार देने वाली कंपनियों को बढ़ावा देकर किस देशभक्ति का उदाहण पेश कर रहे हैं? हैरानी तो इस बात की है कि विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी जिन हथियार माफियाओं के ख़िलाफ आवाज़ उठाती रही, सरकार बनने के बाद उन्हीं हथियार माफियाओं को स्थापित करने के लिए सारे नियम-क़ानून और मर्यादाओं को तोड़ रही है. हम मोदी सरकार द्वारा हथियार की ख़रीददारी में होने वाले ऐसे घोटाले का पर्दाफ़ाश कर रहे हैं, जिसे जानकर देश का सिर शर्म से झुक जाएगा.

संतोष भारतीय

सात नवंबर को डिफेंस एक्वीज़िशन कॉंसिल की बैठक शाम छह बजे हुई. इस बैठक में ये फ़ैसला लिया गया कि एक विशेष ब्लैक-लिस्टेड कंपनी से सामान ख़रीदा जा सकता है, अगर पॉलिसी बदल दी जाय तो. दरअसल, इस बैठक में डिफेंस की ख़रीद की पॉलिसी बदलने की बात हुई और ये निर्णय ले लिया गया. इसीलिए ये ज़रूरी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने की. इस ब्लैक-लिस्टेड कंपनी से सामान ख़रीदने का कारण ये बताया गया कि हमारे देश की एक क्रिटिकल सिचुएशन में क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, इसलिए सामान ख़रीदने की ज़रूरत है. इस कंपनी का नाम है रायनमेटल इंटरनेशनल होल्डिंग. ये कंपनी भारत में ब्लैक-लिस्टेड है और इसपर बैन लगा हुआ है. बैन इसलिए लगा हुआ है, क्योंकि इस कंपनी का सामान घटिया है और जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ये कंपनी रिश्वत देने के मामले में फंसी हुई थी. एक बड़े रक्षा सौदे में इसने बहुत से लोगों को रिश्वत देने की कोशिश की थी, ख़ासकर ऑर्डिनेंस बोर्ड के मैनेजर को. ये कंपनी पकड़ी गयी थी और तभी इसको तत्काल ब्लैक-लिस्ट किया गया था. उस समय इस कंपनी को बैन करने के लिए दबाव बनाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के थे. अब मज़े की बात यह है कि वही लोग, जिन्होंने उस समय बैन करने के लिए दबाव बनाया था, आज इसका बैन हटा रहे हैं. इसका कोई तर्क समझ में नहीं आता.

एक तर्क ज़रूर समझ में आता है कि इस कंपनी ने इस वर्ष के शुरुआत में एक एमओयू साइन किया. वह एमओयू रिलायंस डिफेंस के साथ साइन किया, जिस कंपनी के मालिक प्रसिद्ध उद्योगपति श्री अनिल अंबानी हैं. अनिल अंबानी ने गन और एम्यूनिशन दोनों के लिए एमओयू साइन किया है. जिसके तहत ज्वाइंट वेंचर होगा और ये भारत में फैसेलिटी सेटअप करेंगे. सवाल ये है कि भारत को अगर उदाहरण के लिए 400 गन्स की ज़रूरत है, वो भारत ख़रीद लेगा फिर इसके बाद ये गन्स कहां जाएंगी? किसको बेची जाएंगी? क्या पाकिस्तान को बेची जाएंगी, बांग्लादेश को बेची जाएंगी या फिर नेपाल को बेची जाएंगी? लेकिन ये अपने पड़ोसियों को तो बेची नहीं जा सकतीं, क्योंकि ये रक्षा से जुड़ी हुई चीज़ हैं. अगर हम पड़ोसियों को बेचते हैं, तो हम अपने देश को कमज़ोर करते हैं. इसके जवाब में इन्होंने कहा कि सेटअप हम इंडिया में करेंगे, लेकिन ये गन, एंटी-एयरक्राफ्ट गन हम सिंगापुर को बेचेंगे. लेकिन सिंगापुर के पास तो इतनी बड़ी आर्मी है नहीं कि वो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करे. दर-हक़ीक़त ये गन्स सिंगापुर के रास्ते पाकिस्तान भेजी जाएंगी. इसका सीधा-सीधा मतलब है कि वो गन, एंटी-एयरक्राफ्ट, मिसाइल गन्स बनेंगी इंडिया में, लेकिन सिंगापुर के ज़रिए बेची पाकिस्तान को जाएंगी. इससे बड़ा देशप्रेम क्या हो सकता है या इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? आज के संदर्भ में अगर देशद्रोह और देशप्रेम की बात देखी जाए, तो इससे बड़ा देशद्रोह हो ही नहीं सकता.

रायन मेटल का जो हिंदुस्तानी हेड है, वो एक रिटायर्ड फ़ौजी है, जिसका नाम कर्नल अनिल नंदा है, जिसने अनिल अंबानी के साथ एमओयू साइन किया है. ये कर्नल अनिल नंदा कई जगह पर ये कहते पाये गये कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर तो इनकी जेब में हैं और बॉस की यानि अनिल अंबानी की इनसे हर दूसरे दिन बात होती है.

इसके लिए इन्होंने पूरी पॉलिसी को बदल दिया. इन्होंने ये कहा कि हमें इस सामान की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमें इस कंपनी से ये सामान ख़रीदना है. जबकि अभी-अभी रूस के साथ हमारा एक रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत उससे एस-400 नाम का मिसाइल सिस्टम ख़रीदने जा रहा है. अगर इस मिसाइल सिस्टम को हम ख़रीद रहे हैं, तो हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, जिसके समझौते पर रूस के साथ हस्ताक्षर हो चुके हैं. जब हम रूस से ये सिस्टम ले रहे हैं, तो फिर रायनमेटल से क्यों ले रहे हैं? जबकि रसियन टेक्नोलॉजी, रायनमेटल की टेक्नालॉजी से कई गुना ज्यादा बेहतर है. अब एक और बड़ी ख़तरनाक चीज, रायनमेटल पहले से ही इस इक्विपमेंट को पाकिस्तान को सप्लाई कर रही है. पाकिस्तान आर्मी को यही कंपनी सुर्ज में ट्रेनिंग भी दे रही है. अब ये आश्चर्य की बात है कि हम वो चीज़ क्यों ख़रीद रहे हैं और किसके कहने पर ख़रीद रहे हैं, जो चीज़ पहले से ही पाकिस्तान के पास इसी कंपनी के द्वारा पहुंचाई जा चुकी है? तब हम पाकिस्तान से बेहतर तो हैं ही नहीं. तो क्या इससे ये मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि किसी न किसी को बहुत पैसा मिल रहा है, जिससे वो ये भी ध्यान नहीं रख रहा है कि इससे हमारा देश बिक जाएगा या किसी को देश बेचने के लिए बहुत पैसा मिल रहा है. ये देश इत्मीनान से बेचा जा रहा है और देश बेचने वाले थोड़े दिनों बाद हल्ला मचाएंगे कि हमसे ज्यादा

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सरकार वही, दलाल वही सिर्फ़ हथियार का नाम बदला है P-2

ये घोटाले का लड़ाकू विमान है P-3

सरकार वही, दलाल वही सिर्फ़ हथियार का नाम बदला है

17 अगस्त से 23 अगस्त 2015 के अंक में **चौथी दुनिया** में प्रकाशित रिपोर्ट, जिसमें रायनमेटल नामक हथियार कंपनी की करतूत का ख़ुलासा हुआ था.

चौथी दुनिया ने हथियारों की ख़रीदादारी में हथियार माफिया के वर्चस्व का एक और ख़ुलासा 17 अगस्त 2015 के अंक में किया था. हमने ये ख़ुलासा किया था कि इज़राइल से स्पाइक मिसाइल ख़रीदने में हथियार के दलाल किस तरह सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. हमने उन हथियार के दलालों को बेनक़ाब किया था, जो रक्षा मंत्री से ज्यादा ताक़तवर हैं. जिनकी हां के बिना भारत सरकार कोई हथियार नहीं ख़रीद सकती. हमने हथियार के उन दलालों के नाम बताए थे, उनकी क्रार्य प्रणाली का ख़ुलासा किया था. इस बार की लीड-स्टोरी में प्रधान संपादक **संतोष भारतीय** ने एस-400 की ख़रीददारी में हुए घपले का ख़ुलासा किया है, जबकि 17 अगस्त 2015 का ख़ुलासा स्पाइक मिसाइल को लेकर था. दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही मामलों के केंद्र में रायनमेटल नामक कंपनी ही है. मतलब, मंत्री वही, सरकार वही, अधिकारी वही, दलाल वही और हेराफेरी भी वही. बदला तो सिर्फ़ हथियार का नाम. रायनमेटल का कारनामा समझने के लिए हम यहां 17 अगस्त 2015 की रिपोर्ट का कुछ अंश पेश कर रहे हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो

भारत में हथियार लॉबी बहुत सक्रिय और संगठित तरीक़े से काम करती है. उसके आगे सरकार की भी नहीं चलती. वह पैसे के दम पर अपने हिसाब से सौदा तय करती है. ऐसा लगता है, मानो रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए सामान ख़रीदने के लिए नहीं, बल्कि हथियार के दलालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करता है. भारत में हथियार लॉबी बहुत बड़ी नहीं है. पांच से दस लोगों का एक कॉकस है, गैंग है. उसके सबसे बड़े और किंग-पिन का नाम सुधीर चौधरी है, जो इंग्लैंड में रहकर सब कुछ ऑपरेट करता है. बराक मिसाइल की आपूर्ति में हुए घोटाले में भी उसका नाम आया था, लेकिन सीबीआई ने केस बंद कर दिया. सीबीआई ने कहा कि वह उसके ख़िलाफ़ कोई सुबूत एकत्र नहीं कर सकी. मीडिया भी चौधरी के बारे में नहीं बताता कि उसके पारिवारिक रिश्ते किन-किन पार्टियों के किन-किन नेताओं के साथ हैं. इसके अलावा भी कुछ और नाम हैं, जिनका ख़ुलासा अलग-अलग हथियार सौदों में हुआ है, जिनमें सुरेश नंदा, रवि ऋषि और अभिषेक वर्मा शामिल हैं. उक्त सारे लोग मिल-जुल कर काम करते हैं. उनके साथ सेना एवं रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, विभिन्न पार्टियों के नेता और पत्रकार मिल-जुल कर काम करते हैं. यह एक ऐसा गैंग है, जो हर सौदे पर मुनाफ़ा कमाता है. इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि सरकार किस पार्टी की है और मंत्री कौन है. मज़ेदार बात यह है कि दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इसे सारे लोग बख़ूबी जानते हैं.

अब स्पाइक मिसाइल की बात करते हैं. जर्मनी की एक हथियार कंपनी है, रायनमेटल. इसे ब्लैक-लिस्ट कर दिया गया है. लेकिन, इस कंपनी की देश की हथियार लॉबी के साथ साठगांठ है. यह उन्हें पैसा देती है. भारत के कई रिटायर सैन्य अधिकारी रायनमेटल कंपनी के कंसल्टेंट हैं, उसके एडवाइज़री पैनल में हैं. यह कंपनी भारत में ख़ूब पैसा ख़र्च करती है. सरकार ने जब एंटी-टैंक मिसाइल ख़रीदने का फ़ैसला किया, तो यह कंपनी सीधे तौर पर इस सौदे में हिस्सा नहीं ले सकती थी. मज़ेदार बात यह है कि जिस यूरोस्पाइक नामक कंपनी के ज़रिये इस मिसाइल की मार्केटिंग की जाती है, उसमें रायनमेटल कंपनी की 40 फ़ीसद हिस्सेदारी है. कहने का मतलब यह कि तकनीकी तौर पर इसे इज़राइल की राफेल कंपनी बनाती है, लेकिन इसे बेचने में रायनमेटल की हिस्सेदारी है. सीधे शब्दों में अगर समझा जाए, तो रायनमेटल ख़ुद इसकी सप्लाई न करके इज़राइल की राफेल के ज़रिये सप्लाई कराएगी. रायनमेटल एक हथियार कंपनी है, जिसका पैसा दुनिया की विभिन्न कंपनियों में लगा हुआ है. सरकार को पता लगाना चाहिए कि इज़राइल की राफेल कंपनी के साथ रायनमेटल का क्या रिश्ता है? बताया जाता है कि राफेल के 40 फ़ीसद शेयर रायनमेटल के पास हैं. अगर हमें रायनमेटल से ही मिसाइल ख़रीदनी है, तो यह सौदा बैन हटाकर सीधे उसी से किया जा सकता है. इससे पैसे की बचत हो सकती है.

> जर्मनी की एक हथियार कंपनी है, राइनमेटल. इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. लेकिन, इस कंपनी की देश की हथियार लॉबी के साथ साठगांठ है. यह उन्हें पैसा देती है. भारत के कई रिटायर सैन्य अधिकारी राइनमेटल कंपनी के कंसलटेंट हैं, उसके एडवाइज़री पैनल में हैं. यह कंपनी भारत में ख़ूब पैसा ख़र्च करती है. सरकार को यह बताना चाहिए ऐसी क्या बात हर रक्षा सौदा का रिश्ता इस कंपनी से होता है.

जब भी कोई हथियार या अन्य सामान ख़रीदा जाता है, तो सरकार पहले अपनी इच्छा जताती है और फिर अलग-अलग कंपनियों से प्रस्ताव आते हैं, जो प्रस्ताव सही होता है, उसे मंज़ूर कर लिया जाता है. यह सौदा सरकार मेक इन इंडिया के तहत करना चाहती है. रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि राफेल का रायनमेटल से क्या रिश्ता है? अगर राफेल से रायनमेटल का कोई रिश्ता है और उसी कंपनी से मिसाइल ख़रीदना तय है, तो उसके ब्लैक-लिस्ट होने का कोई मतलब नहीं है. सवाल यह है कि रक्षा मंत्रालय ने इस तथ्य की तरफ़ ध्यान क्यों नहीं दिया? किस लॉबी के दबाव में यह फ़ैसला लिया गया? इस फ़ैसले में कौन-कौन लोग शामिल हैं? क्या इस सौदे के लिए दलाली के रूप में पैसे दिए गए? इन सारे सवालों का जवाब सरकार के पास होना चाहिए और उसे देश की जनता को इसके बारे में बताना चाहिए. मज़ेदार बात यह है कि उक्त सारे फ़ैसले मोदी सरकार बनने के बाद लिए गए हैं. इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस सरकार ने यह फ़ैसला लिया था. यह सौदा मेक इन इंडिया के तहत होना है. मतलब यह कि इसे बनाने का काम भारत में किया जाएगा. तो अब सवाल यह है कि इसे कौन बनाएगा? क्या इज़राइल की कंपनी भारत में मिसाइल बनाने की यूनिट लगाएगी या किसी और निजी कंपनी को इसकी इजाज़त दी जाएगी?

ग़ौर करने वाली बात यह है कि भारत सरकार की अपनी एक कंपनी है, जहां पहले से मिसाइल बनाई जा रही है. इसका नाम है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड. वह पिछले कई सालों से मिसाइल बनाने का काम सफलता से कर रही है. अगर भारत में ही स्पाइक मिसाइल बननी है, तो उसे भारत डायनामिक्स के ज़रिये बनाया जा सकता है. उसके पास अनुभवी लोग हैं, टेक्नोलॉजी है, इंफ़्रास्ट्रक्चर है. भारत डायनामिक्स के पास मिसाइल बनाने का पूरा सेटअप है और सबसे बड़ी बात यह कि वह सरकारी है और यहां से निर्मित मिसाइल के किसी दूसरे देश या संगठन को बेचने का ख़तरा भी नहीं है. क्या बन रहा है और कितनी संख्या में बनाया जा रहा है, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में रहेगा. यह सस्ता भी पड़ेगा. लेकिन, हैरानी की बात यह है कि भारत डायनामिक्स के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय ने ग़ौर भी नहीं किया. उसकी जगह रक्षा मंत्रालय ने बाबा कल्याणी नामक एक छोटी सी कंपनी को हरी झंडी दे दी. इज़राइल की राफेल कंपनी अब बाबा कल्याणी के साथ ज्वाइंट वेंचर में भारत में स्पाइक मिसाइल बनाएगी. फिर वही सवाल कि इस कंपनी पर रक्षा मंत्रालय क्यों मेहरबान हुआ? इस कंपनी का भारत की हथियार लॉबी से क्या रिश्ता है? क्या मोदी सरकार हथियार के दलालों को हथियार निर्माता बनने में मदद कर रही है? यह सवाल इसलिए भी उठाना ज़रूरी है, क्योंकि इस कंपनी के पास मिसाइल बनाने का न तो अनुभव है, न उसके पास लोग हैं, न उसके पास टेक्नोलॉजी है और न भारत में उसका इंफ़्रास्ट्रक्चर है. मतलब यह कि बाबा कल्याणी को सरकार इंफ़्रास्ट्रक्चर तैयार करने में तरह-तरह की मदद करेगी. भारत में कंपनी स्थापित करने में जो ख़र्च आएगा, वह भी मिसाइल की क़ीमत में जुड़ेगा. कोई भी कंपनी अपना नुक़सान करके मेक इन इंडिया में क्यों इंवेस्ट करेगी? यही वजह है कि स्पाइक मिसाइल की क़ीमत दोगुनी हो गई और नई-नई शर्तें सामने आ गईं. अगर उसकी बातें मान ली गईं, तो शायद सरकार जवाब देने लायक़ नहीं बचेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 08 अंक 38
21 नवंबर- 27 नवंबर 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त क़ानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

ये देशभक्ति नहीं दलाली है

पृष्ठ 1 का शेष

देशभक्त कोई नहीं है.

इसी कंपनी की साउथ अफ्रीक़ा में एक और कंपनी है, जिसका नाम है रायनमेटल बेफे. ये कंपनी सिर्फ़ एम्यूनिशन बनाती है और ये कंपनी भी पाकिस्तान को एम्यूनिशन सप्लाई कर रही है. एक अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के ज़रिए ये एम्यूनिशन हमारे देश के कुछ उग्रवादी तत्वों को जाता है, जिनमें नक्सलाइट भी शामिल हैं और इसका रास्ता नेपाल से होकर है. सवाल सिर्फ़ ये दिमाग़ में है कि ऐसी कंपनी को क्यों परमिशन दी जा रही है? इसके लिए क्यों पॉलिसी बदली गई है, जो पाकिस्तान को वही हथियार सप्लाई कर रही है, जिसको हम हिंदुस्तान में बनाने वाले हैं या जो गोलियां पाकिस्तान को बेचती है, वो गोलियां हमें दे रही है, क्यों? क्या सिर्फ कमीशन या रिश्वत के लिए?

इस रायनमेटल का जो हिंदुस्तानी हेड है, वो एक रिटायर्ड फ़ौजी है, जिसका नाम कर्नल अनिल नंदा है, जिसने अनिल अंबानी के साथ एमओयू साइन किया है. ये कर्नल अनिल नंदा कई जगह पर ये कहते पाये गये कि रक्षा मंत्री मनोहर परिकर तो इनकी जेब में हैं और बॉस की यानि अनिल अंबानी की इनसे हर दूसरे दिन बात होती है. सात तारीख़ की सुबह ये ख़बर कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में फैल गई कि आज शाम को डीएसी की यानि डिफेंस एक्वीज़िशन कौंसिल की मीटिंग होगी और इसमें पॉलिसी चेंज हो जाएगी और पॉलिसी चेंज हो गई. ये सारी जानकारी हमें रायनमेटल के सूत्रों से मिली, क्योंकि वो ये चाहती है कि ये बात सबको पता चले कि वो कितनी ताक़तवर है. अब रक्षा मंत्री मनोहर परिकर के साथ रायनमेटल की क्या सेटिंग है या अनिल अंबानी की क्या सेटिंग है, ये किसी को नहीं पता. लेकिन इतना निश्चित है कि इसमें बहुत मोटा पैसा कहीं न कहीं, किसी न किसी बहुत बड़े आदमी को मिला है और अगर ऐसा नहीं होता तो ये पॉलिसी बदलने का खेल नहीं होता. जिस सूत्र ने हमें ख़बर दी उसका रायनमेटल से संबंध है और वो रक्षा सौदों में शामिल रहता है, लेकिन वो भी हिल गया कि ये देश बेचने की नंगी कोशिश हो रही है. उस व्यक्ति का ये कहना है कि ये तो देश बदलने की नंगी साज़िश है. ये डील कांग्रेस के ज़माने में होने वाली थी, लेकिन

कांग्रेस ने इसको मना कर दिया था. इसका मतलब एंटनी, मनोहर परिकर से ज्यादा साफ और क्लीन आदमी हैं. कांग्रेस ने इस कंपनी को ब्लैक-लिस्ट कर दिया था. अब दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हम वही ख़रीद रहे हैं, जो पाकिस्तान जा रहा है और हम वही बना रहे हैं, जो पाकिस्तान में सिंगापुर के थ्रू बिकने वाला है. ये सारी चीज़ें मस्तिष्क से और सारे तर्कों से परे हैं कि जिन्हें हम महान देशभक्त समझते हैं, वो ये महान देशभक्ति का या देशद्रोहिता का काम कैसे कर सकते हैं? ■

editor@chauthiduniya.com

शक के घेरे में है राफेल डील

ये घोटाले का लड़ाकू विमान है

म. क़ु.

क्या लड़ाकू विमान राफेल की ख़रीदारी में कोई बड़ा घोटाला हुआ है? क्या अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए राफेल डील किया गया? यह एक ऐसा सवाल है, जिसे देश का मीडिया जानता तो है, लेकिन खुल कर सवाल नहीं पूछ रहा है. क्या यह डील अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया? विमानों को कितने में ख़रीदा गया? क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा? यूपीए के दौरान जिन बिंदुओं पर करार हुआ, उसे मोदी सरकार ने क्यों ख़ारिज किया और घाटे का सौदा किया? जिस कंपनी से हम ये विमान ख़रीद रहे हैं, उस कंपनी की माली हालत क्या थी? क्या हमारे पास उससे बेहतर विमान खरीदने का विकल्प था? सवाल ये भी है कि डील फाइनल होने के बाद अंबानी की रिलायंस कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर क्यों बनाया? यह समझना ज़रूरी है कि क्या सुरक्षा के नाम पर या पाकिस्तान का डर दिखा कर मोदी सरकार आधुनिक हथियारों की ख़रीदारी में जल्दबाज़ी और हेराफेरी तो नहीं कर रही है? ऐसे कई सवाल हैं, जिनके जवाब जानने ज़रूरी हैं.

सरकार बदलने के साथ-साथ देश में घोटाला करने का तरीक़ा भी बदल जाता है. पहले ज़माने में मंत्री घूस लेते थे, तब उसे घोटाला कहा जाता था. बाद में घोटाले का तरीक़ा बदला और दस्तावेज़ में शब्दों की हेराफेरी कर घोटाला किया जाने लगा, फिर निजी कंपनियों के साथ मिल कर लूटने की प्रथा चली. मतलब यह कि घोटाले का प्रारूप अब पहले से बेहतर और साफ-सुथरा दिखने लगा है. अब घोटाले का जो प्रारूप है, उसका मतलब निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना हो गया है. यही वजह है कि राफेल डील अब शक के घेरे में है, वो इसलिए क्योंकि मोदी सरकार इस समझौते को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं दे रही है. यूपीए सरकार के दौरान राफेल लड़ाकू विमान का सौदा इसलिए पूरा नहीं हो सका क्योंकि सरकार को लगा कि इसकी क़ीमत ज्यादा है. क़ीमत पर तोलमोल हो ही रहा था कि सरकार बदल गई. अब जब डील हुआ तो यह मानना चाहिए कि पहले की तय क़ीमत से कम में हुआ होगा. लेकिन, हैरानी की बात ये है कि मोदी सरकार उसी विमान को चार साल बाद तय क़ीमत से दोगुने से ज्यादा क़ीमत देकर ख़रीद रही है. मामला सिर्फ़ क़ीमत का ही नहीं है, इसमें अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी को भी हिस्सेदार बना दिया गया है. इससे रिलायंस कंपनी को हज़ारों करोड़ का मुनाफा होने की उम्मीद है. जानकार बताते हैं कि राफेल डील का सारा फ़ैसला प्रधानमंत्री कार्यलय में हुआ. इस फ़ैसले को इतना गुप्त रखा गया था कि रक्षा मंत्री तक को इसकी भनक नहीं थी. अब सवाल ये है कि इतने गुप्त तरीक़े से घाटे का सौदा कर किसी निजी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना, अगर घोटाला नहीं है, तो क्या है?

राफेल घोटाले में गड़बड़ी हुई है, यह बात गोपनीय नहीं है. राफेल डील में हुए घपलेबाज़ी को लेकर सबसे पहले बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आवाज़ उठाई थी. वो बहुत पहले से ये कहते आ रहे थे कि राफेल सौदे में घपलेबाज़ी हो रही है. उन्होंने इस मामले को कोर्ट में घसीटने की भी धमकी दी थी. हाल में, स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव व प्रशांत भूषण ने भी राफेल समझौते पर सवाल उठाए थे. उनका ये आरोप था कि जिस विदेशी कंपनी को काली सूची में डालना चाहिए था, उसी के साथ केंद्र सरकार ने राफेल विमान का समझौता किया. स्वराज अभियान ने अपने आरोपों के पक्ष में दस्तावेज़ भी जारी किए और यह आरोप लगाया कि पूरे मामले की जानकारी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व सीबीआई को है, लेकिन केंद्र सरकार कोई क़दम नहीं उठा रही है. उन्होंने सरकार से विमान समझौते से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करने की मांग की, ताकि शुरुआती बातचीत में तय हुई क़ीमत से दोगुने से ज्यादा पर हुए समझौते की वजह पता चल सके.

लड़ाकू विमान राफेल की ख़रीददारी एक विशेष परिदृश्य में की गई, जब भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्ते ख़राब हो गए. बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी और पठानकोट व उरी जैसे हमलों ने देश में अति-राष्ट्रवाद का माहौल बना दिया था. इसी भारत-पाकिस्तान की तनातनी के बीच फ्रांस के साथ राफेल फाइटर प्लेन को लेकर पिछले चार साल से चली आ रही डील सरकार ने दोगुनी से भी ज्यादा क़ीमत देकर फाइनल कर दी. डील के फाइनल होते ही मीडिया और ख़ासकर टीवी चैनलों ने ये प्रसारित करना शुरू कर दिया कि ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान के एफ-16 का सटीक जवाब है. पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए राफेल से बेहतर कोई हथियार नहीं है. मीडिया ने लोगों के दिमाग में यह बिठा दिया कि राफेल का सौदा भारत के लिए हर मायने में मुनाफे का सौदा है. किसी ने इस बात का ज़िक्र तक नहीं किया कि ये सौदा कितने में हुआ, पहले कितने में हो रहा था? साथ ही ये तो किसी ने बताया तक नहीं कि इस डील के पीछे अंबानी की रिलायंस ग्रुप को बैठे-बिठाए हज़ारों करोड़ों का फ़ायदा होगा.

राफेल डील शक के घेरे में इसलिए है, क्योंकि चार साल पहले जब फ्रांस के साथ फाइटर प्लेन की ख़रीद के लिए समझौता हुआ था तब इसके तहत 126 विमानों को 10.2 बिलियन डॉलर में ख़रीदने का प्रावधान था. इस हिसाब से हर विमान की क़ीमत क़रीब 81 मिलियन डॉलर थी. चार साल पुरानी डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात शामिल थी. मोदी सरकार ने राफेल के लिए जो समझौता किया, उसमें सिर्फ़ 36 विमानों को 8.74 बिलियन डॉलर में ख़रीदा जाना है. मतलब यह कि एक विमान की क़ीमत 243 मिलियन डॉलर, वो भी बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के. अब सवाल तो पूछना लाज़िमी है कि चार साल में ऐसी क्या बात हो गई कि राफेल की क़ीमत दोगुनी से ज्यादा हो गई.

विमान की ख़रीद की प्रक्रिया यूपीए सरकार ने 2010 में शुरू की थी. 2012 से लेकर 2015 तक इसे लेकर बातचीत चलती रही. जब 126 विमानों की बात चल रही थी, तब ये सौदा हुआ था कि 18 विमान भारत ख़रीदेगा और 108 विमान भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स एसेम्बल करेगी, और तो और भारत को विमान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी भी मिलने वाली थी. अप्रैल 2015 में मोदी सरकार ने पेरिस में घोषणा की कि हम 126 विमानों के सौदे को रद्द कर रहे हैं और इसके बदले 36 विमान सीधे फ्रांस से ख़रीद रहे हैं और एक भी राफेल विमान बनाएंगे नहीं. ख़बर ये भी आई कि राफेल बनाने वाली कंपनी दस्सो को भारत सरकार 15 फ़ीसदी एडवांस रक़म देगी, तब उन विमानों पर काम शुरू होगा. यह समझना ज़रूरी है कि दस्सो कंपनी बंद होने के कगार पर थी. इस विमान को ख़रीदने वाले ख़रीदार नहीं मिल रहे थे क्योंकि इतनी क़ीमत पर दुनिया में इससे बेहतर लड़ाकू विमान उपलब्ध हैं. जानकारों का मानना है कि भारत ने इस सौदे के जरिए दस्सो कंपनी को खत्म होने से बचाया है. इस डील के होते ही इस कंपनी के शेयर आसमान में उड़ने लगे थे.

एक तरफ आतंकी हमले के परिदृश्य में सरकार ने अफरा-तफरी में डील को हरी झंडी दी, लेकिन हैरानी तो तब होती है कि जब इसके तुरंत बाद अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह तथा राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दस्सो एविएशन ज्वाइंट वेंचर लगाने की घोषणा करती है. अब ये कोई कहे कि राफेल सौदे के पहले किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी तो ये बात किसी को हज़म नहीं होगी. दोनों कंपनियों के बीच हुए ज्वाइंट वेंचर से ये साफ लगता है कि सरकार, दस्सो और रिलायंस ने मिल-जुल कर एक ऐसा मसौदा तैयार किया, जिससे बंद होने वाली कंपनी दस्सो बच भी जाए और रिलायंस को फ़ायदा भी हो जाए. यह इसलिए क्योंकि ज्वाइंट वेंचर का मक़सद ही यह था कि पूरे सौदे के 50 फीसदी रक़म को 'ऑफसेट' कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में रिलायंस अहम भूमिका निभाएगा. इस बात से शक और भी पुख्ता होता है क्योंकि भारत और फ्रांस ने 23 सितंबर को 36 राफेल लड़ाकू जेट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद संयुक्त उद्यम दस्सो रिलायंस एयरोस्पेस गठित किए जाने की घोषणा की है.

लड़ाकू विमान का यह सौदा 7.87 अरब यूरो (करीब 59,000 करोड़ रुपये) का है. 'ऑफसेट' कॉन्ट्रैक्ट के तहत संबंधित कंपनी को सौदे की राशि का एक निश्चित प्रतिशत लगाना पड़ता है. समझौते में 50 प्रतिशत ऑफसेट बाध्यता है, जो देश में अब तक का सबसे बड़ा 'ऑफसेट' अनुबंध है. 'ऑफसेट' समझौते का मुख्य बिंदु यह है कि इसका 74 प्रतिशत भारत से आयात किया जाएगा. इसका मतलब है कि करीब 22,000 करोड़ रुपये का सीधा कारोबार होगा. इसमें टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की भी बात है, जिस पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ चर्चा हो रही है. राफेल सौदे में अन्य कंपनियां भी हैं, जिनमें फ्रांस की एमबीडीए तथा थेल्स शामिल हैं. इनके अलावा सैफरॉन भी ऑफसेट बाध्यता का हिस्सा है. दोनों कंपनियों के संयुक्त बयान के अनुसार, इन ऑफसेट बाध्यताओं के लागू करने में संयुक्त उद्यम दस्सो रिलायंस एयरोस्पेस प्रमुख कंपनी होगी. इस ज्वाइंट वेंचर के लिए महाराष्ट्र के नागपुर में 100 एकड़ ज़मीन का एक प्लॉट भी दे दिया गया है. बताया जा रहा है कि यह नई कंपनी राफेल फाइटर जेट के लिए पूरी सप्लाई चेन तैयार करेगी.

सवाल ये है कि सरकार अनिल अंबानी की रिलायंस पर इतनी मेहरबान क्यों है? अनिल अंबानी की रक्षा क्षेत्र में क्या स्पेशिएलिटी है. इतने बड़े डील के पहले रिलायंस ने तोप और टैंक तो छोड़ दें, क्या कभी कोई रिवॉल्वर या पिस्टल भी बनाई है. रक्षा क्षेत्र में रिलायंस का अनुभव शून्य है, फिर भी मोदी सरकार ने भारत की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान को वायुसेना तक पहुंचाने और मेंटेन करने की ज़िम्मेदारी रिलायंस को क्यों दे दी? हैरानी की बात ये है कि रिलायंस समूह ने रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी का गठन जनवरी 2015 में किया था. क्या केंद्र सरकार को यह सोचना नहीं चाहिए था कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है? बॉर्डर पर तनाव है. चीन और पाकिस्तान से ख़तरा है और हम अपनी देश की सुरक्षा के लिए ऐसी कंपनियों से समझौता कर रहे हैं, जिसमें एक तो बंद होने के क़गार पर है और दूसरी, जिसने आजतक एक छुरी भी नहीं बनाई है. हैरानी की बात तो ये है कि ये सब प्रधानमंत्री कार्यालय में लिए गए फ़ैसले के ज़रिए हुआ और प्रधानमंत्री अपनी इस ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते. ■

सवाल ये है कि सरकार अनिल अंबानी की रिलायंस पर इतनी मेहरबान क्यों है? अनिल अंबानी की रक्षा क्षेत्र में क्या स्पेशिएलिटी है. इतने बड़े डील के पहले रिलायंस ने तोप और टैंक तो छोड़ दें, क्या कभी कोई रिवॉल्वर या पिस्टल भी बनाई है. रक्षा क्षेत्र में रिलायंस का अनुभव शून्य है, फिर भी मोदी सरकार ने भारत की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान को वायुसेना तक पहुंचाने और मेंटेन करने की ज़िम्मेदारी रिलायंस को क्यों दे दी? हैरानी की बात ये है कि रिलायंस समूह ने रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी का गठन जनवरी 2015 में किया था. क्या केंद्र सरकार को यह सोचना नहीं चाहिए था कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है?

feedback@chauthiduniya.com

समाजवादी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर लखनऊ में जुटे दिग्गज नेता

कलह का 'महा-हब्बंधन'

सभी फोटो : सुरेश वर्मा

मुलायम घराने का झगड़ा सुलटाने में ही लगे रहे सारे समाजवादी

अखिलेश के उत्तराधिकार पर सबने लगा दी मुहर, शिवपाल बिफरे

महागठबंधन को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला, और न निकलेगा

विकास यात्रा बनाम रजत जयंती में शिवपाल पर भारी पड़े अखिलेश

प्रभात रंजन दीन

मुलायम घराने की कलह पर सुलह के प्रयास की कोशिश का सार्वजनिक मंच साबित हुआ समाजवादी पार्टी का स्थापना दिवस. समारोह में न कहीं किसी राजनीतिक दल की रजत जयंती का सारगर्भित आयोजन दिखा, न कहीं कोई महागठबंधन की गंभीरता शक्ल लेती दिखी. समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह का मंच कलह के प्रपंच से ओतप्रोत दिखा. एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव खम ठोकते रहे, तो दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तलवार भांजते रहने की मुनादी की. मंच पर बैठे सारे पुराने दिग्गज समाजवादी नेता इस कलह के रजत-जयंतीकरण के चश्मदीद बने रहे और 'पैचअप' की नाकाम कोशिश करते रहे. पार्टी में अर्से से जारी कलह के बावजूद कुछ लोगों को उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में कुछ सार्थक होगा. महागठबंधन को लेकर कुछ ठोस निर्णय होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. सपा के समारोह में शरीक रहे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से लेकर जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव तक ने कहा कि महागठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई. सपा के रजत जयंती समारोह में शरीक होने जितने भी नेता आए थे, उनमें से अधिकांश लोग अखिलेश यादव की तरफ ही अपना रुझान दिखाते रहे और अखिलेश से हाथ मिला कर या हाथ खड़ा कर गौरवान्वित महसूस करते रहे. लालू यादव रहे हों या देवेगौड़ा, सबने मुलायम के बाद अखिलेश को ही अधिक तवज्जो दिया. शिवपाल उनका महत्व पाने में दूसरी पंक्ति में रहे.

पूरा प्रदेश और यह भी कह सकते हैं कि पूरा देश समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस को दो आयोजनों की कसौटी पर रख कर देख रहा था. एक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विकास यात्रा और दूसरा शिवपाल का रजत जयंती कार्यक्रम. दोनों कार्यक्रमों के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा खिंच गई थी. अखिलेश ने विकास यात्रा से शिवपाल और उनकी टीम को बाहर रखा तो रजत जयंती कार्यक्रम से शिवपाल ने अखिलेश और उनकी टीम को बाहर रखा. दोनों लोग समाजवादी पार्टी को अपनी-अपनी ताकत दिखा रहे थे. विकास यात्रा में जुटी भीड़ रजत जयंती समारोह में जुटी भीड़ से भिन्न थी, पर अधिक जुझारू और प्रभावकारी दिख रही थी. शिवपाल के आयोजन में जितने भी वरिष्ठ नेता बाहर-बाहर से आए थे, वे सब अखिलेश की उपेक्षा नहीं कर पाए. सारे लोग अखिलेश यादव को 'गुड-ह्यूमर' में रखते हुए संधि का प्रयास ऐसे कर रहे थे कि जैसे पार्टी के लिए अखिलेश ही अधिक जरूरी हों. राजनीतिक प्रेक्षकों का भी मानना है कि यदि शिवपाल का महत्व अधिक समझा जाता तो अखिलेश की राजनीतिक-उपेक्षा कर दी जाती. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हालांकि शिवपाल को इसकी उम्मीद थी, और ऐसा नहीं होने से उनकी हताशा सार्वजनिक तौर पर अभिव्यक्त भी हुई. इस खीझ में उनके मुंह से ऐसी भी बातें निकल आईं, जिसे राजनीतिक तौर पर अगंभीर वक्तव्य कहा जा सकता है. शिवपाल ने कहा, 'कुछ लोगों को पद भाग्य से मिल जाता है, कुछ लोगों को मेहनत से मिलता है और कुछ लोगों को विरासत में मिल जाता है. वहीं, कुछ लोगों को जिंदगी भर काम करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता. आज भी हम जानते हैं कि इस सरकार में बहुत लोग उपेक्षित हैं और कुछ लोगों ने जरा सी चापलूसी करके सत्ता का पूरा मजा ले लिया. जिन्होंने जान दी, उन्हें कुछ नहीं मिला.'

बहरहाल, हम जैसे-जैसे खबर के विस्तार में जाएंगे, समाजवादी पार्टी की जमीनी असलियत का खुद ब खुद पता चलता जाएगा. समाजवादी पार्टी के 25वें सालाना स्थापना दिवस समारोह के आयोजन से ही हम बात शुरू करते हैं. इस आयोजन में समारोह का हिस्सा सिर्फ इतना ही था कि इसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख चौधरी अजित सिंह, जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, इंडियन नेशनल लोक दल के नेता अभय चौटाला, वरिष्ठ कानूनविद् एवं राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी, वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय जैसे कई गण्यमान्य अतिथि मौजूद हुए, जिनका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने स्वागत किया. इनमें से कई नेताओं ने भाषण भी दिए, लेकिन किसी भी भाषण का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकला. हां, नेताओं ने इतना शिष्टाचार जरूर दिखाया कि मुलायम को सबने नेता माना. मुलायम की वरिष्ठता के नाते यह (शेष पृष्ठ 4 पर)

सुलह का प्रयास ही करते रह गए लालू

समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में अतिथि बन कर आए राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रिश्तेदार के रूप में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सुलह कराने की कोशिश ही करते रह गए. इसके लिए लालू ने रिश्तेदारी का हवाला दिया, फिर बिरादरी का भाव जताया, अखिलेश से शिवपाल का पैर छुवाया, अखिलेश के सिर पर शिवपाल का हाथ रखवाया, इसके बावजूद कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला. शिवपाल ने मंच से ही अखिलेश को खूब कोसा और अखिलेश ने उसका खुला प्रतिकार किया. यह सब लालू के सामने ही हुआ. इसके पहले लालू बोल चुके थे कि कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं है. लालू ने कहा कि काफी दिन से सुन रहा हूं कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में तनातनी चल रही है. मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा. शिवपाल बाबू तथा अखिलेश के संबंध तो बहुत मधुर हैं. सभी लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता दिलाएंगे. लालू ने 'पुनः होने वाले मुख्यमंत्री' कह कर अखिलेश को खुश करने की कोशिश भी की. फिर यह भी कहा कि हमारे समाज में कोई लड़ता नहीं है, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं. लालू ने अखिलेश से कहा, 'आप जो रथयात्रा लेकर निकले हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेकर उसे सफल बनाइये.' ■

सबने कहा मुलायम सर्वमान्य नेता

नेताजी ने सरकार को फिर खींचा

समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में भी मुलायम यह कहने से नहीं चूके कि सपा केवल सत्ता में आने और जमीनों पर कब्जा करने के लिए नहीं बनी है. मुलायम यह लगातार ही कहते रहे हैं कि अखिलेश सरकार के कई मंत्री और कई सपा नेता जमीनों पर अवैध कब्जा कराने के धंधे में लिप्त हैं. हालांकि मुलायम ने यह बात भी कही कि यूपी सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रभावशाली काम किया है. फिर यह भी बोलने लगे कि आज सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों के साथ हो रहा है. सपा सरकार में भी हो रहा है. मैं अखिलेश यादव से कहता हूं कि वह प्रशासन को आदेश देकर ऐसा होने से रोकें. उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शहीदों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. मुलायम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे संकल्प लें कि न अन्याय सहेंगे और न होने देंगे. मुलायम ने भूमि और अन्य सम्पतियों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति को लेकर भी कार्यकर्ताओं को फटकारा और कहा कि क्या सपा ने इसीलिए सरकार बनाई थी कि वहां कब्जा हो जाए, वहां कब्जा हो जाए. जनता निराश हो रही है, सपाइयों को जनता के बारे में सोचना होगा. जो नारा देते हैं, उसका

पालन करना चाहिए. पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने मुलायम के प्रति पूरी निष्ठा जताई और कहा कि साम्प्रदायिक शक्तियों से मुकाबले के लिए हमें मुलायम के नेतृत्व में लड़ाई लड़नी है. में 1997 में छूटी गाड़ी हमें दोबारा पकड़नी है. देवेगौड़ा ने यह भी कहा कि साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ने में सपा ही 'लैंडमार्क पार्टी' है. साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए सेकुलर लोगों को साथ आना ही होगा. देवेगौड़ा ने अपने दस माह के प्रधानमंत्रित्वकाल को पड़ोसियों के साथ देश का सर्वोत्तम समय बताया और कहा कि मेरे प्रधानमंत्री तथा मुलायम सिंह यादव के रक्षामंत्री के कार्यकाल के दौरान देश की सीमा बेहद सुरक्षित थी. इस दौरान कश्मीर में कोई घटना भी नहीं घटी और न वहां पर धारा 144 तक लगाने की जरूरत पड़ी. देवेगौड़ा ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत रहेगी तो देश में विपक्षी एकता भी मजबूत होगी. हम लोग मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने का काम करेंगे. राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख चौधरी अजित सिंह ने कहा कि भाजपा को सत्ता से दूर रखना है, तो मुलायम को क्षेत्रीय दलों को साथ लाकर लड़ना होगा. हमें 2019 के लिए तैयार रहना है. रालोद अध्यक्ष ने कहा कि मुलायम सिंह ने जितनी मेहनत सपा बनाने में की, उतनी ही मेहनत उन्होंने लोकदल को खड़ा करने में भी की थी. चौधरी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को अपना सर्वमान्य नेता माना और कहा कि देश और प्रदेश में अब गठबंधन बनाना बेहद जरूरी है. अब हमारी निगाह 2019 के लोकसभा चुनाव पर है, लेकिन हमको अभी भी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाने से रोकना होगा. उन्होंने कहा कि देश में सरकार बदली है, अब मुलायम सिंह यादव ही एक बार फिर से अगुवाई करें, जिससे कि हम लोग भाजपा को उत्तर प्रदेश में आने से वंचित कर दें. जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने मुलायम सिंह को इंगित करते हुए कहा कि इन पर इतिहास बदलने की जिम्मेदारी है. पूरे देश की नजर यूपी पर है. शरद ने कहा कि मुलायम में समाजवादियों और चौधरी चरणसिंहवादियों को एकजुट करने की काबिलियत है. इनेलो प्रमुख अभय चौटाला ने भी महागठबंधन को जरूरी बताया. राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बैठते-बैठते ही गठबंधन बनता है. मुलायम की जिम्मेदारी है कि सबको समझाएं. नेताजी सब जानते हैं, बढ़िया इलाज कर देंगे. ■

समाजवादी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर लखनऊ में जुटे दिग्गज नेता

कलह का 'महा-हठबंधन'

पृष्ठ 4 का शेष

शिष्टाचार का तकाजा था. महागठबंधन के बारे में बाहरी शोर-शराबा भले ही होता रहा, लेकिन उसकी कोई औपचारिकता समारोह में नहीं दिखी. संभावित महागठबंध के महत्वपूर्ण घटक और कारक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आमंत्रण के बावजूद गैरमौजूदगी और कांग्रेस को अनामंत्रण, दूसरी ही राजनीतिक दिशा का संकेत दे रहा है.

सपा के रजत जयंती समारोह का संयोजन शिवपाल ने संभाल रखा था, सो अतिथियों का स्वागत उन्हें ही करना था. समारोह में आए नेताओं का स्वागत करते हुए शिवपाल अनायास या सप्रयास फट पड़े और समाजवादी पार्टी का कलह-पुराण रजत जयंती समारोह को समेट ले गया. शिवपाल ने अपने स्वागत भाषण में अखिलेश यादव पर जमकर वार शुरू कर दिया. शिवपाल बोले, 'मुझे मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए. जरूरत पड़ने पर मैं अपना खून भी देने को तैयार हूं. मेरा कितना भी अपमान कर लो, उफ नहीं करूंगा. खून मांगोगे वह भी दे दूंगा.' मंच पर शिवपाल का यह वक्तव्य बिल्कुल ही अनपेक्षित था, लेकिन शिवपाल के समर्थक नेताओं का कहना है कि शिवपाल के लिए वही सबसे माकूल समय था. शिवपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मंच से स्वागत जरूर किया पर कहा कि पार्टी को यहां तक लाने में पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का पूरा जीवन खप गया. मैं भी उनके साथ लगा रहा. इस दौरान मुझे काफी कुछ झेलना भी पड़ा. मेरा जितना भी अपमान कर लेना, चाहे बर्खास्त कर लेना, लेकिन मुझे कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनना. शिवपाल ने कहा कि बतौर मंत्री हमने अखिलेश का बहुत सहयोग किया. अभी भी हमारी क्षमता काफी बड़ी है. आप जितना त्याग चाहोगे उतना देंगे, खून भी देंगे. मुख्यमंत्री अखिलेश ने बहुत काम किया. हमने भी उनके साथ मंत्री के तौर पर काफी काम किया. इससे पहले भी तीन महीने के काम को खत्म करने में लोगों ने कई वर्ष लगा दिए. हमने प्रदेश के 25 सहकारी बैंक बंद होने से बचाए. प्रदेश में 36 वर्ष से राजस्व संहिता लागू नहीं हो पा रही थी. प्रदेश के कई अधिकारियों ने बहुत रोड़े अटकाए, इसके बाद भी हमने लागू करा दिया. मैंने अपने विभागों में बहुत काम किया. सिंचाई और राजस्व विभाग में बहुत काम किया.

शिवपाल ने अखिलेश पर सीधे-सीधे निशाना साधा. कहा कि कुछ लोगों को पद भाग्य से मिल जाता है, कुछ लोगों को मेहनत से मिलता है और कुछ लोगों को विरासत में मिल जाता है. कुछ लोगों को जिंदगी भर काम करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता. समाजवादी सरकार में बहुत लोग उपेक्षित हैं और कुछ लोगों ने जरा सी चापलूसी करके सत्ता का पूरा मजा ले लिया, जिन्होंने जान दे दी, उन्हें कुछ नहीं मिला. शिवपाल यादव ने फिर यह कहते हुए बात संभाली कि वे नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ घुसपैठिए घुस गए हैं, उनसे सावधान रहना होगा. शिवपाल का स्पष्ट संकेत था कि अखिलेश के समर्थक पार्टी में घुसपैठिए हैं.

इस पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी ने यह पार्टी बहुत संघर्ष और खून-पसीना बहाकर बनाई है, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं. हमने काफी लंबा रास्ता तय किया है और अब हम समाजवादी पार्टी को नए स्तर पर ले जाएंगे, हमें साथ मिलकर यह काम करना होगा. किसी को परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, किसी को परीक्षा देनी है तो मैं तैयार हूं. अखिलेश ने डॉ. लोहिया का संदर्भ लेते हुए कहा, 'लोहिया जी ने कहा था कि लोग सुनेंगे जरूर लेकिन मेरे मरने के बाद. मैं इसे दूसरे शब्दों में कह रहा हूं कि लोग सुनेंगे जरूर लेकिन समाजवादी पार्टी के बिगड़ने के बाद.' संकेतों में अपना स्टैंड साफ करते हुए अखिलेश ने कहा कि आप लोग मुझे तलवार भेंट करते हो लेकिन चाहते हो कि तलवार नहीं चलाऊं. विचारधारा को बचाने के लिए तलवार चलाना भी जरूरी होता है. समारोह में गायत्री प्रजापति के हाथों मुलायम को गदा और शिवपाल और अखिलेश को तलवारें भेंट की गई थीं. भेंट में मिली तलवार को ही संकेत बना कर अखिलेश ने अपनी बात कह दी. अखिलेश ने कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति का नाम लेते हुए कहा, 'प्रजापति हमें भेंट में तलवार देते हो और कहते हो कि मैं तलवार न चलाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है.' अखिलेश ने संकेतों में बताया कि वे मुख्यमंत्री के अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे. क्योंकि शिवपाल भी अध्यक्ष के अधिकार का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं. अखिलेश ने भरोसा जताया कि समाजवादी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों में जीत हासिल होगी और सपा की ही सरकार बनेगी लेकिन हमें एकजुट होकर रहना होगा. ■

ये सब तो रहे, पर वो कहां रहे?

रजत जयंती समारोह में जुटी भीड़ मंच पर मौजूद नेताओं को देख कर आपस में ही यह सवाल दोहराती रही कि 'ये सब तो हैं, पर वो कहां हैं?' लोगों का सवाल अमर सिंह, प्रो. रामगोपाल यादव, आजम खान और अखिलेश के साथ हमेशा छाया की तरह रहने वाले राजेंद्र चौधरी की गैर-मौजूदगी को लेकर था. रजत जयंती मंच पर राज्यसभा सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा, रेवती रमण सिंह, कैबिनेट मंत्री बलराम यादव, विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय, सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरनमय नंदा, सांसद डिम्पल यादव, धर्मेन्द्र यादव, अबू आजमी समेत कई अन्य नेता मौजूद थे, लेकिन वे नहीं थे, जिन्हें लोग मंच पर देखना चाहते थे. लोगों को वह धक्का भी याद रहेगा जो शिवपाल ने अखिलेश समर्थक मंत्री को लगाया. मंच पर बोल रहे अखिलेश समर्थक जावेद आबदी को शिवपाल यादव ने धक्का देकर हटा दिया. शिवपाल का यह धक्का सुलह के प्रयासों को धक्का था.

सभी फोटो : सुरेश वर्मा

गठबंधन नहीं करेगी सपा : मुलायम

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने सपा के रजत जयंती समारोह के पांच दिन बाद ही 10 नवम्बर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में कोई गठबंधन नहीं करेगी. मुलायम ने कहा कि किसी भी दल के लिए सिर्फ सपा में विलय का रास्ता ही खुला है. सपा मुखिया ने यह ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नही करेगी. मुलायम बोले कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहले लिए गए फैसले पर पार्टी आज भी अडिग है. महागठबंधन से अलग होने के फैसले में सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव की अहम भूमिका रही थी. लिहाजा, यह माना जाने लगा है कि रामगोपाल की पार्टी में शीघ्र ही वापसी होगी, जिन्हें अभी हाल ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. उधर, अखिलेश के जो समर्थक शिवपाल द्वारा पार्टी से निकाले गए थे, उनकी भी वापसी की पहल हो रही है, क्योंकि शिवपाल की मंत्रिमंडल में वापसी भी तभी होगी, जब अखिलेश समर्थकों की पार्टी में वापसी होगी. ■

पर महागठबंधन की बात आगे नहीं बढ़ी

समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह के मंच से सभी नेताओं ने महागठबंधन की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन मंच के नीचे असली राजनीतिक जमीन पर महागठबंधन की बात आगे नहीं बढ़ी. पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (एस) के नेता एचडी देवगौड़ा से जब अलग से महागठबंधन की संभावना के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब के चुनावों के बाद ऐसे हालात शायद पैदा हों. फिलहाल हम यहां सपा के आमंत्रण पर रजत जयंती समारोह में हिस्सा लेने आए हैं. अभी गठबंधन पर कोई बात नहीं. जदयू नेता शरद यादव ने कहा कि सपा से पुराने रिश्ते हैं इसलिए वे समारोह में हिस्सा लेने आए हैं. उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है. इस बारे में मुलायम सिंह यादव बेहतर बता सकते हैं. शरद यादव ने कहा कि महागठबंधन के बारे में मुलायम से पूछें. महागठबंधन को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है. आगे क्या होगा देखते हैं. ■

पीके से मुलाक़ात के मायने और कांग्रेस का संशय

कांग्रेस के योजनाकार प्रशांत किशोर ने विकास यात्रा और रजत जयंती समारोह के दरम्यान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय मुलाकात नहीं हो पाई. जबकि प्रशांत किशोर की सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हो चुकी थी. प्रशांत किशोर और अखिलेश की मुलाकात के बाद गठबंधन और कांग्रेस की रणनीतियों को लेकर चर्चा ने रफ्तार पकड़ी. प्रशांत और अखिलेश की बातचीत करीब तीन घंटे चली. बातचीत का प्रसंग जाहिर तो नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर पता चला कि कांग्रेस के साथ किसी बृहत्तर समीकरण के निर्माण को लेकर दोनों में बातचीत हुई. हालांकि कांग्रेस इस मुलाकात को प्रशांत किशोर की निजी मुलाकात बताती है.

बहरहाल, विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन के प्रयास के रास्ते में कई अड़चनें हैं. सीटों के बंटवारे को लेकर आम सहमति कायम होना मुश्किल है. सपा कहती है कि बिहार चुनाव में जदयू और कांग्रेस ने मिलकर सीटों का बंटवारा कर लिया था और सपा को अंगूठा दिखा दिया था. इसी वजह से सपा महागठबंधन से अलग हो गई थी. लेकिन यूपी चुनाव में वह ऐसा नहीं होने देगी. सपा अपने सहयोगी दलों के लिए ज्यादा से ज्यादा 125 सीटें ही छोड़ेगी. कांग्रेस, रालोद, जदयू व साथ आने वाले अन्य दलों को भी इसी में बंटवारा करना होगा. कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस संभावित बंटवारे में कांग्रेस को कम सीटें मिल पाएंगी, जो कांग्रेस को मंजूर नहीं होगी. कांग्रेस का कहना है कि कम से कम 125 सीट मिलने पर ही वह महागठबंधन को लेकर बात कर सकती है. ■

अखिलेश ने पक्का करा लिया अपना चुनावी चेहरा

अखिलेश यादव ने यह पक्का कर लिया कि 2017 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे. समाजवादी पार्टी की रजत जयंती के पहले अखिलेश यादव की विकास यात्रा इस बात की सनद है. अखिलेश को सपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर और चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड द्वारा विधानमंडल दल का नेता चुने जाने की बात कह कर मुलायम ने जो पानी फेरने की कोशिश की थी, अखिलेश ने अपने विद्रोही तेवर से उसे अपने पक्ष में कर लिया. परिस्थितियां इस तरह बदलीं कि जिस विकास यात्रा को पार्टी से विद्रोह की संकेत यात्रा बताया जा रहा था, उस कार्यक्रम को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरी झंडी दिखा रहे थे. उनके बगल में सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव भी खड़े थे. पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में जिन अखिलेश-समर्थक नेताओं को निष्कासित कर दिया गया था, वे सारे नेता बाकायदा विकास-यात्रा मंच पर मौजूद रहे. मुलायम और शिवपाल समेत सारे नेता युवाओं का ही आह्वान करते दिखे. छात्रसभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सरधना से सपा प्रत्याशी रहे अतुल प्रधान विकास यात्रा में सक्रिय दिखे, जिन्हें शिवपाल यादव ने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही निष्कासित कर किसी दूसरे को प्रत्याशी घोषित कर दिया था. लोहिया वाहिनी के मुहम्मद एहबाद, युवजन सभा के ब्रजेश यादव, छात्रसभा के दिग्विजय और मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के प्रदीप तिवारी भी समारोह में मौजूद थे, जिन्हें शिवपाल ने निष्कासित कर दिया था. शिवपाल ने यह फरमान भी जारी किया था कि निष्कासित लोग पार्टी के किसी भी समारोह में शरीक न हों. लेकिन अखिलेश की विकास रथयात्रा उन सारे निष्कासित नेताओं के कंधे पर चली जो अखिलेश-समर्थक होने के कारण शिवपाल के शिकार बने.

अखिलेश ने अपने संबोधन में कहा भी कि यह विकास-यात्रा ही हमारी सरकार बनवाएगी. अखिलेश ने कहा कि यूपी को विकास के पथ पर ले जाने और जनता की भलाई के लिए पिछले साढ़े चार साल में सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं. इन्हीं की बदौलत प्रदेश में एक बार फिर सपा की सरकार बनेगी. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे, लखनऊ मेट्रो, समाजवादी पेंशन, लैपटॉप वितरण सहित कई योजनाएं चलाई गईं, जिसका सीधा लाभ जनता को मिला है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा की सरकार ने शहरों को गांवों से जोड़ने का काम किया है. जिला मुख्यालयों को भी गांवों से जोड़ने का काम किया गया है. जनता को बिजली मुहैया कराई जा रही है. समाजवादी पेंशन योजना के तहत 55 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं. अखिलेश की विकास यात्रा को उनकी पत्नी सांसद डिम्पल यादव ने भी संबोधित किया. काबीना मंत्री व अखिलेश समर्थक राजेंद्र चौधरी का दावा है कि अखिलेश यादव की 'विजय की ओर विकास रथ यात्रा' ने अपने प्रथम चरण में ही राजनीतिक इतिहास का नया अध्याय रच दिया. चौधरी ने अतिरंजना में विकास यात्रा की तुलना नेहरू और जेपी की रैलियों से कर दी. अखिलेश की विकास रथयात्रा में रथ के अलावा सैकड़ों गाड़ियों का काफिला और पैदल चल रहे कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भीड़ का साथ मिला, जिसने सड़क पर अखिलेश की शक्ति दिखाई लेकिन आम नागरिकों के दैनंदिन कार्य में दिक्कतें पेश की. लब्बोलुबाव यही रहा कि विकास यात्रा हो या रजत जयंती समारोह, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पटल पर अखिलेश ही उभर कर सामने आए. सपा के रजत जयंती समारोह में देश के तमाम बड़े नेताओं ने अखिलेश का हाथ उठाकर उन्हें भविष्य में पार्टी का चेहरा और आने वाले चुनाव में सीएम पद का उम्मीदवार बताने की सनद दी. लालू यादव से लेकर एचडी देवेगौड़ा, शरद यादव, चौधरी अजित सिंह व अन्य बड़े नेताओं ने अखिलेश के उत्तराधिकार को मान्यता दे दी. रजत जयंती समारोह में मौजूद सपा कार्यकर्ता भी अखिलेश के समर्थन में नारे लगा कर अपना पक्ष स्पष्ट कर रहे थे.■

हड़ताल जारी रखना हुर्रियत की मजबूरी

हुर्रियत नेताओं के हड़ताल जारी रखने के फैसले पर घाटी के आम लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की. कुछ लोग यह कह रहे हैं कि हड़ताल की वजह से गरीब लोगों का का जीना मुश्किल हो गया है. वहीं, हड़ताल जारी रखने के पक्ष में बोलने वाले लोगों की दलील है कि पिछले चार महीने के दौरान लोगों ने जो अनगिनत कुर्बानियां दी हैं, उन्हें नजरअंदाज कर हड़ताल खत्म करने का मतलब अवाम को पराजय का एहसास दिलाना है. गौरतलब है कि आठ जुलाई को दक्षिण कश्मीर के एक गांव में सुरक्षा बलों के हाथों नौजवान मिलिटेंट कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में एक बड़ा विरोध-प्रदर्शन फूट पड़ा था.

हारून रेशी

श्रीनगर के हैदरपुरा क्षेत्र स्थित सैयद अली शाह गिलानी के निवास के बाहर आठ नवंबर को भीड़ जमा थी. इस भीड़ में ऐसे दर्जनों नौजवान भी शामिल थे, जिन्होंने अपने चेहरों को रुमाल से ढंक रखा था. वो अपने जोशीले नारों से गिलानी हाउस के अंदर जारी बैठक में भाग ले रहे लोगों को खबरदार कर रहे थे कि वे चार महीने से जारी विरोध-प्रदर्शन को खत्म करने का फैसला कर 'शहीदों के खून के साथ गद्दारी' न करें.

दरअसल गिलानी के घर जारी उस बैठक में ये फैसला लेना था कि चार महीने से जारी विरोध-प्रदर्शन को जारी रखा जाए या इसे वापस ले लिया जाए. गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में कई सामाजिक, धार्मिक और अलगाववादी संगठनों के नेताओं के अलावा व्यापार संगठनों, ट्रांसपोर्टरों के प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया गया था. छह घंटे तक चली इस बैठक में शामिल सभी लोगों ने विरोध-प्रदर्शन के संदर्भ में अपनी-अपनी राय व्यक्त की. उनमें से कुछ ने लगातार चल रहे हड़ताल की वजह से लोगों को हो रही हानि का जिक्र किया और घाटी में आम जिंदगी को सामान्य बनाने की सलाह दी. उनमें से कुछ ने बिना कुछ हासिल किये हड़ताल खत्म नहीं करने की सलाह दी. लेकिन बैठक की समाप्ति पर तीनों नेताओं गिलानी, मीरवाइज और यासीन मलिक ने मीडिया से बात करते हुए विरोध-प्रदर्शन जारी रखने का फैसला सुनाया. उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में उन्हें यह अधिकार दिया गया था कि वो मीटिंग में विरोध-प्रदर्शन जारी रखने या खत्म करने का फैसला कर सकें.

हुर्रियत नेताओं के हड़ताल जारी रखने के फैसले पर घाटी के आम लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की. कुछ लोग यह कह रहे हैं कि हड़ताल की वजह से गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. वहीं, हड़ताल जारी रखने के पक्ष में बोलने वाले लोगों की दलील है कि पिछले चार महीने के दौरान लोगों ने जो अनगिनत कुर्बानियां दी हैं, उन्हें नजरअंदाज कर हड़ताल खत्म करने का मतलब अवाम को पराजय का एहसास दिलाना है.

गौरतलब है कि आठ जुलाई को दक्षिण कश्मीर के एक गांव में सुरक्षा बलों के हाथों नौजवान मिलिटेंट कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में एक बड़ा विरोध-प्रदर्शन फूट पड़ा था. बुरहान के जनाजे में लाखों लोगों को शिरकत करते देखकर सरकार ने घाटी के सभी दस जिलों में कर्फ्यू लगा दिया था. इसके बाद हालात इतने खराब हो गये कि सरकार लगातार 52 दिनों तक कर्फ्यू में छूट नहीं दे पाई. यहां तक कि बकरीद के मौके पर भी कश्मीर घाटी के ज्यादातर इलाकों में कर्फ्यू जारी रहा और लोगों को ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं मिली. इस प्रदर्शन में अब तक सौ लोग मारे जा चुके हैं और पंद्रह हजार लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें बहुतों की आंखों की रोशनी चली गयी. तकरीबन दस हजार नौजवानों को सुरक्षाबलों ने पथराव करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है. इस पृष्ठभूमि में हुर्रियत नेताओं का हड़ताल जारी रखने का फैसला एक असाधारण फैसला है. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, घाटी की विस्फोटक स्थिति के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता ने हुर्रियत नेताओं को हड़ताल जारी रखने के लिए विवश कर दिया है.

उर्दू दैनिक चट्टान के संपादक ताहिर मोहीउद्दीन ने चौथी दुनिया से बातचीत में कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर की गंभीर स्थिति को लेकर पूरी तौर से लापरवाही बरती है. केंद्र सरकार चाहती तो घाटी की स्थिति बेहतर बनाने के लिए या सुधारने के लिए कदम उठा सकती थी, बातचीत का सिलसिला शुरू कर सकती थी. ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार पिछले चार महीने से यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि कश्मीर के लोग चाहे जितना प्रदर्शन कर लें, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी. केंद्र के इस रवैये ने वहां के लोगों और नेताओं की नाराजगी को सख्त गुस्से में बदल दिया है. यही वजह है कि आठ नवंबर की मीटिंग में प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया गया है.

वहीं, दूसरे विश्लेषक हड़ताल जारी रखने के फैसले को उचित नहीं मान रहे हैं. वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक साहिल मक़बूल कहते हैं कि पिछले चार महीने के दौरान यहां जो कुछ भी हुआ, उसके नतीजे में कश्मीर समस्या विश्वस्तर पर उजागर हुई है. लेकिन हड़ताल को जारी रखना जनता के हित में नहीं है. लगातार हड़ताल की वजह से सामान्य जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है. मरीजों को मुनासिब इलाज नहीं मिल पा रहा है. व्यापारी और ट्रांसपोटरों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

चार महीने से जारी इस विरोध-प्रदर्शन में सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है. प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि वह इस बात पर गौर कर रही है कि वर्तमान स्थिति में बच्चों के शैक्षिक भविष्य को कैसे बचाया जाए? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष जीएन वार्न ने इस संदर्भ में चौथी दुनिया से बात करते हुआ कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि बच्चों के भविष्य को कैसे बचाया जाए? हम कुछ दिनों में एक रणनीति तैयार कर उसे लोगों के सामने रखेंगे. उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना सामूहिक खुदकुशी करने जैसा है. हमारे बच्चे हमारे भविष्य हैं और उनकी शिक्षा से ही ये भविष्य रौशन हो सकता है. गौरतलब है कि प्राइवेट स्कूलों ने हाल में बच्चों और उनके माता-पिता को छूट देने के लिए कई उपाय करने का एलान किया है. इसमें पिछले चार माह की स्कूल फीस में भारी छूट देना भी शामिल है. इसके अलावा एसोसिएशन ने यह भी कहा कि जो छात्र विरोध-प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुए हैं, उनकी फीस माफ कर दी जाएगी. जो स्कूल जलाए जा चुके हैं, उनके छात्रों को अलग-अलग स्कूलों में मुफ्त दाखिला दिया जाएगा ताकि स्कूली इमारतों के अनुपलब्धता की वजह से उनकी शिक्षा प्रभावित न हो. बहरहाल यदि विरोध-प्रदर्शन जारी रहते हैं तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सारे उपाय बेमतलब हो जाएंगे.

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लगातार हड़ताल की रणनीति आम लोगों के हित में कतई नहीं हो सकती है. ऐसा लगता है कि हुर्रियत नेतृत्व के पास हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिसके सहारे वे अपने विरोध को जारी रख सकें. विश्लेषकों का कहना है कि हुर्रियत नेतृत्व को ये आशंका है कि अगर वो ऐसे वक्त में हड़ताल खत्म कराएंगे, जबकि हजारों नौजवान जेलों में बंद हैं और हजारों नौजवानों के जख्म ताजा हैं, तो शायद उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

एनजीओ पर तालाबंदी से निभेगी लोकतंत्र की मर्यादा!

चंदन राय

हाल में गृह मंत्रालय ने 11,319 गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मान्यता रद्द कर दी है. साथ ही 25 एनजीओ को राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में लिप्त बताते हुए उनकी मान्यता रद्द कर दी गई. ये एनजीओ अभी तक विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत थे. इनमें करीब 50 अनाथालय, सैकड़ों स्कूल और समाज के वंचित बच्चों के लिए काम करने वाले एनजीओ भी शामिल हैं. जाहिर है मान्यता रद्द होने के बाद अब वे विदेशों से धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे. खबरों के मुताबिक ये संगठन सरकार द्वारा तय की गई तारीख तक अपने पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाए थे. पिछले साल भी करीब 10 हजार एनजीओ के एफसीआरए के तहत पंजीकरण रद्द हुए थे. आरोप था कि उन्होंने बीते तीन वर्षों के अपने सालाना रिटर्न दाखिल नहीं किए थे.

एक स्वस्थ लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी जैसी संस्थाएं फलती-फूलती हैं. जब लोकतंत्र पर अधिनायकवादी ताकतें हावी होने लगती हैं, तो सबसे पहले सिविल सोसाइटी की आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है. समाजशास्त्रियों का मानना है कि एक जीवंत लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी जनमत-निर्माण के जरिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, या यूं कहें कि सरकार की लोककल्याण विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता को एकजुट करते हैं. ऐसे में जाहिर है कि शायद ही कोई लोकतांत्रिक सरकार इस स्थिति को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो. तब शुरू होता है इन संस्थाओं पर सरकारी दमन का खेल. मीडिया पर बैन लगाया जाता है, एनजीओ को फेरा के घेरे में फंसाया जाता है, उन्हें राष्ट्रद्रोही करार दिया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर हमले तेज किए जाते हैं, बुद्धिजीवियों को देश छोड़ने की सलाह दी जाती है. दरअसल, सरकार की नीतियों के खिलाफ जनमत तैयार करने का मकसद सीधे सरकार पर हमला माना जाता है और फिर उसे देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम के ताने-बाने से जोड़ दिया जाता है.

देश में कुछ ऐसी ही स्थितियों के बीच लोकतंत्र अपना सफर तय कर रहा है. पहले, सत्ता पक्ष अपनी नीतियों की खूबियों-खामियों के बारे में जनता की राय जानने के लिए इन संस्थाओं को तवज्जो देते थे. ये संस्थाएं जनता और सरकार की नीतियों के बीच समन्वय का काम करती थीं. अपनी नीतियों की जनता द्वारा की गई आलोचना से घबराने के बजाय सरकार उन्हें बदलने के लिए तैयार रहती थी. लेकिन जब से कुछ संस्थागत पूर्वघोषित एजेंडों के जरिए सरकार की नीतियों का निर्धारण होने लगा है, तब से सिविल सोसाइटी और सरकार के बीच मतभेद बढ़ने लगे हैं. लिहाजा, सिविल सोसाइटी की आलोचना को सरकार व्यक्तिगत आलोचना के रूप में लेने लगी है और उसी के आधार पर तय होता है कि कौन सी संस्था सरकार के पक्ष में है और कौन विरोध में. अब जनपक्षधरता के मुद्दे गौण हो गए हैं और सरकारी नीतियों के बखान में ही सिविल सोसाइटी का एक अवसरवादी धड़ा अपना हित देखने लगा है.

वहीं, 25 राष्ट्रद्रोही घोषित एनजीओ में कई ऐसे एनजीओ भी शामिल होंगे, जिन्होंने सरकार की हां-में-हां मिलाने से इंकार कर दिया होगा. हालांकि इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि एनजीओ की आड़ में कुछ ऐसे धंधेबाज भी हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों व प्राइवेट कंपनियों की कारगुजारियों को जनता में वैधता प्रदान कराने के लिए कार्य करते हैं. कुछ ऐसे एनजीओ भी हैं, जो मानवता के नाम पर विदेशों से चंदा उगाही करते हैं और गुप्त तरीके से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं. यह बात भी जगजाहिर है कि एनजीओ अपने गुप्त धन का हिसाब-किताब शेयर करने से परहेज करते हैं. एक अनुमान के मुताबिक करीब 90 प्रतिशत एनजीओ टैक्स नहीं भरते हैं.

गुजरात की सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ एक एनजीओ चलाती हैं सबरंग ट्रस्ट. इसके संचालक हैं तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद. तीस्ता के एनजीओ पर एफसीआरए के 6 नियमों के उल्लंघन का आरोप है. एक आरोप यह भी है कि विदेशों से आने वाले धन का इस्तेमाल व्यक्तिगत खर्च के लिए हो रहा था. बताते चलें कि सबरंग ट्रस्ट का पंजीकरण सामाजिक और शिक्षा के लिए हुआ है. गौरतलब है कि तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात में हुए दंगों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ काफी मुखर रही हैं. एक अनुमान के मुताबिक, मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से 13,700 से अधिक भारतीय और विदेशी एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए हैं.

जाकिर नाईक के एनजीओ को लेनी होगी पूर्व अनुमति: विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाईक के आईआरएफ एजुकेशनल ट्रस्ट को सरकार ने पूर्व अनुमति श्रेणी में डाल दिया है. अब केंद्र की अनुमति के बिना यह ट्रस्ट विदेशी धन हासिल नहीं कर पाएगा. गृह मंत्रालय ने जांच में यह पाया था कि आईआरएफ एजुकेशनल ट्रस्ट ने फेरा के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. इसके बाद गृह मंत्रालय ने आईआरएफ एजुकेशनल ट्रस्ट को किसी भी तरह का विदेशी योगदान लेने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया. हालांकि जांच में यह भी पता चला कि नाईक एनजीओ के लिए आए धन का इस्तेमाल युवाओं को कथित रूप से कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने में कर रहे थे. सरकार जाकिर नाईक द्वारा शुरू की गई एक अन्य एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का एफसीआरए पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया में है. इस संबंध में संस्था को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है. सूत्रों ने दावा किया कि नाईक ने आईआरएफ के विदेश कोष को पीस टीवी को आपत्तिजनक कार्यक्रम बनाने के लिए स्थानांतरित कर दिया.

25 एनजीओ को बताया राष्ट्रद्रोही : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फेरा के तहत 25 एनजीओ का दोबारा रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने यह कदम उनके देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से उठाया है. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि वैसे एनजीओ जो विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त हैं या देशहित से जुड़े काम नहीं करते हैं, उन्हें विदेश से फंड हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.

कोई एनजीओ राष्ट्रद्रोही है या नहीं, यह तय कौन करेगा? अगर यह सरकार करती है, तो फिर ऐसे एनजीओ पर कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता, जो सरकार परस्त न हों. ग्रीनपीस फाउंडेशन जैसे एनजीओ, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करते हैं, उन पर भी बैन इसलिए लगा दिया गया क्योंकि वे सरकार द्वारा संचालित कई ऐसे प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे, जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं था. सरकार पर्यावरण को लेकर जितनी चिंतित नजर नहीं आती, उससे ज्यादा चिंतित बड़े बांधों व परमाणु भट्टियों के निर्माण को लेकर होती है, जो कभी भी जनता के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं. कई एनजीओ के रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद भारत में विदेशों से फंड हासिल करने वाले एनजीओ की संख्या अब 33,138 से घटकर 20,000 रह गई है.■

feedback@chauthiduniya.com

स्थापना के 16 साल बाद भी झारखंड में सपना रह गया 24 घंटे बिजली

वादा आपूर्ति फुल बिजली आपूर्ति ज़ीरो

प्रशान्त शरण

बिजली की समस्या से जूझ रहे झारखंड के लोगों को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह आश्वासन दिया था कि अब निर्बाध बिजली की आपूर्ति होगी. सत्ता संभालते ही उन्होंने 'जीरो पावर कट' की बात कही थी. उन्होंने सख्त लहजे में कहा था कि जहां बिजली कटेगी, वहां के अभियंता पर कार्रवाई होगी. पर झारखंड में जीरो पावर कट लोगों का सपना ही रह गया. राज्य में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था लचर है. सुधार के लाख दावों के बावजूद बिजली का कटना जारी है. बीते सालों की तुलना में स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है. राज्य का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है, जहां 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती हो, आलम यह है कि राजधानी रांची में भी 20 से 22 घंटे ही बिजली मिल पाती है, वहीं राज्य के अन्य इलाकों में 15 से 17 घंटे ही बिजली मिल पाती है. पर झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम के अधिकारियों का दावा है कि राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की क्षमता है, पर ट्रांसफॉर्मर व तार की स्थिति ऐसी नहीं कि बिजली की फुल लोड आपूर्ति की जा सके. आंधी बारिश में भी तार टूट जाते हैं, लोकल फॉल्ट आ जाता है. इस कारण समय-समय पर बिजली कटती रहती है.

पर अगर सच्चाई पर गौर करें तो हकीकत कुछ और बयां करती है, दरअसल झारखंड में बिजली का उत्पादन ही नहीं है कि फुल लोड बिजली की आपूर्ति की जा सके. राज्य को 2100 मेगावाट बिजली की जरूरत है, पर वर्तमान में 1800 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध हो पा रही है. जरूरत के अनुपात में आधे बिजली का ही उत्पादन राज्य में अभी हो पा रहा है. तेनुघाट विद्युत निगम पर ही राज्य सरकार निर्भर है, यहां से 380 मेगावाट बिजली का उत्पादन ही हो पाता है, पर इसपर लोड बढ़ने से इसका एक यूनिट हमेशा ठप हो जाता है. इस कारण पूरे राज्य के किसी भी भाग में जीरो पावर कट बिजली नहीं मिल पाती है.

दरअसल राज्य गठन के 16 साल बाद भी इस ओर कोई ठोस रोड मैप बनाकर काम नहीं किया गया है. रांची सहित अन्य कुछ शहरों में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम शुरू हुआ, पर यह अभी तक नहीं हो सका. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 17 हजार गांवों का विद्युतीकरण किया गया है, पर वहां बिजली कैसे मिले, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई. अब भी अगर गांवों में एक बार ट्रांसफॉर्मर खराब हुआ तो उसे बदलने में सालों लग जाते हैं, साथ ही राज्य का आधा भाग अति उग्रवाद प्रभावित रहने के कारण इन क्षेत्रों में तार चोरी की घटनाएं भी अधिक होती है. इस कारण अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र अभी भी अंधेरे में ही डूबे रहते हैं. संथाल परगना का पूरा क्षेत्र अभी बिहार एवं कहलगांव के एनटीपीसी पावर प्लांट पर ही निर्भर है. यहां से बिजली खरीद कर सरकार इन क्षेत्रों में बिजली देती है. राज्य में बिजली का उत्पादन नहीं होने के कारण सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं.

राज्य में अभी 26 लाख से अधिक बिजली के उपभोक्ता हैं, 2010 तक मात्र 14 लाख ही बिजली उपभोक्ता थे. उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण अब प्रतिमाह 917 करोड़ यूनिट की खपत है. उपभोक्ताओं की पूर्ति के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम 370 करोड़ रुपये की बिजली प्रतिमाह खरीदता है, बिजली बोर्ड का अपना स्थापना व्यय भी 35 करोड़ रुपये है. बोर्ड बिजली चोरी रोकने एवं भ्रष्टाचार पर काबू पाने में पूरी तरह विफल रहा है. इस कारण बिजली बोर्ड का घाटा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है. मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा बार-बार चेतावनी दिये जाने के बाद भी इसका कोई असर नहीं हो पा रहा है.

वैसे मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सभी गांवों में विद्युतीकरण कराने का लक्ष्य रखा है. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया है कि दिसम्बर 2017 तक सभी घरों में विद्युत कनेक्शन मुहैया करा दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि हर हाल में इस लक्ष्य को पूरा किया जाए, अन्यथा काम में कोताही बरतने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री के इस आदेश का असर भी देखने को मिल रहा है. बिजली निगम ने इसके लिए एक रोड मैप भी तैयार किया है. मुख्यमंत्री राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने को लेकर भी गंभीर है. अभी तेनुघाट विद्युत निगम पर ही राज्य सरकार निर्भर है, पर अब इसकी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इसका जीर्णोद्धार करने का फैसला लिया गया है, जबकि पतरातू थर्मल पावर को एनटीपीसी को दे दिया गया है. इस बिजली संयंत्र से एवं इसका विस्तार कर एनटीपीसी 4 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा. इस पर काम शुरू किया जा रहा है. कुछ निजी कंपनियों को भी विद्युत संयंत्र लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है. इसमें अडानी समूह मुख्य है. अडानी गोड्डा में 2200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा. अभी दो निजी कंपनियां इनलैण्ड पावर एवं आधुनिक पावर द्वारा बिजली उत्पादन किया जा रहा है. इन दोनों पावर प्लांट से 180 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. बिजली निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक आर.के. श्रीवास्तव ने दावा किया है कि सभी घरों में जल्द ही बिजली कनेक्शन पहुंचा दिया जाएगा. साथ ही फुल लोड बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है. बिजली कंपनी में हो रहे घाटे को दूर करने के लिए ठोस नीति बनायी गई है. पर अब देखना है कि झारखंड के लोगों का यह सपना पूरा होता है या जीरो पावर कट मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही बनकर रह जाएगा.■

अगले साल हर घर में बिजली - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने को लेकर तल्ख रवैया अपनाया है, अपने मातहत अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि 2017 के अंत तक हर घर में बिजली पहुंच जाना चाहिए. इसके लिए राशि भी स्वीकृत कर दी गई है. वैसे अभी तक पूर्ण विद्युतीकरण नहीं होने पर पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराने से नहीं थकते हैं. उनका मानना है कि अगर आत्मविश्वास और दृढ़संकल्प के साथ कोई योजना शुरू की जाए, तो उसे हर हाल में पूरा किया जा सकता है. जिनके घर अभी तक अंधेरा था, उस घर में जल्द ही बिजली पहुंचेगी. राज्य में जितनी बिजली की आवश्यकता है, उतना उत्पादन नहीं है, तो ऐसे में इतने घरों में डीवीसी एवं राज्य के विद्युत उत्पादन संयंत्र से उत्पादन बढ़ाकर इस कमी को दूर किया जाएगा. दिसम्बर, 2017 तक राज्य के सभी पंचायतों के घरों में बिजली कनेक्शन मुहैया करा दिया जाएगा, यह सरकार का वादा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यह प्रबल इच्छा है कि हर घर में रोशनी हो. मुख्यमंत्री का मानना है कि नई ऊर्जा नीति के तहत निजी औद्योगिक घरानों द्वारा राज्य में बिजली उत्पादन संयंत्र लगाए जा रहे हैं, तेनुघाट विद्युत निगम को भी एनटीपीसी को दिया गया है, इस कारण राज्य में कुछ दिनों के बाद बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी. साथ ही बिजली का खपत कम करने के लिए एलईडी बल्बों का वितरण किया जा रहा है. इन बल्बों की कीमत तो कम रखी ही गई है, साथ ही गरीब एवं बीपीएल परिवारों के लिए किस्तों में दस रुपये प्रतिमाह की राशि पर मुहैया कराया जा रहा है, वैकल्पिक ऊर्जा के प्रति भी मुख्यमंत्री रघुवर दास कुछ ज्यादा ही गंभीर हैं, सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है. खूंटी व्यवहार न्यायालय में सोलर लाइट के द्वारा ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपी मॉडल पर सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने की कार्रवाई की जा रही है. कई औद्योगिक घरानों ने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं. कुछ ही दिनों में झारखंड बिजली के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा.■

90 प्रतिशत आदिवासी घरों में बिजली नहीं - मरांडी

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी ने कहा रघुवर दास केवल भोली-भाली जनता को बड़े-बड़े वादे कर लुभाने की कोशिश में है, पर आगामी चुनाव में जनता ने भाजपा को सबक सिखाने का मन बना लिया है. अभी भी 90 प्रतिशत आदिवासी गांवों में बिजली का तार नहीं पहुंचा है, पहले तार और बिजली तो पहुंचाए, तब हर-हर घर में बिजली और जीरो पावर कट का दावा करे. मुख्यमंत्री लुभावनी घोषणा करना बंद करें और धरातल पर काम करना सीखें. उन्होंने कहा कि यह सरकार घोर आदिवासी और मूलवासी विरोधी हैं, इसलिए जनहित का कोई काम नहीं किया जा रहा है. भाजपा अपने पार्टी के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए भोले-भाले लोगों का जमीन अधिग्रहण करने में लगी हुई है. जब आदिवासी के पास जमीन और मकान ही नहीं रहेगा तो बिजली किसको देंगे. मुख्यमंत्री पहले विस्थापन और लोगों का पलायन तो रोके. उन्होंने कहा कि राज्य की 68 प्रतिशत आबादी अभी भी अंधेरे में रहने को विवश है. मुख्यमंत्री राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर काबू पाएं. बिजली बोर्ड तो भ्रष्टाचार का अड्डा है. वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत भी ढूंढना चाहिए, तभी राज्य के सभी घरों में बिजली पहुंचायी जा सकती है. ■

68 फ़ीसदी ग्रामीण घरों तक नहीं पहुंची बिजली

राज्य के लगभग 68 प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली नहीं है. सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल गांवों के लोग तो बिजली का मतलब भी नहीं समझते. स्वयं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में यह स्वीकार किया था कि झारखंड राज्य में ग्रामीण घरों की कुल संख्या 46 लाख 85 हजार 965 है, जिसमें 15 लाख 14 हजार 50 घरों में ही बिजली पहुंचाई जा सकी है. झारखंड के ग्रामीण इलाकों में केंद्र सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं राज्य योजना के अंतर्गत राज्य के गांवों का विद्युतीकरण किया गया है. सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र एवं आदिम जनजाति बहुल क्षेत्रों में विद्युतीकरण का काम राज्य गठन के 16 वर्षों के बाद भी शुरू नहीं हो सका है, हालांकि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इन क्षेत्रों में बिजली बहाल करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है. झारखंड बिजली वितरण निगम का दावा है कि गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है. पोल, तार एवं ट्रांसफॉर्मर लगाने का काम एक साथ शुरू किया गया है, पर कुछ परेशानियां भी निगम के सामने आ रही हैं. राज्य के 409 गांवों के आसपास कोई ट्रांसमिशन लाइन नहीं है. वैसे राज्य सरकार इन गांवों में सोलर लाइट के द्वारा विद्युतीकरण करने की योजना पर काम कर रही है. ■

घोषणाओं की सरकार - हेमंत सोरेन

विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह सरकार घोषणाओं की सरकार है. बड़ी-बड़ी घोषणाएं एवं वादे किए जाते हैं, पर अभी तक एक भी घोषणा जमीन पर नहीं उतर सकी है. रघुवर सरकार ने एक लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, पर किसी एक को भी नौकरी नहीं दी गई. इतना ही नहीं, जिन लोगों को पूर्ववर्ती सरकारों ने संविदा के आधार पर रखा, उन्हें भी निकालने की साजिश यह सरकार कर रही है. सभी लोगों को बिजली देने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि रघुवर दास जब मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए तो उन्होंने राजधानी एवं राज्य के लोगों से जीरो पावर कट की बातें कही थी, पर सुदूर गांव की बात तो छोड़ दें, राजधानीवासियों को भी गर्मियों में आठ-आठ घंटे तक बिजली नहीं मिल पाई थी. मुख्यमंत्री किस आधार पर जीरो पावर कट की बात कह रहे हैं, यह समझ से परे है. राज्य में बिजली की जरूरत जितनी है, उतना उत्पादन है नहीं. बिजली कंपनियों का बकाया राशि होने के कारण कंपनियां राज्य को बिजली देने में आना-कानी कर रही है, इसमें डीवीसी प्रमुख है. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने राज्य को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के कई प्रयास किए, कुछ निजी कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया, आए भी, पर भाजपा सरकार द्वारा उन्हें दी गई कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द कर दिया, जिससे वे पीछे हट गए. वहीं भाजपा अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए हर कदम उठा रही है. अडानी की शर्तों पर ही यह सरकार पावर प्लांट लगवा रही है. इस पावर प्लांट से राज्य सरकार को कुछ लाभ नहीं होने वाला है. वैकल्पिक ऊर्जा की चर्चा करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि इसके प्रति राज्य सरकार गंभीर नहीं है. केवल सोलर संयंत्र के नाम पर लूट-खसोट मचा हुआ है. ■

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

अपने विरोधियों को राष्ट्रद्रोही कहना बंद कीजिए

इस हफ्ते की दूसरी बड़ी ख़बर 1000 और 500 के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण (मुद्रा का चलन बन्द करना) थी. विमुद्रीकरण कोई नई चीज़ नहीं है. इससे पहले भी भारत में 1954 में और 1978 में विमुद्रीकरण किया गया था. लेकिन काला धन कम करने में उनका प्रभाव बहुत ही मामूली था. इस बार ये कहा जा रहा है कि ये विमुद्रीकरण जाली नोटों और आतंकवाद पर हमला है. ये संभव है. ऐसा हो सकता है कि इस संबंध में सरकार के पास कुछ जानकारी हो. यदि जाली नोटों के प्रचलन में कमी होती है, तो ये कभी भी अच्छी बात है, और यदि विमुद्रीकरण से आतंकवाद बुरी तरह से प्रभावित होता है, तो ये भी ठीक है. लेकिन, विमुद्रीकरण के शुरुआती अवधी के दौरान यानी तीन-चार दिन या एक हफ्ता या दिसम्बर तक कम और माध्यम आय वर्ग के लोगों को अधिक परेशानी में डाल दिया गया है.

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं. दरअसल यह हिलेरी की उतनी बड़ी पराजय नहीं है, जितनी बड़ी उन मूल्यों की पराजय है, जिनपर अमेरिका खड़ा है. एक ऐसे व्यक्ति को देख कर जो खुलेआम उन मूल्यों का उपहास उड़ा रहा है और जनता उसका समर्थन कर रही है, टॉमस जेफर्सन ज़रूर अपनी कब्र में करवट बदल रहे होंगे. मैं यहां ट्रम्प की व्यक्तिगत टिप्पणियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो न सिर्फ अमरीकी मूल्यों के विरुद्ध हैं बल्कि सभ्यता-विरोधी भी हैं. बहरहाल, हर राष्ट्र को उसके अनुरूप ही नेता मिलता है, और अगर जनता स्वयं ही ऐसी हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? जहां तक भारत का सवाल है, तो इसका कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत-अमेरिका संबंध व्यक्तित्व आधारित नहीं हैं बल्कि ज़मीनी हकीकत पर आधारित हैं. ये हकीकत वर्तमान में भारत के पक्ष में हैं, क्योंकि दुनिया मंदी के शिकंजे में है. भारत एक ऐसी जगह है जहां वे निवेश के करना चाहते हैं और जहां अपना मैन्युफैक्चरिंग आधार भी बनाना चाहते हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि दुनिया में मचे आर्थिक उथल-पुथल में भारत एक शांत जगह है. दूसरी बात ये है कि भारत के मैन पॉवर को भी कोई नज़रंदाज़ नहीं कर सकता. हालांकि ट्रम्प वीज़ा कम करने की बात करते हैं, क्योंकि वो स्थानीय लोगों को अधिक नौकरी देना चाहते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त को वो नज़रंदाज़ नहीं कर सकते.

इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर 1000 और 500 के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण (मुद्रा का चलन बन्द करना) थी. विमुद्रीकरण कोई नई चीज़ नहीं है. इससे पहले भी भारत में 1954 में और 1978 में विमुद्रीकरण किया गया था. लेकिन काला धन कम करने में उनका प्रभाव बहुत ही मामूली था. इस बार ये कहा जा रहा है कि ये विमुद्रीकरण जाली नोटों और आतंकवाद पर हमला है. ये संभव है. ऐसा हो सकता है कि इस संबंध में सरकार के पास कुछ जानकारी हो. यदि जाली नोटों के प्रचलन में कमी होती है, तो ये कभी भी अच्छी बात है, और यदि विमुद्रीकरण से आतंकवाद बुरी तरह से प्रभावित होता है, तो ये भी ठीक है. लेकिन, विमुद्रीकरण के शुरुआती अवधी के दौरान यानी तीन-चार दिन या एक हफ्ता या दिसम्बर तक कम और माध्यम आय वर्ग के लोगों को अधिक परेशानी में डाल दिया गया है. अभी मैंने सुना है कि किसान चिंतित हैं कि उनकी फसल से हासिल उपज बिक नहीं पायेगी, क्योंकि बिचौलिए, जो उसे खरीदते थे वो कैश में खरीदते थे. यहां लेनदेन बैंक के जरिया नहीं होता था. लिहाज़ा यह उन्हें मुश्किल में डालेगा. बहरहाल, मैं आश्वस्त हूं कि भारत का खोजी दिमाग इन परेशानियों से निकलने का कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगा. लेकिन आगे जाकर विमुद्रीकरण का कोई फायदा होगा या नहीं, मैं समझता हूं कि सरकार इस संबंध में एक साल या छह महीने के बाद ही कोई आंकड़ा जारी कर सकती है. यदि विमुद्रीकरण से जाली नोटों के प्रचलन पर लगाम लग जाता है, तो यह एक उपलब्धी मानी जाएगी.

चिंता का जो दूसरा विषय है, वो है एक आम माहौल. एनडीटीवी को एक दिन के लिए ऑफ-एयर करने की बात चल रही थी. इसका कारण यह बताया गया कि उसने पठानकोट एनकाउंटर को दिखाया. गौरतलब है कि एनडीटीवी ने उस एनकाउंटर का सीधा प्रसारण नहीं किया था, जो प्रतिबंधित है. आप एनडीटीवी पर मीट्रिक जुर्माना

लगा सकते हैं, लेकिन एक दिन के लिए ऑफ-एयर करना नुक़सानदेह है. कुछ क़ानून होंगे, जिनके तहत आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वैसी चीज़ों के लिए जो राष्ट्रविरोधी हों. अब राष्ट्रविरोधी की परिभाषा क्या है? पिछले दिनों हमने राजद्रोह के कई मुकदमे देखे, जो सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा में कहीं नहीं टिक सकते. राजद्रोह का मामला तब बनता है, जब आप स्टेट के ख़िलाफ़ सशस्त्र विद्रोह करने या करवाने की कोशिश कर रहे हों. केवल बयान दे देने से राजद्रोह का मामला नहीं बनता, जैसे जेएनयू के छात्रों या कश्मीर के नेताओं ने किया, या फिर जैसा प्रशांत भूषण ने कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए. ये मामले राजद्रोह के मामले नहीं हैं. ये विचार हैं, भले ही ये कितने भी असुविधाजनक क्यों न हों. दरअसल अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब होता है ऐसी बात बोलने की आज़ादी, जिसे सरकार पसंद नहीं करती हो. ऐसी बातें बोलना जो सरकार सुनना चाहती है, उसके लिए किसी आज़ादी की आवश्यकता ही नहीं है. राष्ट्रद्रोह शब्द का इस्तेमाल आज जिस तरह हो रहा है, वैसे इसका इतेमाल नहीं होना चाहिए. मिसाल के तौर पर, बरखा दत्त या राजदीप सरदेसाई या कोई अन्य रिपोर्टर या एनडीटीवी जैसा कोई चैनल चूंकि बीजेपी-आरएसएस-सरकार के विचारों से सहमत नहीं हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्र विरोधी बता दिया जाए. आप इंटरनेट पर देख लीजिए उन्हें राष्ट्रविरोधी बताने वाले बहुत सारे लोग मिल जायेंगे. ऐसा फासीवाद में होता है, जहां राज्य और शासक एक होते हैं. लोकतंत्र में शासक बदलता रहता है, जबकि राज्य स्थिर रहता है. अगर कोई वाक़ई राज्य के ख़िलाफ़ कुछ करता है, तो वह राष्ट्र विरोधी गतिविधि है. आप उनके ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई कीजिए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कीजिये. ताकि अदालत उसकी समीक्षा कर सके और यदि उनको अदालत द्वारा दोषी करार दिया जाता है तो फिर उसे राष्ट्रविरोधी माना जाए. लेकिन ऐसे वातावरण, जिसमें सबको राष्ट्रविरोधी कहा जाए, से फासीवाद की बू आती है.

वर्ष 2014 में जब नरेन्द्र मोदी सत्ता में आये थे, तो हम में से बहुत सारे लोग चिंतित थे कि आरएसएस की फासीवादी सोच लोगों पर थोपी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हम प्रधानमंत्री के शुक्रगुज़ार हैं, जब उन्होंने कहा था कि देश के लिए एक मात्र पवित्र ग्रन्थ संविधान है. वे अक्सर अपनी बातों में गांधीजी का नाम लेते हैं. सरदार पटेल उनके सबसे नए प्रतिक हैं. लेकिन विडम्बना यह है कि सरदार पटेल अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा ही एक कांग्रेसी रहे. आरएसएस और बीजेपी से उनका कोई लेना-देना नहीं था. इस अफ़वाह में कि पटेल और नेहरू के बीच काफी मतभेद थे, कोई खास दम नहीं दिखता. गांधीजी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, जबकि पटेल का देहांत दिसंबर 1950 में हुआ था. गांधीजी के बाद नेहरू और पटेल ने पूरे तीन साल तक एक साथ काम किया. पटेल को अपने कैबिनेट से हटाने से नेहरू को कौन रोक सकता था और पटेल को कांग्रेस पार्टी तोड़ने से कौन रोक सकता था. लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनके मतभेद वस्तुगत थे, मुनासिब थे और देशहित में थे. उनकी सियासत देशहित में थी. इस बात की सराहना करने के बजाये, एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है जैसे नेहरू अवांछनीय थे और पटेल वांछनीय थे. मैं इस मामले का सकारात्मक पहलू भी देख रहा हूं. यदि इससे पटेल का राजनीतिक कद बढ़ता है, तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है. हालांकि वे (भाजपा) पटेल का नाम एक मकसद के लिए इस्तेमाल कर हैं, लेकिन अगर आप पटेल की नीतियों का अक्षरशः अनुकरण करना चाहते हैं, तो लोकतंत्र सुरक्षित है, हिन्दू-मुस्लिम रिश्ता सुरक्षित है, देश के मुसलमान सुरक्षित हैं, और कुछ भी गलत नहीं होगा.

लेकिन इस तरह का वातावरण जिसमे हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहना, जो आपसे असहमत है, तो मैं उसे एक मज़ाक़ कहूंगा, हालांकि ये अब बड़ा रूप ले रहा है. वे केजरीवाल के ख़िलाफ़ हैं, वे राहुल गांधी के ख़िलाफ़ हैं और विडम्बना यह है कि राहुल गांधी और केजरीवाल का क़द इनके हमलों की वजह से बढ़ रहा है. राहुल गांधी पर हालिया हमला- जब वे राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल में किसी से मिलना चाहते थे, तो पुलिस ने उनके साथ जो किया, उसने उन्हें नेता बना दिया. मैं समझता हूं कि भाजपा के समर्थक कांग्रेस पार्टी की एक तरह से सेवा कर रहे हैं. हालांकि राहुल गांधी बहुत ही सौम्य तरीक़े से काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार जब वे कठोर ढंग से सड़क पर उतर जाएं, तो वे एक नेता बन जायेंगे और इसका श्रेय इस सरकार की कार्यप्रणाली को जायेगा. राष्ट्रद्रोही शब्द का प्रयोग उन्हें रोक देना चाहिए. गृह राज्य मंत्री को या तो किसी अन्य मंत्रालय में भेज देना चाहिए या उन्हें ये सिखाना चाहिए कि जो बातें वे कह रहे हैं, वो संविधानसम्मत नहीं हैं, सही नहीं हैं. हमें आशा करनी चाहिए की चीज़ें बेहतर होंगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

कश्मीर का भविष्य

आवरण कथा (07 नवंबर-13 नवंबर) कश्मीर दर्द से चीख रहा है, में संतोष भारतीय ने जिस तरह से कश्मीर की हकीकत का आंखो देखा हाल बयां किया है, उसे पढ़कर सच में कश्मीरियों के बारे में चिंता हो रही है. यह पूरा देश जानता है कि कश्मीर जल रहा है, वहां के लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं. केंद्र सरकार को चाहिए कि स्थानीय सरकार और वहां के सर्वमान्य नेताओं के साथ मिलकर इस समस्या का स्थायी निदान निकाले. लेकिन यहां सरकार समस्या का राग अलापने में ही लगी है. इस लेख में लिखी गई ये पंक्तियां कश्मीर समस्या से भारत के संबंध को बखूबी बयां करती हैं- 'कश्मीर एक दर्द के धुएं के बीच घिरा हुआ इलाका है. सरकार कोई भी फैसला करे तो यह मानकर करे कि वहां के 60 लाख लोगों को या तो वह अपने पक्ष में करना चाहती है या 60 लाख लोगों को अपने विरोध में करना चाहती है.' दर्द से चीख रहा कश्मीर आज उस मुहाने पर खड़ा है, जहां भारत सरकार का एक निर्णय उसके भविष्य का निर्धारण करेगा. इसलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़कर इस मामले में पहल करें.

- इशरत नूर, *दिल्ली*

नीति से निकले रास्ता

जब तोप मुकाबिल हो में संतोष भारतीय की संपादकीय कश्मीर के छह हिस्से को मिलाकर बातचीत हो (07 नवंबर-13 नवंबर) पढ़ा. सबसे पहले तो संपादक महोदय को धन्यवाद हमें इस सच्चाई से अवगत कराने के लिए. आपने एकदम सही लिखा है कि पूरे भारत में कश्मीर को लेकर एक समान्य राय बनी हुई है कि कश्मीर में धारा 370 खत्म होनी चाहिए और 370 खत्म होते ही कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा बन जाएगा. असल में आज का समाज सुने-सुनाए तथ्यों और बनी-बनाई विचारधारा के सहारे आगे बढ़ने ही होड़ में है. कोई भी हकीकत जानने की जहमत नहीं उठाना चाहता. कोई यह नहीं जानना चाहता कि कश्मीरी आखिर क्यों और किन हालातों में पाकिस्तान का झंडा दिखाने को मजबूर होते हैं. बस उसे बिना कुछ जाने समझे पाकिस्तान परस्ती से जोड़ दिया जाता है. जिस क्षेत्र के भौगोलिक इतिहास में आजादी

हो, वहां के लोग कैसे और क्यों बंदिशों को बर्दाश्त करें. आखिर हमारी सरकार को समस्या क्या है वाजपेयी जी के कदमों पर आगे बढ़कर कश्मीर समस्या का हल ढूंढने में. एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बूटों और बंदूकों से दबा कर किसी पर अपनी राय थोपी नहीं जा सकती.

- मनोज कुमार, *रीवा, मध्यप्रदेश*

सपा का अंतर्कलह

पा के सामने ही डूब रही सपा (07 नवंबर-13 नवंबर) शीर्षक से लिखा गया प्रभात रंजन दीन का लेख पढ़ने के बाद यह तो स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी की फजीहत के लिए समाजवादी ही जिम्मेदार हैं. कहा जाता है कि बड़े-बुजुर्ग परिवार की रीढ़ होते हैं लेकिन इस सियासी परिवार में वह रीढ़ ही अपनों की कमर तोड़ने पर आमादा है. अखिलेश यादव को राजनीति में लाकर यूपी में सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का काम मुलायम सिंह यादव दे ही किया था. लेकिन अब जबकि चुनाव सर पर हैं और अखिलेश को अपनों के समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसी समय उनके अपने ही उनकी फजीहत कराने पर तुले हैं. जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते हुए भी जनता के सामने भरी सभा में अपने पिता के डांट को आदर भाव से स्वीकार करते हैं, उनका पर कतरना सपा सुप्रीमो को शोभा नहीं देता. भले ही मुलायम सिंह यादव पारंपरिक राजनीति के सहारे चुनाव में जाना चाहते हों, लेकिन उन्हें अखिलेश यादव की विकासवादी छवी को भी साथ लेकर चलना चाहिए.

- रोहित सिंह, *बनारस, उत्तर प्रदेश*

कबड्डी का सुखद भविष्य

भारत बना कबड्डी का सरताज (07 नवंबर-13 नवंबर) शीर्षक से लिखे सैयद मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट पढ़ी. यह खुशी की बात है कि भारत में अब क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों को भी प्राथमिकता दी जा रही है. कबड्डी जो कभी भारत के गांवों और गलियों का खेल माना जाता था, उसमें विश्व चैंपियन बनना अपने आप में गौरव की बात है. विश्व स्तर पर कबड्डी में परचम लहराना इसके स्वर्णिम भविष्य के लिए भी संकेत है. गांवों और शहरों में कबड्डी खेलते बच्चे अब इस खेल में भी अपना करियर तलाश सकते हैं. कबड्डी की बढ़ती लोकप्रियता और स्वीकार्यता ने ऐसे बच्चों के सपनों की बुनियाद भी मजबूत कर दी है. यह भी कम खुशी और आत्मगौरव की बात नहीं है कि कबड्डी वर्ल्ड कप में भारत ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को ज्यादा अंकों के अंतर से हराया.

- दीपक पांडेय, *बुलंदशहर*

प्रगतिशील शायर सज्जाद ज़हीर

'आजादी केवल एक देश का अपना झंडा, अपना राष्ट्र गान या अपना सिक्का दे देने का नाम ही नहीं है, बल्कि आजादी का मतलब तो बराबरी और वह समानता है, जिसमें सबका बराबर का हक हो.' ये विचार भारत के प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कर उसमें अहम भूमिका निभाने वाले साहस और संवेदना के प्रगतिशील शायर और कलमकार सज्जाद ज़हीर के हैं, जिन्होंने उस जमाने में 'अंगारे' जैसी किताब लिखी, जब ऐसा करना संभव नहीं था. उन्होंने अंग्रेजी राज के विरोध में ही 'लंदन की एक रात' जैसी रचना का सृजन किया, जो उनके एक और साहस का ही प्रतीक है. आजादी के लिए लिखना और लिखने की पूरी आजादी होना यही उनकी जिंदगी का मकसद था. वे शायरी को इंसानियत का सबसे खूबसूरत तत्व मानते थे. उनकी अधिकांश कहानियां इस्लाम धर्म की रूढ़िवादिता पर सीधा प्रहार करती हैं. सोचने-समझने, परखने-जांचने की आजादी और रूढ़िवादिता की बेड़ियों में जकड़ी परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाने के कारण ही उनकी रचना अंगारे पर प्रतिबंध लगाया गया. फिर भी उन्होंने तत्कालीन शासकों से माफी नहीं मांगी और मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाते हुए ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के भारतीय सेल का गठन कर पेरिस में होने वाले फासिस्टवाद के खिलाफ लेखकों के अंतराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया.

- शिव कुमार फैजाबादी,
नियावां, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

देश भीषण महंगाई के दौर में प्रवेश कर गया है

पुणे के एक एनजीओ की सलाह पर, जो एक इंजीनियर चलाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे नोटों को रद्द करने का फ़ैसला लिया है. हो सकता है यह ख़बर सही हो. इसके लिए मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने कई कहावतों को एक साथ चरितार्थ कर दिया. मोहम्मद बिन तुग़लक़ का नाम इतिहास में बड़े आदर से लिया जाता है. इसी तरह कालिदास का नाम भी इतिहास में बड़े आदर से लिया जाता है. मेरी प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम इतिहास में उस आदर से न लिया जाए, पर कुछ सवाल तो हैं, जो आज प्रधानमंत्री सहित सारी सरकार से पूछना आवश्यक हो गया है. क्या देश के सारे अर्थशास्त्री, देश या विश्व की अर्थव्यवस्था को जानने वाले लोग बुद्धिहीन हो गए, जो पुणे के एक एनजीओ, जिसका दावा है कि उसका रिश्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है और देश की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए जिसने अपने एक इंजीनियर साथी की मदद से देश की अर्थव्यवस्था के संपूर्ण परिदृश्य को बदल दिया.

क्या वो अर्थशास्त्री, जो वित्त मंत्रालय से जुड़े हैं या देश के महान वकील, जो सुप्रीम कोर्ट में अक्सर मुक़दमे जीतते हैं, अरुण जेटली जो आज देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, वित्त मंत्रालय का भार संभालते हैं, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ये नहीं बताया कि देश का 90 प्रतिशत ब्लैकमनी शेयर्स, सोने के बिजनेस और रीयल इस्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व है. सिर्फ 10 प्रतिशत ब्लैकमनी कैश के रूप में देश में चल रहा है, जिसमें ज्यादातर छोटे और मध्यम दर्जे के व्यापारी और वे सारे लोग, जो इस देश में अपनी सुरक्षा के लिए पचास हज़ार, एक लाख रुपए रखते हैं, ताकि वक्त ज़रूरत में उनके काम आ सके. मोदी जी के इस क़दम से वो सारे लोग बच गए, जो ब्लैकमनी का संचालन करते हैं, जो समानांतर अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं. अर्थव्यवस्था का संचालन करने वालों का पैसा बेनामी कंपनियों के एकाउंट्स में, बैंक में सुरक्षित है और जो उससे बड़े हैं, उनका सारा पैसा स्विट्जरलैंड, पनामा, मॉरीशस जैसे टैक्स हैवेन और कालेधन के लिए स्वर्ग माने जाने वाले अफ़्रीक़ी देशों तथा उन जगहों पर, जो सारी दुनिया के ब्लैकमनीज़ संचालित करने वालों के लिए स्वर्ग है, वहां सुरक्षित है. देश की ब्लैकमनी या समानांतर अर्थव्यवस्था का संचालन करने वाले डॉलर और पाउंड में डील करते हैं, भारतीय मुद्रा में डील नहीं करते हैं. प्रश्न उठता है कि मोदी जी ने इन लोगों के ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला? क्या ये पैसा जो देश के कालेधन के 90 प्रतिशत को कंट्रोल करता है, सिर्फ़ इसलिए हाथ नहीं डाला कि उसकी मदद आनेवाले चुनाव में कोई एक राजनीतिक दल लेना चाहता है? क्या वित्त मंत्रालय ने इसका अंदाज़ा लगाया है कि दो हज़ार रुपए का नोट, जो अब भारतीय बाज़ार में सरकार द्वारा लाया गया है, वह अगले पांच से दस साल में किस तरह की अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा?

क्या हम एक नए इन्फ्लेशन के दौर में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का सीधा रिश्ता प्रिंटिंग ऑफ हायर इनोमिनेशन नोट्स और इन्फ्लेशन के बीच है. और हाइपर इन्फ्लेशन बल्कि कहें कि देश इन्फ्लेशन तथा हाइपर इन्फ्लेशन के दौर में प्रवेश कर गया है. अब तक हम जिस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से बचते आए हैं, क्या इस फ़ैसले ने हमें उस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौर का अगुआ तो नहीं बना दिया है. एक जानकारी के मुताबिक, अमेरिका हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़ने की बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था. उसके लिए आश्चर्य का विषय था कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का शिकार होने से बच गई और उसने इस बार हमें समझदारी के साथ तोड़ दिया. अब तक बचने का एक ही बड़ा कारण था कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को यानी हिन्दुस्तान के लोग अपनी अर्थव्यवस्था को अपनी ताक़त के साथ, अपने सेल्फ गवर्नेंस के तरीक़े से संभाल लेते थे. इस फ़ैसले से हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा निर्देशित अर्थव्यवस्था के एक पिछलग्गू अगुआ बन गए हैं. हमारी अर्थव्यवस्था भी अब विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का एक घटिया अंग बन गई है. हम उस मंदी के सबसे सशक्त हिस्सेदार बनकर उभरने वाले हैं. अगर हमने तत्काल करेक्टिव मेजर्स नहीं उठाए या भूल को सुधारने की कोशिश नहीं की, तो हम अमेरिका या यूरोप जैसी आर्थिक मंदी का शिकार होने से बच नहीं पाएंगे.

भारत में काग़ज़ के नोटों पर आधारित जिस ब्लैकमनी की बात या टेरेरिस्ट को जानेवाले पैसे की बात भारत सरकार या प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सिर्फ़ हम इतना समझना चाहते हैं कि अगर ये पैसा बंद हो जाएगा, तो क्या टेरेरिस्टों के पास बाहर से पैसा आना रुक जाएगा? क्या हमारे यहां हमले रुक जाएंगे? क्या हमारे यहां हथियार बंटने बंद हो जाएंगे? मैं जानता हूं कि इसका उत्तर सरकार हमें नहीं देगी, लेकिन मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि आतंकवादियों की अर्थव्यवस्था हमारे नोटों से नहीं चलती. आप जो भी नोट लाएंगे, उनसे हथियार नहीं ख़रीदे जाते. हथियार आते हैं, आप उन हथियारों को रोक नहीं पाते, क्योंकि उन हथियारों को लाने में हमारी ही व्यवस्था के कुछ लोग शामिल हैं. सरकार को जिन चीजों पर चाक-चौबंद होना चाहिए, वहां

क्या हम एक नए इन्फ्लेशन के दौर में प्रवेश कर गए हैं क्योंकि इन्फ्लेशन का सीधा रिश्ता प्रिंटिंग ऑफ हायर इनोमिनेशन नोट्स और इन्फ्लेशन के बीच है. और हाइपर इन्फ्लेशन बल्कि कहें कि देश इन्फ्लेशन तथा हाइपर इन्फ्लेशन के दौर में प्रवेश कर गया है. अब तक हम जिस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से बचते आए हैं, क्या इस फैसले ने हमें उस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौर का अगुआ तो नहीं बना दिया है.

सरकार निष्क्रिय साबित हो रही है. सरकार सिर्फ़ उन सवालों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, जो सवाल हिन्दुस्तान के लोगों में विकास और विकास के मॉडल को लेकर हैं, नौकरियों व लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलने की कोशिशों को लेकर हैं, कश्मीर के लोगों को लेकर हैं, बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर हैं. जिन वादों के ऊपर मौजूदा सरकार आई थी, उनमें से कितने वादे पूरे हुए, इसका कोई लेखा-जोखा न सरकार के पास है और न ही उन अर्थशास्त्रियों के पास, जो सरकार से जुड़े हैं. ढिंढोरची मीडिया के पास इन सवालों के जवाब तो हैं ही नहीं. हम देश में धीरे-धीरे एक अराजकता का माहौल पैदा करने के हिस्सेदार बनते जा रहे हैं.

कहीं ऐसा न हो कि इस फ़ैसले से देश में शादी इंडस्ट्री, खाने-पीने का उद्योग, जिसमें किसान का सामान ख़रीदा और बेचा जाता है, जिसमें छोटे स्तर के काम करने वाले, जिनमें सब्जी, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले हैं, जितने मंझोले और छोटे व्यापारी हैं, उनका काम दो साल के भीतर ख़त्म हो जाए. मल्टीनेशनल कंपनियां, जिस मॉल कल्चर को सालों से हिन्दुस्तान में लाने की कोशिश कर रही थीं, उसे एक झटके में ले आया गया है. उस मॉल कल्चर के आने से हमारे देश में करोड़ों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और उसका परिणाम कहीं बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के रूप में हमें न देखने को मिले. आज सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं, जिनका इस ब्लैकमनी के साम्राज्य से कोई लेना-देना नहीं है, जो अपनी मुसीबत के समय दस-बीस-चालीस हज़ार या एक लाख रुपए अपने घर में रखते हैं बड़े नोटों के रूप में क्योंकि छोटे नोट जगह ज्यादा घेरते हैं, उन पर सरकार ने ये प्रहार किया है. 90 प्रतिशत ब्लैकमनी चलाने वाले जो कुछ लोग हैं, उनके ऊपर सरकार का कोई प्रहार नहीं हुआ. वो सुरक्षित हो गए और इस समय मुस्कुराते हुए इस देश की राजनीति को सौ प्रतिशत अपने कब्जे में लेने की योजना बनाते हुए शराब की पार्टियां कर रहे होंगे. अगर कहीं ईश्वर है तो मेरी उससे प्रार्थना है कि मेरी ये सारी शंकाएं निर्मूल साबित हों और ये चेतावनियां कूड़े के ढेर में चली जाएं. पर अफसोस ऐसा नहीं होने वाला और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ़ कुछ महीने चाहिए और उन दो महीनों के भीतर इन चेतावनियों के सत्य होने की शुरुआत हो जाएगी, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा. ■

editor@chauthiduniya.com

कहीं ऐसा न हो कि इस फ़ैसले से देश में शादी इंडस्ट्री, खाने-पीने का उद्योग, जिसमें किसान का सामान ख़रीदा और बेचा जाता है, जिसमें छोटे स्तर के काम करने वाले, जिनमें सब्जी, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले हैं, जितने मंझोले और छोटे व्यापारी हैं, उनका काम दो साल के भीतर ख़त्म हो जाए. मल्टीनेशनल कंपनियां, जिस मॉल कल्चर को सालों से हिन्दुस्तान में लाने की कोशिश कर रही थीं, उसे एक झटके में ले आया गया है. उस मॉल कल्चर के आने से हमारे देश में करोड़ों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और उसका परिणाम कहीं बिगड़ी हुई क़ानून व्यवस्था के रूप में हमें न देखने को मिले.

मत-मतांतर

नेहरू के लिए अव्यवहारिक था गांधी का हिंद स्वराज

पिछले अंक में हमने नेहरू के नाम महात्मा गांधी का पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को स्वराज के सिद्धांत के बारे में बताया था, लेकिन पंडित नेहरू के विचार महात्मा गांधी से अलग थे. महात्मा गांधी भारत के विकास का आधार गांवों को बनाना चाहते थे, परंतु पंडित नेहरू का भरोसा औद्योगीकरण में था. गांधीजी धर्म को शिक्षा और राजनीति दोनों का एक आवश्यक अंग मानते थे, परंतु पंडित नेहरू को धर्म शब्द से ही चिढ़ थी. महात्मा गांधी अंग्रेजी सभ्यता को भारत ही नहीं, वरन् पूरी दुनिया के लिए खतरा मानते थे, परंतु पंडित नेहरू अंग्रेजी सभ्यता के प्रशंसक थे. गांधी और नेहरू का यह वैचारिक मतभेद किसी कल्पना पर आधारित नहीं है. उनका यह मतभेद उनके आपसी पत्र व्यवहार से साफ पता चलता है. इस अंक में हम पंडित नेहरू द्वारा 1945 में गांधीजी को लिखे गये पत्र को प्रकाशित कर रहे हैं. यह पत्र नेहरू ने गांधीजी के उस पत्र के उत्तर में लिखा था, जिसमें गांधीजी ने उन्हें देश के विकास का प्रारूप तैयार करने से पहले हिन्द स्वराज पढ़ने की राय दी थी. गांधीजी का वह पत्र पिछले अंक में प्रकाशित किया जा चुका है. पंडित नेहरू का उत्तर यहां प्रस्तुत है.

आनंद भवन, इलाहाबाद
9 अक्टूबर, 1945

प्रिय बापू,

संक्षेप में कहूं, तो मेरा मानना है कि हमारे सामने सवाल सच बनाम झूठ और अहिंसा बनाम हिंसा का नहीं है. सभी का प्रयास होना चाहिए कि आपसी सहयोग एवं शांतिपूर्ण रास्ता हमारा ध्येय हो और एक ऐसे समाज का निर्माण करना हमारा उद्देश्य, जो इस रास्ते पर ले जाने को प्रेरित करता हो. सवाल यह है कि ऐसे समाज का निर्माण कैसे हो और इसके अवयव क्या हों? मुझे समझ नहीं आता कि किसी गांव में सच्चाई और अहिंसा पर इतना बल क्यों दिया जाता है? आमतौर पर माना जाता है कि गांवों में रहने वाले लोग बुद्धिमत्ता और सांस्कृतिक तौर पर पिछड़े हुए होते हैं. एक पिछड़े हुए वातावरण में कोई प्रगति नहीं हो सकती, बल्कि संकुचित विचारों वाले लोगों के झूठे व हिंसक होने की संभावना ज्यादा रहती है.

इसके अलावा, हमें अपने कुछ लक्ष्य भी तय करने हैं, मसलन, खाद्य सुरक्षा, कपड़े, आवास, शिक्षा, स्वच्छता, वगैरह. ये वे न्यूनतम लक्ष्य हैं, जो किसी भी देश या व्यक्ति के लिए अनिवार्य हैं. इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमें यह देखना है कि हम कितनी तेजी से उन्हें हासिल कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, यातायात के आधुनिक साधनों व दूसरी आधुनिक गतिविधियों का विकास और उनकी निरंतर प्रगति भी मुझे अपरिहार्य लगते हैं. इसके अलावा, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखता. भारी उद्योग भी आज की आवश्यकता हैं और क्या यह सब विशुद्ध ग्रामीण परिवेश में संभव है?

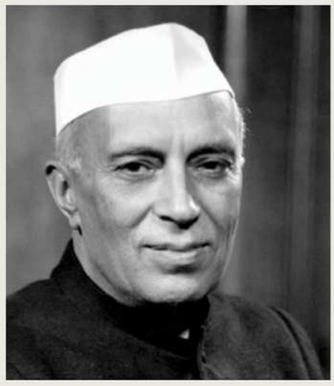

व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि भारी और हल्के उद्योगों का यथासंभव विकेन्द्रीकरण होना चाहिए और बिजली का नेटवर्क बन जाने के बाद यह संभव भी है. देश में अगर दो तरह की अर्थव्यवस्था काम करेगी तो या तो दोनों के बीच द्वंद्व होगा या एक, दूसरे पर हावी हो जाएगी.

लाखों-करोड़ों लोगों के लिए महल बनाने का सवाल नहीं है. लेकिन इसका भी कोई कारण नहीं है कि उन सभी को ऐसे सुविधाजनक व आधुनिक घर मिल सकें, जहां वे एक अच्छा संस्कारी जीवन जी सकें. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई भारी-भरकम शहरों में बहुत सी बुराइयां घर कर गई हैं. इनकी निंदा की जानी चाहिए. शायद हमें एक सीमा से अधिक शहरों के विकास पर रोक लगानी होगी, लेकिन साथ ही गांव वालों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना होगा कि वे शहरों की संस्कृति में खुद को ढाल सकें.

उस बात को कई साल हो गए हैं, जब मैंने हिन्द स्वराज पढ़ी थी. आज मेरे दिमाग में उसकी कुछ धुंधली सी यादें हैं, लेकिन जब मैंने उसे 20 या अधिक साल पहले पढ़ा था, तब भी वह मुझे अव्यावहारिक लगी थी. उसके बाद के आपके लेखों व भाषणों से मुझे लगा है कि आप भी उस समय से काफी आगे निकल चुके हैं और आधुनिक परिवेष को समझने लगे हैं. इसलिए मुझे तब आश्चर्य हुआ, जब आपने कहा कि वह पुरानी तस्वीर आज भी आपके दिमाग में बसी हुई है. आपको मालूम ही है कि कांग्रेस ने उस तस्वीर पर कभी विचार ही नहीं किया. उसे स्वीकार करने की बात तो छोड़ ही दीजिए. आपने स्वयं भी कभी इसके लिए जोर नहीं दिया. एकाध मामूली से अपवाद को छोड़ कर. यह निर्णय आपको करना है कि इस तरह के आधारभूत, लेकिन दार्शनिक सवालों पर कांग्रेस को विचार भी करना चाहिए. मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसे संगठन को इस तरह की किसी बहस में नहीं उलझना चाहिए, जिससे लोगों के दिमाग में उलझन पैदा हो और वे वर्तमान में काम करने में असमर्थ हो जाएं. इससे कांग्रेस और देश के दूसरे लोगों के बीच एक दीवार भी खड़ी हो सकती है.

आपका ही,
जवाहरलाल

कोसी में सक्रिय हैं मौत के सौदागर

कोसी के विभिन्न इलाकों में संचालित नर्सिंग होम में से अधितर के रसूखदार लोगों द्वारा चलाए जाने की बातों से स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों सहित प्रशासनिक पदाधिकारी भी इंकार नहीं करते. कुछ के निबंधन की बात तो सामने आ रही है, लेकिन कई बिना निबंधन के ही संचालित हैं. इससे बड़ी हकीकत यह है कि विभिन्न नर्सिंग होम के बाहर लटके पड़े बोर्ड पर अंकित डॉक्टरों में से अधिकांश को इस बात का पता भी नहीं होता कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. कई मौके पर इस बात का पर्दाफाश भी हो चुका है.

राजेश

जिंदगी व मौत की जंग लड़ रही पिंकी देवी के साथ-साथ श्वेता देवी भले ही हांफने लगी हो और उसकी आंखों में मौत नाचने लगी हो, लेकिन उनका गलत ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की अब तक न ही पहचान संभव हो सकी है और न ही बिना निबंधन के संचालित दिव्य नर्सिंग होम के संचालक को गिरफ्तार किया गया है. हद तो यह है कि खगड़िया के सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार सिंह मामले की तफ्तीश कर फर्जी क्लिनिक संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय अपनी नाकामी छिपाने के लिए यह कह रहे हैं कि क्या करें, सभी फर्जी क्लिनिक संचालकों को जेल भेज दें! लगातार घटित घटनाओं के बाद मची हाय-तौबा के बीच डीएम जय सिंह के द्वारा जारी जांच का आदेश भी दम तोड़ने लगा है. सिविल सर्जन के द्वारा कार्रवाई की बात तो दूर, जांच की भी जहमत नहीं उठाई गई है. वह कहते हैं कि चिकित्सकों की कमी के कारण जांच कार्य संभव नहीं हो पा रहा है. अगर चिकित्सकों को फर्जी क्लिनिक व डॉक्टरों की कुंडली खंगालने के साथ-साथ दिव्य नर्सिंग होम में गलत ऑपरेशन की शिकार पिंकी व श्वेता के मामले में लगा दिया गया तो सदर अस्पताल का ओपीडी बंद करना होगा. वैसे सीएस भी इस बात को स्वीकारते हैं कि दबंग व रसूखदार लोगों के द्वारा खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा सहित कोसी के विभिन्न इलाकों में फर्जी तरीके से संचालित दर्जनों नर्सिंग होम के विरूद्ध कार्रवाई करना शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है. अन्य नर्सिंग होम की बातों को फिलवक्त नजरअंदाज कर अगर खगड़िया जिले के गोगरी थाना अंतर्गत मुश्कीपुर कोठी स्थित दिव्य नर्सिंग होम की बात की जाय तो यह नर्सिंग होम पहली बार सुर्खियों में नहीं आया है, अन्य कई तरह के फर्जीवाड़े को लेकर दिव्य नर्सिंग होम अक्सर सुर्खियों में रहा है. कमोबेस पिंकी देवी की ही तरह प्रसव वेदना पीड़ित श्वेता देवी भी दिव्य नर्सिंग होम में भर्ती हुई थी. सिजेरियन ऑपरेशन के बाद गौछाड़ी की रहने वाली पिंकी को लड़का पैदा हुआ जबकि श्वेता को लड़की, लेकिन दोनों के नवजात अब तक मां की दूध के लिए तड़प रहे हैं. डॉक्टरों ने तीन-तीन बार उनका ऑपरेशन किया और अब आंत में इंफेक्शन होने के कारण दोनों जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं. श्वेता देवी के पति संजीत कुमार की लिखित तहरीर पर पुलिस मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा कि दिव्य नर्सिंग होम में ही दोनों प्रसव वेदना पीड़ित महिलाओं का ऑपरेशन होने की बात प्रमाणित होने के बाद भी प्राथमिकी तक दर्ज नहीं हुई है. गंभीर स्थिति में अन्यत्र इलाजरत पिंकी के परिजनों द्वारा किसी तरह की लिखित शिकायत पुलिस अथवा प्रशासनिक पदाधिकारियों के समक्ष नहीं किए जाने के कारण डीएम के द्वारा जारी जांच के आदेश को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है. ऐसी स्थिति में अन्य मामलों की तरह अगर इस मामले को भी जमींदोज कर दिया गया तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए. श्वेता और पिंकी ही नहीं दर्जनों मरीज फर्जी तरीके से संचालित दिव्य नर्सिंग होम में बैठे तथाकथित डॉक्टरों का शिकार होकर या तो मौत के गाल में समा चुके हैं या जिंदगी और मौत के बीच जूझने को मजबूर हैं. पिंकी और श्वेता दिव्य नर्सिंग होम में इलाज कराने पहुंची थीं. इसके फर्जीवाड़े की कहानी से अनभिज्ञ प्रसव वेदना से पीड़ित पिंकी तथा श्वेता को क्या पता था कि स्वास्थ्य होने की कामना लेकर वे दिव्य नर्सिंग होम पहुंची तो हैं, लेकिन सौगात में सिसकती जिंदगी मिलेगी. दोनों के परिजनों से चौबीस-चौबीस हजार रुपये लेकर पहली बार सिजेरियन ऑपरेशन किया गया. पिंकी को लड़का पैदा हुआ जबकि श्वेता को बेटी. लेकिन नवजात को जनने की खुशियां दोनों की आंखों से काफूर हो गईं. पिंकी व श्वेता के साथ-साथ इनके परिजनों के पैरों तले से जमीन तब खिसक गई जब

> **डॉक्टर अमित का कहना है कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि दिव्य नर्सिंग होम तथा परमानंद हॉस्पीटल में वह अपनी सेवा देते हैं, लेकिन अगर दिव्य नर्सिंग होम में पिंकी देवी का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, तो वह इन्होंने नहीं किया. श्वेता देवी का ऑपरेशन इन्होंने किया है, लेकिन गलत ऑपरेशन नहीं. इधर डॉक्टर सचिन कुमार गौतम का कहना है कि दिव्य नर्सिंग होम में इनके बिना सहमति के ही नाम अंकित कर दिया गया है. इतना ही नहीं स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ के नाम पर डॉक्टर पवन कुमारी को ढाल बनाया जा रहा है. यहां तक कि दिव्य नर्सिंग होम का स्वास्थ्य विभाग द्वारा निबंधन तक नहीं कराया गया है.**

कुछ ही घंटों बाद पिंकी व श्वेता के पेट में असहनीय दर्द शुरू हुआ. आनन-फानन में दोनों को पुनः दिव्य नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया. नर्सिंग होम संचालक रिंकेश उर्फ पिंकेश के द्वारा पिंकी व श्वेता के परिजनों को फिर से पेट खोलने के एवज में राशि जमा करने का आदेश दिया गया. ऑपरेशन के नाम पर दोबारा पेट खोलने से पहले बीस से पच्चीस हजार रुपये खर्च होने की बात बताई गई, लेकिन पेट खोलने के बाद भारी-भरकम राशि वसूल ली गई. दोनों के परिजनों के सर दुःख का पहाड़ उस समय टूट पड़ा जब तीसरी बार पेट में दर्द की शिकायत कर पिंकी व श्वेता कराहने लगीं. एक बार फिर पेट खोलने की बात बताकर दोनों को भर्ती कर लिया गया. ऑपरेशन के बाद जब पैसे जमा करने की बारी आयी तो परिजनों को सूद पर रुपये लेने पड़े. सूद पर रुपये लेकर नर्सिंग होम की फीस तो चुका दी गई, लेकिन पिंकी अब भी बेगूसराय के प्रभा नर्सिंग होम में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और श्वेता भी किसी अन्य नर्सिंग होम में स्वास्थ्य जिंदगी पाने के लिए संघर्ष कर रही है.

नदियों से घिरे कोसी इलाके में इस तरह का वाकया पहली बार सामने नहीं आया है. अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और मामला शांत पड़ते ही फिर से फर्जी डॉक्टरों द्वारा मौत बांटने का खेल शुरू कर दिया जाता है. चौथम थाना अंतर्गत करुआमोड़ स्थित परमानंद हॉस्पीटल में किए गए ऑपरेशन के बाद पंकज की बिगड़ी स्थिति को लेकर कुछ दिनों तक खगड़िया या यों कहें कि कोसी इलाका खूब उबला था. धरना-प्रदर्शन के बाद भी जब स्वास्थ्य विभाग के जिला प्रमुख की नींद नहीं खुली, तो बेशर्मी की हद पार कर चुके सिविल सर्जन को नींद से जगाने के लिए आंदोलित परिजनों सहित ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम कर दिया गया. पदाधिकारियों सहित सिविल सर्जन की नींद खुली और आनन-फानन में जांच का आदेश जारी किया गया. लेकिन जांच के नाम पर महज डॉक्टरों की टीम बनाकर खानापूर्ति कर ली गई.

कोसी के विभिन्न इलाकों में संचालित नर्सिंग होम में से अधिकतर के रसूखदार लोगों के द्वारा चलाए जाने की बातों से स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों सहित प्रशासनिक पदाधिकारी भी इंकार नहीं करते. कुछ के निबंधन की बात तो सामने आ रही है, लेकिन कई बिना निबंधन के ही संचालित हैं. इससे बड़ी हकीकत यह है कि विभिन्न नर्सिंग होम के बाहर लटके पड़े बोर्ड पर जिन डॉक्टरों के नाम लिखे होते हैं, उनमें से अधिकतर को इस बात का पता भी नहीं होता कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. कई मौके पर इस बात का पर्दाफाश भी हो चुका है. लेकिन अभी तक किसी भी मामले में कार्रवाई नहीं होना, कई तरह के सवालों को जन्म देने के लिए काफी है. अन्य मामलों को दरकिनार कर अगर पिंकी तथा श्वेता के ऑपरेशन मामले को खंगाला जाय, तो यह प्रमाणित होना तय है कि कोसी में फर्जी डॉक्टरों के द्वारा बड़े-बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं. दिव्य नर्सिंग होम में पिंकी तथा श्वेता के ऑपरेशन की बात तो प्रमाणित हो चुकी है, लेकिन इतनी हाय-तौबा मचने के बाद भी अभी तक यह प्रमाणित नहीं हो सका है कि आखिर किस डॉक्टर के द्वारा श्वेता तथा पिंकी का तीन-तीन बार गलत ऑपरेशन किया गया. श्वेता तथा पिंकी देवी के परिजनों द्वारा चीख-चीखकर कहा जा रहा है कि डॉक्टर अमित कुमार के ही द्वारा ऑपरेशन किया गया है. लेकिन आरोपित डॉक्टर अमित कुमार पिंकी का ऑपरेशन किए जाने से इंकार कर रहे हैं. डॉक्टर श्वेता का गलत ऑपरेशन किए जाने की बातों को भी सिरे से खारिज कर रहे हैं. डॉक्टर अमित का कहना है कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि दिव्य नर्सिंग होम तथा परमानंद हॉस्पीटल में वह अपनी सेवा देते हैं, लेकिन अगर दिव्य नर्सिंग होम में पिंकी देवी का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, तो वह इन्होंने नहीं किया. श्वेता देवी का ऑपरेशन इन्होंने किया है, लेकिन गलत ऑपरेशन नहीं. इधर डॉक्टर सचिन कुमार गौतम का कहना है कि दिव्य नर्सिंग होम में इनके बिना सहमति के ही नाम अंकित कर दिया गया है. इतना ही नहीं स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ के नाम पर डॉक्टर पवन कुमारी को ढाल बनाया जा रहा है. यहां तक कि दिव्य नर्सिंग होम का स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निबंधन तक नहीं कराया गया है. इधर खगड़िया के जिलाधिकारी जय सिंह ने फर्जी चिकित्सकों के साथ-साथ फर्जी नर्सिंग होम संचालकों को खबरदार करने के अंदाज में कहा है कि इलाके के किसी भी फर्जी चिकित्सकों के साथ-साथ फर्जी नर्सिंग होम संचालकों को बख्शा नहीं जाएगा. संदर्भित जांच रिपोर्ट मिलते ही फर्जीवाड़े के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.■

feedback@chauthiduniya.com

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड

पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी

Laboratory Tested
Please Compare Lab Report

Made from Imported Chemicals
ईटालियन व्हाईट वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior

लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है

प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतू सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ

सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ
मिस्टर केमिस्ट

सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध। मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए।

Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

बागमती तटबंध ने बदला गांवों का भूगोल

> तकरीबन चार दशक पूर्व तत्कालीन सरकार ने बागमती नदी की दहाड़ पर लगाम लगाकर बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने का प्रयास किया. आमजनों के विरोध के बावजूद सरकारी फरमान के अनुसार बागमती नदी के दोनों किनारे तटबंध निर्माण का कार्यारंभ कराया गया. करोड़ों की लागत से शुरू यह योजना ससमय पूरी नही की जा सकी. वर्ष 2005 में जब बिहार के शासन की कमान मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने संभाली, तब चुनावी घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए तटबंध निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की दिशा में पहल की. तटबंध निर्माण से एक ओर जहां प्रतिवर्ष होने वाले जानमाल की क्षति पर विराम लगा है, वहीं कई मामलों में बांध लोगों के लिए अभिशाप साबित होकर रह गया है. आलम यह है कि हजारों एकड़ उपजाऊ जमीनों ने अब खरही के जंगल का रूप ले लिया है, वहीं सैकड़ों परिवारों को जीवन यापन के लिए परदेश भटकना पड रहा है.

वाल्मीकि कुमार

सीतामढ़ी

साल 1975 में जब बागमती नदी के दोनों किनारे तटबंध निर्माण की कवायद शुरू की गई थी, तब गांवों के लोगों को लगा था कि यह सहीं नही है. उस वक्त लोगों ने बांध निर्माण का विरोध तो किया, परंतु तत्कालीन हुक्मरानों के फैसले में इनकी आवाजें दबकर रह गईं. आमजनों की भावनाओं की अनदेखी कर शुरू कराया गया कार्य भी अधर में ही अटक गया. इस बीच प्रतिवर्ष बागमती नदी में आने वाली बाढ़ से व्यापक स्तर पर जानमाल का नुकसान आम बात बनी रही. भारत-नेपाल सीमा पर बसा सीतामढ़ी जिला विकास के मामले में तब एक कोने में दुबका दिखता रहा. राजधानी पटना से भाया मुजफ्फरपुर होते सीतामढ़ी तक की वन वे सड़क को साल 2000 से पूर्व ही एनएच-77 का दर्जा दे दिया गया था. परंतु सड़क का हाल गांव की पगडंडी से बेहतर नहीं हो सका था. साल 2005 में बिहार में चले सत्ता परिवर्तन के दौर ने शासन की कमान नीतीश कुमार के हाथों में दे दी. इस वक्त नीतीश ने अलग-अलग चुनावी सभाओं में मंच से यह घोषणा की थी कि अगर बिहार में शासन का कमान मिला तो सबसे पहले आवागमन की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे. सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर एनएच-77 के कटौझा का तात्कालिक हाल यही था कि साल के चार माह तक लोगों के लिए 60 किलोमीटर की दूरी तय कर एक दिन में वापस आना मुश्किल बना रहता था. लोगों को कटौझा में बाढ़ के दौरान तकरीबन ढाई किलोमीटर की यात्रा नाव अथवा ट्रैक्टर से करने की विवशता होती थी. शारीरिक, आर्थिक व मानसिक यातनाओं के दौर को झेलने वालों ने भरोसा कर बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए कमर कसी थी. चुनाव बाद जब नीतीश कुमार ने शासन की बागडोर संभाली तो सबसे पहले कटौझा में बागमती नदी पर रामवृक्ष बेनीपुरी सेतू का निर्माण कराने के साथ हीं लोगों में नयी उम्मीदें भी भरी.

अब चर्चा कुछ स्थानीय पहलुओं पर भी जरूरी है. बताया जाता है कि साल 1975 में बांध निर्माण कार्य का अंतिम पड़ाव सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड के तिलकताजपुर गांव के समीप रहा. जहां नेपाल सीमा से दोनों किनारे बांध के बीच जमा बाढ़ का पानी इस गांव के समीप खुले मैदान में उतरते ही अपने रौद्र रूप से लोगों को बेचैन करता रहा. एक ओर जहां खेतों में लहलहाते फसलों के साथ सैकड़ों लोगों का आशियाना तबाह होता रहा, वहीं आवागमन की

असुविधा के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य परेशानियों का सामना लोगों की नियति बनी रही. तकरीबन तीन से चार माह तक लोगों को आवश्यक कार्य के लिए नाव से ही आवागमन की मजबूरी थी. तटबंध निर्माण के बाद का हाल यह है कि दोनों बांध के बीच पड़ जाने के कारण कई गांवों से लोगों को अपना पुस्तैनी मकान छोड़कर पलायन करना पड़ा है. सरकारी स्तर पर विस्थापितों को पुनर्वास के लिए मामूली जमीनें दे दी गई, जो परिवारों के बढते सदस्यों की संख्या के हिसाब से अपर्याप्त साबित होता रहा. संपन्न लोगों ने आवश्यकतानुसार जमीन खरीद कर नया आशियाना तैयार कर लिया. परंतु सैकड़ों मध्यम वर्गीय व कमजोर परिवारों के लिए जीवन यापन अब भी गंभीर चुनौती बनी है. जानकारों की मानें तो क्षेत्र के तिलकताजपुर, मधौल व मानपुर रत्नावली गांव के ही करीब 4 हजार परिवारों को अपना पुस्तैनी घर छोड़कर भागना पड़ा है. आलम यह है कि कभी घनी बस्ती के रूप में चर्चित रहे इन गांवों का वर्तमान में भूगोल बदल गया है. जो पूर्व में पड़ोसी थे, वे वर्तमान में काफी दूर हो गए हैं. कोई बस्ती में तो कोई वीरान सरेह में बसने को मजबूर हैं.

> क्षेत्र के तिलकताजपुर, मधौल व मानपुर रत्नावली गांव के ही करीब 4 हजार परिवारों को अपना पुस्तैनी घर छोड़कर भागना पड़ा है. आलम यह है कि कभी घनी बस्ती के रूप में चर्चित रहे इन गांवों का वर्तमान में भूगोल बदल गया है. जो पूर्व में पड़ोसी थे, वे वर्तमान में काफी दूर हो गए हैं. कोई बस्ती में तो कोई वीरान सरेह में बसने को मजबूर हैं. जहां तक नदी के हाल का सवाल है, तो तटबंध का निर्माण कई मायने में नदी के लिए भी घातक साबित हो रहा है. संभव है आने वाले सालों में इसके भयावह रूप से लोगों को सामना करना पड़े.

जहां तक नदी के हाल का सवाल है तो तटबंध का निर्माण कई मायने में नदी के लिए भी घातक साबित हो रहा है. संभव है आने वाले सालों में इसके भयावह रूप से लोगों को सामना करना पड़े. बताया जाता है कि तटबंध निर्माण से पूर्व प्रतिवर्ष बाढ़ के पानी के साथ आने वाली मिट्टी की परतें जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती थीं, जिससे एक ओर बाढ़ से लोगों की तबाही बढ़ती थी, तो दूसरी ओर जमीन में फसलों का बेहतर होना इनके सारे जख्मों के लिए मरहम का काम करता था. परंतु बांध बनने के बाद अब बाढ़ के पानी के साथ आने वाली मिट्टी व बालू की परतें नदी के गर्भ में ही जमा होने लगी हैं. नतीजतन एक ओर जहां किसानों के जमीन की उर्वरा शक्ति का ह्रास होने लगा है. वहीं दूसरी ओर नदी का गर्भ भरने लगा है. ऐसे में भारी बाढ़ के दौरान तटबंधों के टूटने की संभावना अधिक बढ़ती जा रही है. लोगों की मानें तो बागमती नदी की धारा में शायद ही कोई स्थान रहा है, जहां से किसी भी महीने में कोई पानी पार कर एक से दूसरे छोर तक जाने का साहस करता था. लेकिन वर्तमान में हाल यह है कि नदी की बीच धारा में कई स्थानों पर टापू बन गया है. हाल के दशक में नदी की कई उपधारायें भी निकल आई हैं. यह कभी भी तटबंधों को ध्वस्त कर आम जनों के लिए घातक साबित हो सकती हैं. सबसे पहली धारा कंसार गांव के समीप से निकली जो खड़का होते हुए भर्थी से मुख्य धारा में मिली. वर्तमान में कटौझा के समीप बागमती नदी पर बने पुल के उत्तरी व दक्षिणी भाग से दो धारायें आकर मिलती हैं. इन दोनों ही धाराओं के बीच तकरीबन 2 हजार एकड़ उपजाऊ जमीन वर्तमान में बीहड़ का रूप ले चुकी है. उन जमीनों का हाल यह है कि कोई भी भूस्वामी अब वहां जाना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि बालू के टीले में बदल चुके वे जमीन अब खरही जंगल का रूप ले चुके हैं. भूस्वामियों के लिए वे जमीन फिलहाल किसी काम के नही रह गए हैं.

क्षेत्र की बदहाली दूर करने को लेकर सरकारी योजनाओं के तहत विकास का खाका तो खींचने का प्रयास किया गया. परंतु वह अब तक नहीं किया जा सका है, जिसकी जरूरत सबसे पहले थी. रून्नीसैदपुर की पूर्व विधायक गुड्डी देवी ने बतौर विधायक विस्थापितों के पुनर्वास के लिए जमीन मुहैया कराने को लेकर सार्थक पहल की थीं. गांव की गलियों को मुख्य सड़क से जोडने के अलावा शिक्षा, चिकित्सा व बिजली समेत अन्य समस्याओं का निदान कराने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया था. जिसका परिणाम अब लोगों के बीच है. मगर चुनावी वादा कर वोट बटोरने वाले प्रतिनिधियों ने कुछ भी ऐसा नही किया, जिससे स्थानीय लोगों की समस्या का स्थायी निदान संभव हो सके. न रोजगार को लेकर कोई योजना सरकारी स्तर पर इन क्षेत्रों में पहुंची है और न ही औधोगिक विकास को लेकर ही कोई प्रयास किया जा सका है. नतीजा है कि हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग पलायन को मजबूर हैं. जीवन यापन के लिए परदेश में पसीना बहाना इनकी नियति बन गयी है. आवश्यकता है क्षेत्र में रोजगार के लिए बेहतर अवसर के साथ ही सरकारी स्तर पर आमलोगों के मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की. इन घरों को रोशन करने की, जहां अब तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच सकी है. सरकार प्रायोजित योजनाओं का लाभ हकदारों को मिले इसकी गारंटी की जवाबदेही भी जनप्रतिनिधियों को लेनी होगी.■

feedback@chauthiduniya.com

दाँतों के साथ मसूढ़ों की करें हिफाजत
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

खगड़िया के दंत चिकित्सक डॉ. सुधांशु शेखर ने दांतों और मसूढ़ों की सुरक्षा के लिए लोगों को समय देने के लिए कहा और बताया कि दांत को साफ करने के साथ मसूढ़ों की भी सुरक्षा जरूरी है और इसके लिए सबसे पहले अपनी साफ अंगुली से खाना खाने के बाद मुंह धोते वक्त मसाज करें या साफ करें। यह आदत बच्चों में भी डालें खाना खाने के दांतों और मसूढ़ों की बीच कुछ फंसा नहीं होना चाहिए। डॉ. शेखर ने आगे बताते हुए कहा कि हरेक दांत के दो मुख्य भाग होते हैं- शीर्ष और जड़. शीर्ष दांत का वह भाग होता है, जिसे आप देख सकते हैं, और जड़ आपके मसूड़ों के नीचे छिपी होती है। यह दांत की कुल लंबाई का करीब दो तिहाई हिस्सा होती है। वयस्कों में ज्ञान दंत समेत 32 स्थायी दांत होते हैं। प्रत्येक दांत का निर्माण चार प्रकार के ऊतकों से होता है एनामेल या आवरण स्थायी, उजला आवरण होता है। एनामेल दांत को चबाने के दौरान होनेवाली टूट-फूट से बचाता है। डेंटिन आपके दांत के आवरण की सुरक्षा करता है। यह पीले रंग का हड्डी जैसा पदार्थ होता है, जो एनामेल से मुलायम होता है और इसमें कुछ स्नायु तंत्र भी होते हैं, जो आपको आपके दांत के भीतर कुछ होनेवाली गड़बड़ के बारे में बताते हैं।

पल्प या गूदा दांत का केंद्र होता है। यह नरम ऊतक होता है, जो रक्त और द्रव वाहिकाओं तथा स्नायु तंत्र से भरा होता है। पल्प के माध्यम से ही दांत पोषण ग्रहण करता है और आपके दिमाग को संकेत भेजता है। सीमेंटम या जड़यौगिक से दांत की जड़ का अधिकांश हिस्सा ढंका होता है। यह आपके जबड़ों की हड्डियों से दांतों को जोड़े रखने में मदद करता है। सीमेंटम और जबड़े की हड्डी के बीच एक गद्देदार परत होती है, जिसे पीरियोडोंटल लिगामेंट कहा जाता है। यह दोनों को जोड़ने में मदद करती है। मुंह का स्वास्थ्य आपके मसूड़े(जिंजिवे) आपके दांतों को घेरे रख कर उनको अपनी जगह पर जमाए रखते हैं। अपने दांतों को कम से कम दो बार ब्रश करें,जब आप ब्रश करें तो जल्दबाजी न करें ,अच्छी सफाई के लिये इसे पर्याप्त समय दें। अच्छे टूथपेस्ट और टूथब्रश का प्रयोग करें फ्लोराइड टूथपेस्ट और मुलायम ब्रिस्टल वाले टूथब्रश का प्रयोग करें। अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करें अपने टूथब्रश को अपने दांतों से हल्के कोण पर पकड़ें और आगे और पीछे करते हुए ब्रश करें,अपने दांतों की भीतरी और चबाने वाली सतहों और जीभ पर ब्रश करना न भूलें ,तेजी से न रगड़े,वरना आपके मसूड़े कट भी सकते हैं। टूथब्रश बदलना हर तीन से चार महीनों में नया टूथब्रश खरीदें ह्या उससे भी पहले यदि ब्रिस्टल फैल गए हों। हमेशा नरम ब्रिस्टल वाले टूथब्रश का प्रयोग करें। भोजन के बाद कुल्ला करके मुंह को साफ कर लें। दांतों के बीच फ्लॉस्स करके फंसे हुए खाद्य कणों को निकाल दें।▪ भारती

डॉ. सुधांशु शेखर सुमन
दंत चिकित्सक (BDS)) खगड़िया
ममता डेन्टल क्लीनिक,मछली बन के पिछे

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.

बालमुकुन्द डायमंड टी.एम.टी.
IS:1786
CM/L5125752
To know more about Balmukund Diamond TMT
नं०1 छड़ बालमुकुन्द पीढ़ियों चले
FE 500+
इसमें है दम
यही है नम्बर 1
सभी प्रकार के निर्माण में मजबूती एवं सुरक्षा की गारन्टी
Website : www.balmukundtmt.com, Email : bconcast@yahoo.com

उजागर हो रहीं बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री के क्षेत्र की 'बेसिक' ख़ामियां

कैलाश चौरसिया

तीन बार चुने गए काम एक बार भी नहीं किया

डॉ. नीरज त्रिपाठी

संतोष देव गिरि

सूबे के बेसिक शिक्षा एवं पुष्टाहार राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आने लगी हैं. उन्हें उनके ही घर में घेरने की तैयारी शुरू कर दी गई है. तीन बार से मीरजापुर सदर सीट से विधायक चुने जाने के साथ मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले कैलाश चौरसिया के खिलाफ विकास कार्यों की अनदेखी और विकास कार्यों के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए जनपद के प्रमुख चिकित्सक एवं भाजपा नेता डॉ. नीरज त्रिपाठी ने मोर्चा खोल दिया है. मंत्री पर उनके गृह जनपद मीरजापुर में बेसिक शिक्षा विभाग में सह समन्वयकों की नियुक्ति शासनादेश एवं उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर बड़े पैमाने पर थांधली का आरोप लगाया गया है. बेसिक शिक्षा विभाग में चल रहे निरंतर अनियमितताओं और घोटाले की शिकायत मुख्यमंत्री से करते हुए जांच कराये जाने की भी मांग की गई है. राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया के विभाग बेसिक शिक्षा के अंतर्गत मीरजापुर में घूस लेकर नई नियुक्तियां की जा रही हैं. विभाग में मध्य सत्र में पुनः स्थानान्तरण एवं प्रमोशन का कार्य भी रिश्वत लेकर किया जा रहा है. इस संबंध में आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई लेकिन संबंधित अधिकारी सूचना देने से कतरा रहे हैं. पिछले दिनों प्रदेश के बेसिक शिक्षा एवं पुष्टाहार राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया ने अपने

मीरजापुर-रीवां, मध्य प्रदेश नेशनल हाईवे सहित संत रविदास नगर (भदोही) औराई-विंध्याचल मार्ग के फोरलेन एवं मीरजापुर जिले के सभी संपर्क मार्गों की हालत खस्ता है. इसे आम जनता भुगत रही है. पिछली समीक्षा बैठक में राज्यमंत्री ने विंध्याचल नवरात्र मेला से पूर्व सड़कों के सुधार का आश्वासन दिया था, लेकिन वह भी बेमानी साबित हुआ.

जनसंपर्क कार्यालय पर प्रेस वार्ता के माध्यम से मीरजापुर और अपने सदर विधान सभा क्षेत्र में कराये गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज, गंगा नदी पर भटौली एवं चुनार में पुल, ट्रॉमा सेंटर आदि बनवाने का जिक्र किया था. जबकि सच्चाई इसके इतर है. वास्तविकता यह है कि इनमें से एक भी कार्य अभी पूर्ण नहीं हो पाया है और न काम के पूर्ण होने की कोई तिथि तय है. काम की लागत में दिनोंदिन इजाफा जरूर होता जा रहा है. भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है और प्रोजेक्ट के पूरा होने के नाम पर लूट की खुली छूट मिली हुई है. जांच होने पर मामला पूरी तरह से साफ हो जाएगा. दशकों से इन प्रोजेक्ट्स के लटके पड़े होने से विकास कार्यों की लागत में बढ़ोत्तरी होती जा रही है और जनता को परेशानियों से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है.

मीरजापुर-रीवां, मध्य प्रदेश नेशनल हाईवे सहित संत रविदास नगर (भदोही) औराई-विंध्याचल मार्ग के फोरलेन एवं मीरजापुर जिले के सभी संपर्क मार्गों की हालत खस्ता है. इसे आम जनता भुगत रही है. पिछली समीक्षा बैठक में राज्यमंत्री ने विंध्याचल नवरात्र मेला से पूर्व सड़कों के सुधार का आश्वासन दिया था, लेकिन वह भी बेमानी साबित हुआ. चौरसिया पिछले तीन बार से मीरजापुर नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते चले आ रहे हैं. लिहाजा ऐसे आश्वासनों का अर्थ लोगों को समझ में आता है. समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्यमंत्री होने के बाद भी वे अपने विधानसभा क्षेत्र को विकास की दौड़ में शामिल करा पाने में नाकाम रहे हैं. इनके विकास के खोखले दावों की पोल खोलने के लिए ही भाजपा ने 'पोलखोल यात्रा' शुरू करने का एलान किया है. इस अभियान के माध्यम से जन समस्याओं की अनदेखी किए जाने का पूरा चिट्ठा खोला जाएगा. 'पन्द्रह साल – नगर विधानसभा बदहाल' के नारे के साथ भाजपाई जनता के बीच जाएंगे. भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं जनपद के प्रमुख चिकित्सक डॉ. नीरज त्रिपाठी राज्यमंत्री के कामकाज पर सवाल उठाते हैं. वे कहते हैं कि जो काम राज्यमंत्री ने नहीं किया उसका भई श्रेय लेने की कोशिश करते हैं. चौरसिया केंद्र सरकार की विजयपुर गांव में प्रस्तावित सोलर पावर परियोजना का श्रेय भी अपने नाम करने का जतन करते दिखते हैं. राज्यमंत्री का नाम उन शिलापट्टों पर भी अंकित हो गया, जिन कार्यों से राज्यमंत्री का कोई लेना देना भी नहीं था. राज्यमंत्री द्वारा अपने निजी आवास स्थित जनसंपर्क कार्यालय से सरकारी अनुदान एवं राजकीय नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना भी क्षेत्र में चर्चा का विषय है. विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्यमंत्री ने लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए मिस्डकॉल नम्बर जारी किया. इसे लेकर भी लोगों में हास-परिहास जारी है. ■

नक्सल क्षेत्र में बेपटरी है पठन-पाठन

शिक्षा विभाग द्वारा सूबे के नक्सल प्रभावित गांवों में लोगों को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में बेहतर कदम उठाए जाने के दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है. मीरजापुर नक्सल प्रभावित राजगढ़ क्षेत्र की बदहाल शिक्षा व्यवस्था देख कर आम लोगों को भी रोना आता है. क्षेत्रीय निवासी रमाशंकर सिंह पटेल कहते हैं कि राजगढ़ क्षेत्र के अधिकांश प्राइमरी विद्यालय बंद रहते हैं. विद्यालय बंद होने से पठन-पाठन ठप्प रहता है. स्थानीय लोग राजगढ़ के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के साथ एमडीएम की गुणवत्ता जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं, ताकि सरकारी धन का बेजा उपयोग रुके और बच्चों को सुलभ शिक्षा का लाभ मिल सके.

पूर्वांचल में सक्रिय हो रही शिवसेना

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना भी मैदान में उतर रही है. शिवसेना ने पूर्वांचल के कई जनपदों में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है. जौनपुर जिले में शिवसेना ने उत्तर भारतीय संघ के नेता गुलाब दुबे को मैदान में उतारने का मन बनाया है. वाराणसी से शिवसेना के दिग्गज नेता अरुण पाठक के नाम की चर्चा जोरों पर है. गुलाब दुबे जौनपुर के मड़ियाहू क्षेत्र के रामपुर गांत के रहने वाले हैं. वाराणसी निवासी अरुण पाठक की पहचान काशी में वाटर फिल्म के विरोध से बनी थी. वाराणसी के ही शिवसेना महानगर अध्यक्ष अजय चौबे सहित कई अन्य नामों की चर्चा है. मीरजापुर, आजमगढ़, भदोही, गाजीपुर, मऊ और बलिया की विधानसभा सीटों पर शिवसेना अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है. शिवसेना उत्तर प्रदेश के युवा प्रभारी अरुण पाठक बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में शिवसेना पूरी दमदारी के साथ उतरेगी. उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी शीघ्र की जा सकती है. ■

बिना टेंडर के वितरित हो गए यूनिफॉर्म

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में लूट की खुली छूट है. इसकी बानगी यूनिफॉर्म वितरण में देखने को मिल रही है, जिसमें शासनादेश की धज्जियां उड़ाते हुए जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है. इस भ्रष्टाचार में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया का जनपद भी शामिल है. राज्यमंत्री के गृह जनपद मीरजापुर में विभागीय योजनाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को वितरित होने वाले यूनिफॉर्म को लेकर आरोप है कि बिना टेंडर निकाले ही करीब पांच दर्जन विद्यालयों में यूनिफॉर्म बांट दिए गए. अधिकांश जगहों पर रेडीमेड यूनिफॉर्म का वितरण किया गया है, जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि यूनिफॉर्म को सिलवाकर वितरित किया जाए. शासन का निर्देश है कि जिस विद्यालय में ढाई सौ से अधिक छात्र हैं, वहां पर नियमानुसार टेंडर कराकर ही यूनिफॉर्म का वितरण किया जाए. मीरजापुर जनपद में इस श्रेणी के पांच दर्जन से अधिक विद्यालय हैं. इन स्थानों पर ढाई सौ छात्रों से अधिक अथवा एक लाख से अधिक की धनराशि के यूनिफॉर्म का वितरण होना था, लेकिन कहीं भी इन निर्देशों और मानकों का पालन नहीं किया गया है. शासन का आदेश है कि अच्छी क्वालिटी का कपड़ा लेकर उसे छात्रों के नाप के अनुसार दर्जी से सिलवाकर ही उन्हें दिया जाए. इसके लिए शासन ने एक सेट यूनिफॉर्म की कीमत दो सौ रुपए तय कर रखी है. हर छात्र को दो सेट यूनिफॉर्म दिए जाने का निर्देश है. लेकिन हो रहा है इसका ठीक उल्टा. अभिभावकों का आरोप है कि उन्हें बाध्य किया जा रहा है कि वे रेडीमेड यूनिफॉर्म ही लें. इसके अलावा दूसरे कपड़ों की क्वालिटी को लेकर भी उंगलियां उठ रही हैं. अभिभावकों ने इसकी जांच कराए जाने की मांग की है. इस बारे में पूछने पर बीएसए मनभरन राम राजभर कहते हैं कि विद्यालयों में नियमानुसार यूनिफॉर्म का वितरण किया जा रहा है. वह बताते हैं कि कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहां नामांकन तो है, लेकिन वे छात्र स्कूल नहीं आते, ऐसे में यूनिफॉर्म तो उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो वास्तविक हैं और जो नियमित विद्यालय आते हैं. उल्लेखनीय है कि मीरजापुर जिले के परिषदीय विद्यालयों में ढाई लाख छात्रों को यूनिफॉर्म वितरण के लिए नामांकित किया गया था. पूरे जनपद में इस योजना के तहत 03 लाख 10 हजार 377 छात्र-छात्राएं हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

खीरी में ख़राब स्वास्थ्य सेवाएं, झूठ के आसरे सीएमओ

अजय गुप्ता

चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन सच मानिए, पूरे प्रदेश की जनता विभिन्न मुद्दों जैसे बिजली, पानी, कानून, रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर त्राहि-त्राहि कर रही है. प्रदेश में स्वास्थ्य का मुद्दा अत्यंत गंभीर है. इन दिनों समूचा प्रदेश डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टायफाइड जैसी बीमारियों से आक्रांत है. सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं. मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हो पा रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में बसे जनपद लखीमपुर खीरी की स्वास्थ्य सेवाएं तो पूरी तरह चरमरा गई हैं. डेंगू जैसे जानलेवा बुखार से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन जिला अस्पताल में संक्रामक बीमारियों से बचाने का कोई इन्तजाम नहीं है. जिला अस्पताल में अव्यवस्था का साम्राज्य है. पीड़ितों की सुनने वाला कोई नहीं है. पूरे अस्पताल परिसर में गंदगी भरी पड़ी है. मरीजों के तीमारदारों के लिए बने रैन बसेरों की भी हालत नारकीय है. अस्पताल में खून इत्यादि की जांच के नाम पर जमकर वसूली की जा रही है. ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की जर्जर मशीनें खुद ही अपने उपचार की बाट जोह रही हैं. जिला अस्पताल के पड़ोस में स्थित महिला अस्पताल की हालत भी ऐसी ही है.

जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जावेद अहमद कहते हैं कि जिला चिकित्सालय में डेंगू व चिकनगुनिया से पीड़ित कोई भी मरीज पंजीकृत नहीं हुआ और न ही कोई मौत हुई है. जबकि सच यह है कि जनपद खीरी में डेंगू व तेज बुखार से दर्जनों लोगों की मौत हुई है. मरने वालों में रोशन नगर के 24 वर्षीय अरुण शुक्ला, ओयल निवासी 34 वर्षीय सुधांशु सिंह, ग्राम मझगंई के लोकनपुरवा निवासी राजेश राणा के 3 वर्षीय पुत्र हरिओम, रोशन नगर के ही 45 वर्षीय वशीउल्ला, मौलवीगंज के 50 वर्षीय सगीर खां, तीन वर्षीय श्रुति और मोहल्ला ईदगाह निवासी अब्दुल वहीद खां वगैरह के नाम शामिल हैं. दूसरी तरफ डेंगू बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में भी प्रतिदिन इजाफा हो रहा है. गांव पकरिया के वीरेन्द्र वर्मा, मशिरुद्दीन अंसारी, श्रीकेशन जायसवाल, देवेन्द्र, अंकिता गुप्ता, सचिन गुप्ता, भरिगवां के विनीत यादव और द्वारिका डेंगू के घोषित मरीज हैं. फिर भी सीएमओ झूठ बोल रहे हैं. डेंगू को सिरे से नकार रहे सीएमओ इस आधिकारिक तथ्य से भाग रहे हैं कि डेढ़ दर्जन से अधिक मरीज डेंगू की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

फैक्ट्री के ज़हरीले धुएं से 25 वर्ष से ख़राब हो रही फ़सलें

फूंक दी फ़सलें आजिज़ किसानों ने

दिल्ली के बाद यूपी में पसर रहा प्रदूषण, हवा में लाठी भांज रहा तंत्र

दीनबंधु कबीर

दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश प्रदूषण से आक्रांत है. प्रदूषण की रोकथाम के लिए जमीनी उपाय करने के बजाय हवा में लाठी भांजी जा रही है. विभिन्न कल-कारखानों से फैल रहे प्रदूषण को रोकने पर किसी का ध्यान नहीं है. शासन और सरकारी तंत्र फसलों के ठूंठ जलाने से रोकने और दीपावली की आतिशबाजी का बहाना ढूंढने में ही लगे है. शासन के इस अंधत्व के खिलाफ पूर्वांचल के किसानों ने तो अपनी तैयार फसलें ही फूंकनी शुरू कर दी हैं.

गोरखपुर के चौरा चौरा तहसील में एशियन फर्टिलाइज कारखाने से फैल रहा प्रदूषण व्यापक क्षेत्र में लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा है, लेकिन इसे रोकने में प्रशासन या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कोई दिलचस्पी नहीं है. कारखाने से फैल रहे प्रदूषण के कारण फसलें झुलस रही हैं. सरकारी तंत्र कारखाना प्रबंधन से उपकृत है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. मजबूरी में किसानों ने अब अपनी तैयार फसलें ही फूंकनी शुरू कर दी हैं. गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील के देवकहिया समेत कई अन्य गांवों में किसानों ने अपनी फसलों में आग लगा कर विरोध जताया. चौरी चौरा के देवकहिया में एशियन फर्टिलाइज़र फैक्ट्री स्थित है. फैक्ट्री के धुएं से हर साल किसानों की फसलें झुलस जाती हैं, लेकिन सरकार कोई उपाय नहीं कर रही. किसानों ने इसकी शिकायत कई जगह की लेकिन शासन और प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र में खाद बनाने वाली उक्त फैक्ट्री सल्फ्यूरिक एसिड का भी निर्माण करती है, जिससे वातावरण में भीषण प्रदूषण फैल रहा है. इसके खिलाफ किसान अर्से से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा. लाचार होकर किसानों ने अपनी फसलें जलानी शुरू कर दी हैं. पिछले दिनों किसानों ने तैयार धान की फसलों में आग लगा कर विरोध जताया. गन्ना किसान संघर्ष समिति (पूर्वी क्षेत्र) के अध्यक्ष अवधेश सिंह के नेतृत्व में किसानों ने एशियन फर्टिलाइजर के खिलाफ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक को शिकायत पत्र भेजा, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई. अवधेश सिंह ने खुद अपनी डेढ़ एकड़ फसल में आग लगा कर अपना विरोध जताया. इसी तरह देवकहिया के मुसाफिर और नन्दलाल ने एक-एक एकड़, नगई, अर्जुन, होशिला, अयोध्या सिंह ने एक-एक बीघा, ओमप्रकाश गुप्ता ने 15 कट्ठा, अजय ने सात कट्ठा, चईत्तर ने सात कट्ठा, जयहिन्द विश्वकर्मा ने 10 कट्ठा और जयप्रकाश ने 15 कट्ठा खेत में लगी धान की फसल जला दी. किसानों का कहना है कि रसायनिक फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं से फसलों को झुलसाने से अच्छा है कि उन्हें स्वाहा ही कर दिया जाए. किसान कहते हैं कि वे पिछले 25 साल से इस प्रदूषण के खिलाफ विरोध जता रहे हैं लेकिन शासन-प्रशासन की खाल पर कोई असर नहीं पड़ रहा. अपनी फसलों में आग लगाते हुए किसान अत्यंत भावुक थे, लेकिन उनके पास अब कोई उपाय नहीं बचा. ■

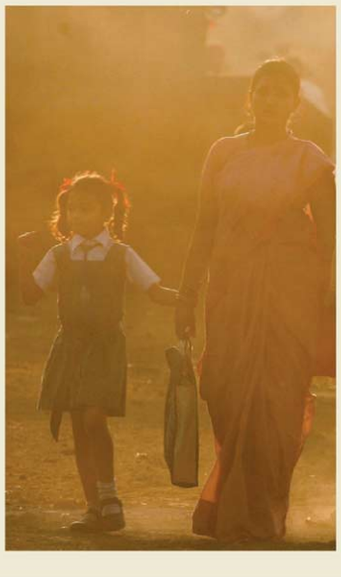

प्रदूषण पर सरकारी ढिलाई के ख़िलाफ़ शिकायत

पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी जहरीली धुंध की चपेट में है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है. लेकिन प्रदूषण रोकने को कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं. शहर के अलग-अलग इलाकों की जांच के आधार पर लखनऊ में प्रदूषण का स्तर सामान्य से आठ गुना ज्यादा पाया गया. जहरीली हवा के मामले में लखनऊ दिल्ली, फरीदाबाद और आगरा के बाद देश में चौथे स्थान पर आ गया है. समाज सेविका उर्वशी शर्मा ने इस बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पर्यावरण, प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, निदेशक पर्यावरण, महापौर लखनऊ, नगर आयुक्त लखनऊ और जिलाधिकारी लखनऊ को पत्र भेज कर त्वरित कार्रवाई की मांग की है.

प्रदूषण की रोकथाम का उपाय करने में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरी तरह नाकारा साबित हुआ है. जबकि प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम के लिए बोर्ड के लखनऊ स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लेकिन प्रदेश के 71 जिलों में से मात्र 21 में ही वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग की जा रही है. तथ्य यह भी बताता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली से सटे नोएडा में बीते फरवरी के बाद से प्रदूषण की जांच तक नहीं की है. उधर, दिल्ली में छाए स्मॉग के कारण पड़ोस के नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा और कानपुर, लखनऊ तक वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर चला गया है. जहरीली गैसों कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइ ऑक्साइड और अन्य गैसों सहित एसपीएम, आरपीएम, सीसा, बेंजीन और अन्य खतरनाक जहरीले तत्वों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है. ■

बढ़ते प्रदूषण पर बढ़ता सरकारी दिखावा

एक तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ सरकारी दिखावा उसी रफ्तार से बढ़ रहा है. आदेश-निर्देश देने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है, उसका अंदाजा बढ़ते प्रदूषण से लगाया जा सकता है. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने पिछले दिनों वरिष्ठ अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि प्रदेश में वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर प्रभावी कार्रवाई हो. प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाए. ट्रैफिक जाम से वायु प्रदूषण न हो, इसके उपाय किए जाएं. हास्यास्पद बात यह है कि प्रदेश के मुख्य सचिव ने प्रदेश की जनता को बेहतर वायु वातावरण उपलब्ध कराने हेतु दो दिन के लिए स्टोन क्रशर्स बंद करने और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अर्थवर्क का काम रोकने का निर्देश दिया. प्रदूषण मसले पर मुख्य सचिव ने पिछले दिनों उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और निर्देश जारी किए. उसी बैठक में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी एसआर सचान भी मौजूद थे, जो बार-बार यही कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण दिल्ली की अपेक्षा कम है. जबकि वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति गंभीर है और विशेषज्ञों का कहना है कि 'एक्रिड स्मॉग' की पूरी संभावना है. एक्रिड को गंध से जोड़ कर देखा जाता है. यह इस तरह का वायु प्रदूषण है, जो केवल देख कर ही नहीं, बल्कि सूंघ कर भी महसूस किया जा सकता है. लखनऊ के क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार जिस स्मॉग ने दिल्ली को घेरा हुआ है, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी छाया है. आने वाले दिनों में यह स्मॉग राज्य में करीब 21 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है. दिल्ली की ही तरह लखनऊ में भी हवा में पीएम 2.5 नाम के ऐसे छोटे कण मिले हुए हैं, जो सांस के साथ फेफड़ों में पहुंच कर उन्हें जाम कर सकते हैं. इनकी मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन की बताई गई सुरक्षित सीमा से कम से कम 40 गुना अधिक पाई गई है.

धार्मिक नगरी में अधर्मी-प्रदूषण

प्रदूषण के कारण धार्मिक नगरी काशी के लोग जानलेवा बीमारी का शिकार हो रहे हैं. यह प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, लेकिन शासन तंत्र को कोई चिंता या शर्म नहीं है. कुछ अर्से पहले ही बीएचयू के वरिष्ठ चेस्ट विशेषज्ञ डॉ. एसके अग्रवाल ने कहा था कि काशी शहर गैस चैंबर में तब्दील हो चुका है. पिछले दिनों उन्होंने अपना पुराना वक्तव्य फिर से दोहराया और कहा कि अब तो स्थिति और भी भयावह हो चुकी है. उन्होंने कहा कि काशी की हालत दिल्ली से भी अधिक खराब और चिंताजनक है. डॉ. अग्रवाल का मानना है कि शहर की हवा का स्तर (क्वालिटी) इन दिनों बेहद निचले स्तर पर है. काशी में कई जगहों पर सांसों के जरिए नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक पीएम 2.5 और पीएम 10 से जुड़ी रियल टाइम रीडिंग हवा के सुरक्षित स्तर से कई गुना ज्यादा है. काशी में 24 घंटे के एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर मापने का कोई पैमाना नहीं है, इसलिए यह पता नहीं चल रहा है कि यह कहां और खतरे के किस स्तर तक पहुंच चुका है. वैसे उनका मानना यह है कि यह सीजन के सबसे खराब स्तर अधिकतम 500 के आसपास होगा. बीएचयू अस्पताल में इन दिनों आने वाले मरीजों की संख्या में भी कई गुना इजाफा देखा जा रहा है. अगर प्रदूषण का यह स्तर बरकरार रहा तो वाराणसी में भी असामयिक मौतों का सिलसिला शुरू हो सकता है. पीएम 2.5 के तत्व इतने सूक्ष्म व खतरनाक होते हैं कि ये पहले सांसों के जरिये फेफड़ों, फिर खून और फिर हृदय में पहुंचकर हार्ट अटैक का कारण बनते हैं. शहर के भीतरी हिस्सों खासकर गोदौलिया, विशेश्वरगंज, मैदागिन, रथयात्रा, कैंट स्टेशन, पांडेयपुर आदि इलाकों के सड़क किनारे रहने वालों के फेफड़ों पर जोखिम बढ़ता जा रहा है. पहले बीएचयू में एक फूंक मारने से जो स्केल 525 तक पहुंच जाता था वह अब चार सौ के आसपास ही रहता है. यह हाल बिल्कुल स्वस्थ लोगों का है. स्पष्ट है कि खुद को बेहद स्वस्थ मानने वाले आम काशीवासियों का फेफड़ा 80 प्रतिशत ही काम कर रहा है. यह बेहद खतरनाक स्थिति है. सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, खुले प्रदूषण के बीच काम करने वाले लोग लगातार धीमी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं. इस पर सरकारें कोई ध्यान नहीं दे रही हैं. ■

प्रगतिशीलता के नाम पर फासीवाद

अनंत विजय

कोलकाता में एक बार फिर प्रगतिशीलता को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही और इस कथित प्रगतिशीलता ने एक बार फिर से प्रगतिशील लेखकों के संविधान विरोधी चेहरे को बेनकाब कर दिया. इस पूरे वाकए से फिर साबित हो गया कि प्रगतिशीलता के आवरण में संविधान विरोध है. दरअसल कोलकाता के भारतीय भाषा परिषद के सभागार में एक आयोजन किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का काव्यपाठ और उपन्यास विवेचना होनी थी. इस आयोजन के निमंत्रण पत्र पर आयोजक के तौर पर ग्यारह संगठनों के नाम छपे थे, जिसमें बंगीय हिंदी परिषद से लेकर भारतीय भाषा परिषद आदि के नाम थे. इनके अलावा आयोजनकर्ता में प्रगतिशील लेखक संघ का भी नाम छपा था. बस यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई. प्रगतिशीलता और जनवाद की ध्वजा थामे हिंदी जगत में विचरण करने वालों को ये बात नागवार गुजरी कि इस आयोजन में प्रगतिशील लेखक संघ कैसे सह आयोजक हो सकता है. सोशल मीडिया पर भी इसके खिलाफ मुहिम शुरू हो गई. फेसबुक पर बेहद सक्रिय कोलकाता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी ने भी प्रगतिशील लेखक संघ पर सवाल खड़े करते हुए लिखा- पश्चिम बंगाल के हिन्दीभाषी लेखकों-संस्कृतिसेवियों के संगठन किस तरह आरएसएस के नेता के लिए लाल कारपेट बिछाकर सेवा में लगे हैं यह निमंत्रण पत्र उसका आदर्श नमूना है. इस निमंत्रण पत्र का सबसे अपमानजनक पहलू है प्रगतिशील लेखक संघ का आरएसएस के नेता के इस आयोजन का हिस्सा बनना. कायदे से संगठन के केन्द्रीय नेतृत्व को बंगाल इकाई के खिलाफ कदम उठाना चाहिए. इस टिप्पणी के साथ जगदीश्वर चतुर्वेदी ने इस आयोजन का निमंत्रण पत्र भी लगाया. अब जरा इसकी भाषा को देखिए जिसमें प्रोफेसर चतुर्वेदी ने एक प्रदेश के राज्यपाल को आरएसएस का नेता करार दिया है. हो सकता है कि केशरीनाथ त्रिपाठी आरएसएस से जुड़े हों, लेकिन हमारा संविधान राज्यपाल के पद को संवैधानिक पद मानता है और उस पद पर बैठे व्यक्ति को दलगत राजनीति से इतर और ऊपर मानता है. ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी लोगों को नहीं है, लेकिन तथ्यों को छिपाकर प्रचार करना तो प्रगतिशीलता की बुनियाद रही है. पहली आपत्तिजनक बात तो ये है कि किसी भी प्रदेश के राज्यपाल को किसी संगठन विशेष का सदस्य करार देकर उनके बहिष्कार आदि की परोक्ष मांग करना. दूसरी बात ये कि किसी दूसरी विचारधारा के लेखक को अस्पृश्य मानना. यहां एक बार फिर से संविधान का अपमान जो कि देश में अस्पृश्यता के खिलाफ है. जो जाति धर्म आदि के आधार पर किसी भी विभेद को मंजूरी नहीं देता है.

फेसबुक पर इस बात के आते ही चंद कथित प्रगतिशील लेखकों ने छाती कूटना प्रारंभ कर दिया. किसी ने इसको प्रगतिशील लेखक संघ का वैचारिक पतन तो किसी ने इसको प्रगतिशील लेखक संघ की अवसरवादिता करार दिया. बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इस विवाद के उछलते ही प्रगतिशील लेखक संघ ने इस आयोजन से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया और ये भी दावा किया गया कि संगठन ने भारतीय भाषा परिषद से विरोध भी दर्ज करवा दिया है. प्रगतिशील लेखक संघ की तरफ से ये बात भी फैलाई गई कि उनके संगठन से जुड़े एक शख्स ने मौखिक तौर पर इस आयोजन से जुड़ने की सहमति दे दी और निमंत्रण पत्र पर आयोजक के दर्जन भर नामों में प्रलेस का नाम भी छाप दिया गया. कोलकाता में निमंत्रण पत्र बांट भी दिए गए लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ को पता नहीं चला. संघ को तो पता तब चला जब फेसबुक पर उसकी लानत-मलामत शुरू हुई. संघ मतलब प्रगतिशील लेखक संघ. सवाल यही उठता है कि क्या प्रगतिशील लेखक संघ के कार्य करने का तरीका इतना लचर हो चुका है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, या फिर वहां इतनी अराजकता है कि कोई भी कुछ भी फैसला ले सकता है. सोशल मीडिया पर तो ये भी बात सामने आई कि भारतीय भाषा परिषद की कुसुम खेमानी ने प्रगतिशील लेखक संघ के सेराज खान बातिश से मौखिक स्वीकृति ले ली थी और कार्ड पर नाम छप कर बंट गए.

दरअसल इस वक्त कथित प्रगतिशील विचारधारा को खुद के सैनिकों से खतरा है. प्रगतिशीलता को ओढ़कर अपनी राजनीति चमकाने वाले ज्यादातर लोग अवसरवादी थे और जब देश में प्रगतिशील विचारधारा का बोलबाला था तो वो उनके ध्वजवाहक बनकर लाभ उठा रहे थे. अब वही लोग दूसरी विचारधारा के साथ हो लिए हैं या फिर हो लेने की फिराक में हैं क्योंकि उन जैसों के लिए तो अवसर ही विचार हैं.

ये तो खैर आरोप-प्रत्यारोप की बात है, सच्चाई तो ऐसे मामलों में कभी सामने आती नहीं है, क्योंकि करार मौखिक था और जबतक दोनों पक्ष स्वीकार ना कर लें तो माना जाना कठिन है.

परंतु इस पूरे विवाद में ये तो सच्चाई है कि प्रगतिशीलता का ताना बाना ओढ़े लोगों को आरएसएस या फिर किसी अन्य की विचारधारा से कितनी तकलीफ है. फासीवाद की बात करने वाले लोग खुद की विचारधारा का फासीवाद स्थापित करना चाहते हैं. लोकतंत्र की स्थापना और उसकी मजबूती की बात करने वाले लोग लोकतंत्र को किस तरह से एकतंत्र में तब्दील करना चाहते हैं इसके इस तरह की घटनाओं से संकेत मिलते हैं. दरअसल इस वक्त कथित प्रगतिशील विचारधारा को खुद के सैनिकों से खतरा है. प्रगतिशीलता को ओढ़कर अपनी राजनीति चमकाने वाले ज्यादातर लोग अवसरवादी थे और जब देश में प्रगतिशील विचारधारा का बोलबाला था तो वो उनके ध्वजवाहक बनकर लाभ उठा रहे थे. अब वही लोग दूसरी विचारधारा के साथ हो लिए हैं या फिर हो लेने की फिराक में हैं क्योंकि उन जैसों के लिए तो अवसर ही विचार हैं. इसी अवसर की तलाश में संभव है कि एक राज्यपाल के कार्यक्रम में आयोजक होना स्वीकार कर लिया गया हो. वैसे अगर देखें तो जहां लाभ आदि की गुंजाइश नजर आती है वहां प्रगतिशीलता नेपथ्य में चली जाती है. चाहे वो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से विदेश यात्रा का आनंद

उठाना हो या फिर संस्कृति मंत्रालय के अनुदान से किसी कार्यक्रम का आयोजन करना हो. केशरीनाथ त्रिपाठी जिस विचारधारा से आते हैं उसी विचारधारा को मानने वाले हमारे देश के संस्कृति मंत्री डॉ महेश शर्मा भी हैं लेकिन महेश शर्मा के मंत्रालय के अनुदान से आयोजित होनेवाले समारोह में प्रगतिशील लेखकों को जाने में कोई दिक्कत नहीं है. वो राजी खुशी वहां जाते हैं. उसी विचारधारा के डॉ रमन सिंह जब रायपुर में साहित्य महोत्सव करते हैं तो प्रगतिशीलता के कई तिलकधारी वहां नजर आते हैं. तो फिर ये स्नॉबरी क्यों, ये दोहरा रवैया क्यों.

प्रतीत तो ये भी होता है कि प्रगतिशील विचारधारा के पोषक अन्य विचारधारा को मुख्यधारा में आने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई अन्य विचारधारा मजबूती से सामने आ गई तो उनकी विचारधारा के अंतर्विरोध एक्सपोज हो जाएंगे. खुद की इस कमजोरी को छुपाने के लिए तरह तरह के तर्कों का सहारा लिया जाता है. कभी फासीवादी तो कभी नफरत की विचारधारा करार देकर उनसे दूरी बनाने के कोशिश की जाती है. ये दांव वहीं चला जाता है, जहां से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है. ये पूरा मामला वही है कि गुड़ खाएं लेकिन गुलगुले से परहेज. दरअसल अगर हम गंभीरता से विचार करें तो मौजूदा सरकार विचारधारा के मामले में काफी उदार नजर आती है. इसी साल जुलाई में हंस पत्रिका के कार्यक्रम में मोदी सरकार को जमकर कोसा गया और उस आयोजन के लिए संस्कृति मंत्रालय ने मदद की थी. अब तीन महीने बाद हंस साहित्योत्सव के लिए एक बार फिर से संस्कृति मंत्रालय ने मदद कर दी. कहीं कोई विवाद नहीं कहीं कोई विरोध नहीं. यही तो है अवसरवादी विचारधारा को मानने वालों का असली चाल चरित्र और चेहरा. हमारे देश में लोकतंत्र की जड़े बहुत गहरी हैं और बहुलतावादी संस्कृति और विचार इसकी ताकत हैं. केशरीनाथ त्रिपाठी या किसी अन्य के कार्यक्रम को विचारधारा के नाम पर बहिष्कार कर देने से लोकतंत्र को कमजोर ही किया जा रहा है. होना तो ये चाहिए कि सभी विचारधारा के लोग साथ बैठें और जमकर बहस करें. एक दूसरे की विचारधारा की कमियों को सामने लाएं, तर्क के आधार पर सिद्धातों को ध्वस्त करें लेकिन इससे भागने से किसी का हित सधनेवाला नहीं है. विमर्श को बाधित करने से वही होगा कि हमारी चिंतन पद्धति कमजोर होगी. अस्पृस्यता को बढ़ावा देनेवाली इसी विचारधारा के मजबूत होने का नतीजा है कि आज जब व्याकरण की बात होती है तो हमारी देश की नई पीढ़ी को पाणिनी का नाम नहीं याद पड़ता है वो तो व्याकरण का नाम सामने आते ही रेन एंड मार्टिन की माला जपने लगते हैं. भारतीय संस्कृति का नाम आते ही उसको पिछड़ा औरर दकियानूसी करार देने लग जाते हैं. हमारे देश की चिंतन पद्धति के विकास के लिए यह आवश्यक है कि सभी विचारधारा के लोग खुले मन से एक साथ बैठें और विचार विनिमय करें क्योंकि अलग अलग विचारों को मानने वाले विरोधी तो हो सकते हैं दुश्मन नहीं होते हैं. और अगर दुश्मन नहीं हैं तो साथ बैठने में क्या आपत्ति. जरा इसपर भी प्रगतिशील लोग विचार करें. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कपास

परिचय

आयुर्वेद की प्राचीन संहिताओं एवं निघण्टुओं में कपास का वर्णन प्राप्त होता है. कपास की रूई का प्रयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है. विश्व में यह मिस्र, अमेरिका, तथा अन्य उष्ण प्रदेशों में भी पाया जाता है. भारतवर्ष के अनेक भागों मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम एवं तमिलनाडू में बहुलता से इसकी कृषि की जाती है. प्रतिवर्ष प्रायः वर्षा के प्रारम्भ होते ही खेतों में इसके बीज बोए जाते हैं. तथा कार्तिक से चैत माह तक रूई को संग्रह कर पौधों को काट दिया जाता है या वे पौधे स्वयं ही सूख जाते हैं.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

❖ **शिरो रोग** : कपास से निर्मित तेल को सिर में लगाने से रूसी नष्ट होती है.

❖ **मस्तक पीड़ा** : कपास की मींगी को पीसकर मस्तक में लेप करने से मस्तक-पीड़ा का शमन होता है.

❖ **नेत्र रोग** : कपास के पत्तों को पीसकर उसमें दही मिलाकर नेत्र के बाहर लगाने से नेत्र-पीड़ा का शमन होता है.

❖ **कर्णस्राव** : सर्ज छालचूर्ण में कपास-फल-स्वरस तथा मधु मिलाकर, एक से दो बूंद कान में डालने से कान का बहना बंद हो जाता है.

❖ जामुन पत्र-स्वरस, आम पत्र-स्वरस, कपित्थ तथा कपास फल-स्वरस को समान मात्रा में लेकर, मधु मिलाकर एक से दो बूंद कान में डालने से कान का बहना बंद हो जाता है.

❖ **कास** : इंगुदी, फल त्वक्, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, मूसली, मनःशिला, कपास की गुठली तथा अश्वगंधा को समान मात्रा में लेकर पीसकर उसकी वर्त्ती बनाकर, घी में डुबाकर धूमपान करने से खांसी में लाभ होता है.

❖ वन्य एवं ग्राम्य दोनों तरह के कपास में एक से दो ग्राम फल कल्क को जल में घोलकर पीने से क्षतज तृष्णा में लाभ होता है.

❖ समभाग कपास तथा प्लक्ष स्वरस 5 मिली को मधु के साथ सेवन करने से कफज अतिसार में लाभ होता है.

❖ 5 मिली कपास पत्र-स्वरस में नींबू स्वरस को समान मात्रा में मिलाकर सेवन करने से पेचिश तथा अतिसार में लाभ होता है.

❖ 5 मिली कपास पत्र-स्वरस में 5 मिली नींबू स्वरस मिलाकर सेवन करने से गुर्दे की पथरी टूट-टूट कर निकल जाती है.

❖ **वातव्याधि** : कपास की गुठली तथा कुलथी क्वाथ में तिल तेल मिलाकर, पकाकर, छानकर सुरक्षित रख लें. इस तेल की मालिश करने से वातव्याधि का शमन होता है.

❖ **संधिशूल** : कपास पत्र तथा बीजों को पीसकर संधियों में लेप करने से संधिशूल का शमन होता है.

❖ **जोड़ों का दर्द** : कपास के पत्तों में तेल चुपड़कर हल्का गर्म करके जोड़ों में बांधने से जोड़ों की वेदना का शमन होता है.

❖ **गठिया** : कपास की मींगी के तेल की मालिश करने से गठिया में लाभ होता है.

❖ **कुष्ठ** : कपास पुष्प कल्क को लगाने से कुष्ठ में लाभ होता है.

❖ वनकपास कूल तथा चावल को पीसकर, पूड़ी बनाकर सेवन करने से गले की गांठ में लाभ होता है.

❖ रूई तथा कपास मूल से निर्मित भस्म को लगाने से सूजन में लाभ होता है तथा इस अवधि में पथ्य के रूप में दूध तथा शालितण्डुल का सेवन करना चाहिए.

❖ **वृश्चिकदंश** : कपास फल को पीसकर, उसमें घी मिलाकर वृश्चिक दंश पर लेप करने से दंशजन्य दाह एवं वेदना का शमन होता है.

❖ **विष** : 500 मिग्रा से 1 ग्राम कपास की मींगी को दूध के साथ पीसकर पिलाने से समस्त प्रकार के विषों का शमन होता है.

❖ कपास मूल को चबाने से बिच्छू का विष उतरता है.

प्रयोज्यांग : *मूल, मूल त्वक्, काण्ड त्वक्, पत्र, पुष्प तथा बीज.*

मात्रा : *चूर्ण 3-6 ग्राम. क्वाथ 20-50 मिली. तेल 10-25 मिली.* ■

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

धर्म-स्थान एवं वेशभूषा

परिस्थिति के अनुरूप वेशभूषा धारण करें

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

पिछले अंक से आगे

हर व्यक्ति के जीवन में दुःख और सुख दोनों हैं. इस कारण मन्दिर में हर व्यक्ति को शांत भाव से रहना चाहिए. यह स्थान भक्तों द्वारा सम्मिलित रूप से मन और आत्मा को ईश्वर के प्रति एकाग्र करके पूजा एवं आरती आदि करने के लिए है. जब मंदिरों में एकत्रित भक्त सामूहिक रूप से अपने विचार, भावना एवं कर्म को एक ही धारा में सम्मिलित करके इष्ट या सद्गुरु की प्रार्थना/आह्वान करते हैं, तब भक्तों पर इष्ट या सद्गुरु का प्रेम और दिव्य शक्ति भी बरसती है. मंदिर अथवा धार्मिक समारोहों में जाने की विधि और वास्तविक उद्देश्य यही है.

दूसरी ओर एक ऐसी परिस्थिति के बारे में कल्पना कीजिए की मंदिर का ऐसा पवित्र वातावरण जब ध्यानमग्न भक्तों की आत्मा की दिव्यानंद की उच्चतर स्थिति में ले जा रहा हो कि तभी ऐसे में कोई एक भक्त मंदिर में प्रवेश करता है, जिसकी अटपटी वेशभूषा, पारस्परिक बातचीत या जोर-जोर की हंसी जाने-अनजाने में अन्य भक्तों का ध्यान भंग करती है और मंदिर का वातावरण दूषित हो जाता है. मैंने देखा है कि साईं-मंदिरों में भक्तों का ध्यान अपने आराध्य यानि श्री साईंनाथ महाराज की मूर्ति से हटकर ऐसे लोगों की ओर आकर्षित हो जाता है. ऐसी स्थिति में मंदिर आने का पूरा उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है.

शिरडी के श्री साईं बाबा कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करते थे कि उनके भक्त एवं कार्यकर्ता इस प्रकार की अनावश्यक वेशभूषा धारण करें. प्रसिद्ध कीर्त्तनकार श्री दासगणु जो कि बाबा एवं अन्य संतों की जीवन-गाथा का गायन करते थे, एक बार बाबा का कीर्त्तन करने के लिए किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते समय बाबा के पास आये. उस समय उन्होंने तड़कीली-भड़कीली पोशाक पहन रखी थी. तब उन्हें देखकर बाबा ने उनसे इस प्रकार की चमक-दमक वाली महंगी और दिखावटी पोशाक धारण न कर अत्यन्त सादगी वाली साधारण वेशभूषा पहनकर उस कार्यक्रम में जाने के लिए कहा.

बाबा के इन उपदेशों को ध्यान में रखते हुए शिरडी साईं-भक्तों के लिए उचित यह होगा कि जब भी वे मंदिर में बाब की पूजा के लिए या किसी धार्मिक आयोजन/सभा में भाग लेने जायें, तो परिस्थिति के अनुरूप सादी वेशभूषा धारण करें. बाबा की शिक्षाएं यही दर्शाती हैं कि भक्तों द्वारा फिजूल एवं आडंबरपूर्ण भौमिकता-प्रदर्शन या चमचमाती हुई वेशभूषाओं को बाबा का कभी भी समर्थन नहीं था. फटे वस्त्र धारण करने वाले फकीर श्री साईं बाबा सादे वस्त्र पहनने वाले सच्चे लोगों के साथ ज्यादा आत्मीय अनुभव करते थे.

इस संदर्भ में मैंने यह भी देखा है कि बहुत से भक्त बाबा को कफनी (शरीर को पूरा ढकने वाला चोगा) पहना देख उनकी देखा-देखी खुद भी कफनी और पटके की वेश-भूषा धारण करने लगते हैं. उनमें से कुछ तो हाथ में सटका भी लिए रहते हैं. प्रसिद्ध गुरु गीता में यह निर्दिष्ट है कि भक्तों को अपने गुरु के वेश, मुद्रा या व्यवहार की नकल नहीं करनी चाहिए. आध्यात्मिक जगत में गुरु-शिष्य संबंधी एक सर्वमान्य नियम है. यहां तक कि लोकप्रसिद्ध श्री विवेकानन्द ने कभी भी अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जैसा आचरण करने या उनके जैसा वेश धारण करने की नकल नहीं की. निःसंदेह, श्री साईं के कुछ भक्त चूंकि उन्हें अच्छा लगता है, अतः अज्ञानवश बाबा जैसी वेशभूषा धारण करते हैं. लेकिन बहुत से ऐसे धोखेबाज पाखंडी लोग भी हैं, जो कि बाबा जैसी वेशभूषा धारण कर भोले-भाले भक्तों को बहका कर उनसे पैसा ऐंठते हैं और उनकी सरलता का फायदा उठाते हैं. इसलिए मंदिर की ट्रस्ट के लिए उचित यह होगा कि वे विनम्रतापूर्वक मंदिर में आने वाले भक्तों को इस दिशा में प्रेरित करें कि वे मंदिर में उचित वेशभूषा पहन कर आएं एवं मंदिर के प्रांगण में उचित रूप से व्यवहार करें. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

फिर अपने रंग में लौट रही भारतीय हॉकी

सैयद मोहम्मद अब्बास

भारतीय हॉकी अब सुर्खियों में है, लेकिन इस बार किसी विवाद के लिए नहीं, बल्कि अपने शानदार खेल के लिए. अभी हाल में ही भारतीय टीम ने एशियाई चैम्पियंस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को धूल चटाकर अपनी हॉकी का लोहा मनवाया. हाल के दिनों में भारतीय हॉकी टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है. हालांकि ओलम्पिक में भारत भले ही पदक जीतने से चूक गया हो लेकिन उसने अपने आक्रमक खेल की बदौलत खूब वाहवाही लूटी थी. यह वही हॉकी टीम है जो अपने सुनहरे दिन को दोबारा हासिल करने के लिए जूझ रही है. इतिहास में भारतीय हॉकी अमर रही है. भारतीय हॉकी का कोई सानी नहीं था. ध्यानचंद का सपना पूरा करने के लिए अभी भारतीय हॉकी को लंबा सफर तय करना है. वक्त और हालात दोनों भारतीय हॉकी से रूठे रहे हैं लेकिन अब वक्त ने थोड़ी करवट बदली है. टीम में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं. टीम में युवा खिलाड़ी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. एशियन मेन्स हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जीत इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को मात दी है. खिताबी जंग में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया है. इस जीत में टीम के अनुभवी खिलाड़ी रूपिंदर सिंह पाल व निकिन थिमैया का खास योगदान रहा है. भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे दानिश मुजतबा ने भी भारत की जीत पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने चौथी दुनिया से खास बातचीत में कहा कि टीम अब पुरानी लय में लौट रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम का लक्ष्य है कि वह अपनी रैंकिंग में और सुधार कर सके. दानिश के अनुसार टीम नम्बर वन बनने के लिए मजबूती से कदम बढ़ा रही है. दरअसल भारतीय टीम मौजूदा रैंकिंग में छठे पायदान पर है. उन्होंने कोच रोलैंट ओल्टमैंस की तारीफ करते हुए कहा कि उनके आने से भारतीय टीम की तस्वीर बदल गई है. दानिश ने माना कि रोलैंट ओल्टमैंस की कोचिंग से टीम तकनीकी रूप से भी काफी मजबूत हुई. दानिश ने बताया कि कोच टीम के खिलाड़ियों को कहते हैं कि हॉकी में डिफेंस और आक्रामक खेल दोनों ही बेहद जरूरी है, लेकिन मैच जीतना है तो आक्रामक खेलना होगा और टूर्नामेंट जीतना है तो डिफेंस भी रखना आवश्यक होगा. यानी दोनों ही चीजें अहम हैं. ओलम्पिक में आठवें नम्बर पर रहने वाली टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल दिखाया लेकिन अंतिम पलों में कमजोर प्रदर्शन के चलते टीम पदक की दौड़ से बाहर हो गई. उन्होंने बताया कि कोच रोलैंट ओल्टमैंस खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से कोचिंग दे रहे हैं. टीम के खिलाड़ी भी रोलैंट ओल्टमैंस की शैली समझने लगे हैं. भारतीय हॉकी टीम एशियाई देशों में अव्वल मानी जाती रही है लेकिन अभी उसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को हराने के लिए कड़ा अभ्यास करना होगा. इतना ही नहीं, हाल के दिनों में भारत के आलावा बेल्जियम और अर्जेंटीना ने भी अपनी हॉकी में गजब का सुधार किया है. दूसरी ओर भारतीय टीम अपने नये कोच के साथ नये प्रतिमान स्थापित करने के लिए लगातार अपनी हॉकी की शैली में काफी बदलाव कर रही है. भारत पहले देसी कोच के सहारे अपनी हॉकी को चमकाने में लगा था, लेकिन अब विदेशी कोच के आने से टीम में एक अलग ही उत्साह देखा जा सकता है. उधर हॉकी इंडिया ने भी कोच रोलैंट ओल्टमैंस की कोचिंग से बेहद खुश होकर उनका करार 2020 तक कर दिया है. ऐसे में रोलैंट ओल्टमैंस के पास लम्बा वक्त है जिससे वह भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर की कहानी फिर से दोहरा सकें. एशियाई हॉकी का सिरमौर बनने में कोच रोलैंट ओल्टमैंस का खास योगदान रहा है. रियो ओलम्पिक में भले ही टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा हो लेकिन उस नाकामयाबी को पीछे छोड़ते हुए टीम ने एशियाई टूर्नामेंट में बेहतर खेल दिखाया. भारत ने नये सीजन के लिए कड़ा अभ्यास किया. इसी को ध्यान में रखकर टीम को कड़े फिटनेस से भी गुजरना पड़ रहा है. यह बात भी सत्य है कि रियो में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी हॉकी की धमक से दुनिया के कई देशों के माथे पर बल ला दिया था. पूरी दुनिया में भारतीय हॉकी की प्रशंसा हो रही है. दरअसल भारत अभी से अगले ओलम्पिक व विश्व कप के लिए तैयार हो रहा है. इसी को ध्यान में रखकर कोच रोलैंट ओल्टमैंस की देखरेख में हॉकी इंडिया जूनियर खिलाड़ियों को बड़े स्तर के लिए तैयार करना चाहता है. जूनियर खिलाड़ियों के लिए यूपी में होने वाली जूनियर विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करने का सुनहरा मौका होगा. रोलैंट ओल्टमैंस की कोशिश है कि मिडफील्ड और फारवर्ड पोजिशन के लिए टीम और मजबूत हो. उनके कोच रहते भारतीय टीम ने कई मौकों पर देश का गौरव बढ़ाया है. उनमें सबसे प्रमुख है चैम्पियंस ट्रॉफी में रजत पदक जीतना. जबकि पिछले साल दिसम्बर में वर्ल्ड लीग में भी जानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक पर कब्जा किया था. इसके साथ ही अब एशियाई टूर्नामेंट में खिताब जीतकर भारत को शीर्ष टीम में शामिल करने की शुरुआत हो गई है.

भारतीय हॉकी के इतिहास पर गौर किया जाये तो एक वक्त ऐसा भी था जब भारतीय हॉकी की तूती पूरे विश्व में बोलती थी. हॉकी के जनक मेजर ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को बुलंदियों पर पहुंचाया. इतना ही नहीं 1920 से 1980 तक भारतीय हॉकी का डंका पूरे विश्व में बोलता था. उस दौरान भारत ने ओलम्पिक में 11 पदक भी जीते. उसी दौरान कई और अहम प्रतियोगिता में भारत ने कई पदक अपने नाम किये. उसमें 1975 में विश्व कप का खिताब भी शामिल है.

श्रीजेश

रूपिंदर पाल सिंह

दानिश मुजतबा

आकाशदीप

भारतीय हॉकी के मौजूदा प्रदर्शन पर गौर किया जाये तो अभी उसने अतीत से प्रेरणा लेते हुए एशियन मेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है. इससे पूर्व भारत ने साल 2011 में इस प्रतियोगिता का खिताब जीता था. इस बार भारतीय टीम एक भी मैच हारी नहीं. टीम को केवल एक मुकाबले में ड्रॉ से संतोष करना पड़ा था. दक्षिण कोरिया के खिलाफ टीम ने मुकाबले को बराबरी पर रोक दिया था.

टीम के खिलाड़ियों की बात की जाये तो इस समय टीम में एक खिलाड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में है, वह है रूपिंदर पाल सिंह है. इनकी करिश्माई हॉकी को विश्व में खूब सराहा जा रहा है. इस ड्रैग-फ्लिकर को काबू में करने के लिए विरोधियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. रूपिंदर पाल सिंह ने इस टूर्नामेंट में कुल 11 गोल दागकर हॉकी का लोहा मनवाया. यह प्रदर्शन उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. उन्होंने खिताबी जंग में भी एक गोल किया था जबकि जापान के खिलाफ उन्होंने छह गोल दागकर विरोधियों के छक्के छुड़ा दिये थे. इतना ही नहीं पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भी एक-एक गोल किये. उन्होंने साल 2010 में अपने करियर की शुरुआत की थी. अब अपने जानदार खेल की बदौलत अपनी टीम में उन्हें अहम खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है. करियर के शुरुआती दौर में उनकी हॉकी चर्चा में बनी रही. साल 2011 में सुलतान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता में रूपिंदर पाल सिंह ने बेहद खास प्रदर्शन करते हुए ब्रिटेन के खिलाफ हैट्रिक गोल दागकर सबको अपनी हॉकी का मुरीद बना दिया था. इसके बाद उनको भारतीय टीम का उपकप्तान बना दिया गया था. भारतीय हॉकी टीम के नये स्टार के रूप में उनको देखा जा रहा है. छह फीट के लम्बे कद के रूपिंदर पाल सिंह के ममेरे भाई गगनजीत सिंह भी भारत के अच्छे हॉकी खिलाड़ियों में शामिल हैं. मिडफील्ड के रूप में शामिल रूपिंदर पाल सिंह हाल के दिनों में ड्रैगफ्लिकर के तौर पर भी टीम में खास योगदान दे रहे हैं. एशियन मेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में रूपिंदर पाल सिंह के आलावा कई और खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टीम की जीत में अहम योगदान दिया. उनमें निकिन थिमैया का नाम शामिल है. उन्होंने खिताबी जंग में पाकिस्तान के खिलाफ अहम गोल दागा था. इतना ही नहीं लीग मैचों में भी निकिन थिमैया ने भारतीय हॉकी को बुलंद किया. दूसरी ओर भारतीय हॉकी टीम के कप्तान श्रीजेश भी टूर्नामेंट भारतीय खिलाड़ियों के लिए अहम कड़ी साबित हुए. गोलकीपर के रूप में वह भारत के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरों में एक हैं. हाल के दिनों में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें भारतीय हॉकी टीम की कमान सौंप दी गई. सरदार सिंह की खराब फिटनेस के बाद श्रीजेश के रूप में हॉकी इंडिया को कप्तानी के लिए सबसे बड़ा विकल्प मिल गया. श्रीजेश ने 2004 में जूनियर टीम में अपनी उपयोगिता साबित करने के बाद सीनियर टीम में अपना दावा ठोका. 2006 में सीनियर टीम में उन्हें भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया. वह कई मौकों पर भारत के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में चुने गये. क्लब लेवल पर भी उनकी गोलकीपिंग को लोगों ने काफी सराहा है. एशियन मेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी गोलकीपिंग चरम पर रही. उन्होंने कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में आखिरी गोल रोक कर टीम की जीत में खास योगदान दिया था. हालांकि फाइनल में वह चोट के चलते नहीं खेल सके. हाल के दिनों में भारतीय हॉकी टीम के कई खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल की बदौलत विश्व हॉकी पटल पर अपनी अलग पहचान बनायी है. अनुभवी ड्रैग फ्लिकर वीआर रघुनाथ की हॉकी की तूती अब पूरे विश्व में सुनाई पड़ती है. हालांकि वह अभी अपनी खराब फिटनेस से जूझ रहे हैं लेकिन उनके लौटने से टीम को मजबूती मिलेगी. वीआर रघुनाथ अभी कोहनी की चोट से बेहाल हैं. हॉकी इंडिया को उम्मीद है कि वह जल्द अपनी चोट से उबर जाएंगे. टीम में उनके आलावा आकाशदीप व दानिश मुजतबा जैसे खिलाड़ी प्रमुख माने जा रहे हैं. प्रतिस्पर्धी हॉकी के लिए युवा खिलाड़ियों को अभी काफी मेहनत करनी होगी. युवा खिलाड़ियों को सीनियर खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि भारतीय हॉकी में सुधार हो सके.

भारतीय हॉकी टीम को अब अपने खेल को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इस समय दुनिया की कई बड़ी टीमें लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. एशिया में मिली जीत का कारवां आगे बढ़ाने की जरूरत है. भारत को आने वाले विश्व कप के लिए लगातार दुनिया की बड़ी टीम को हराना होगा तभी वह रैंकिंग में आगे बढ़ सकता है. ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसी टीम को पकड़ना है, तो इसके लिए खास रणनीति आवश्यक होगी. ये टीमें ऐसी हैं, जो अपनी खास तरह की हॉकी के लिए जानी जाती हैं.

अतीत में भारतीय हॉकी बुलंदियों पर रही लेकिन बाद में इस खेल को लेकर कई बातें कही जाने लगीं. संघों में एकजुटता की कमी भी देखी गयी. हॉकी को चलाने वाले संघ ने हॉकी के नाम पर खूब खेल खेला. इतना ही नहीं बदहाल हॉकी को देखकर इसके राष्ट्रीय खेल पर भी सवाल उठा दिया गया. दरअसल सच्चाई यही है कि हॉकी को लेकर हमेशा भेदभाव रखा गया. जहां एक ओर क्रिकेट में लगातार भारत का नाम चमक रहा है, वहीं हॉकी के नाम पर कुछ भी नहीं होता है. हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं आता है. लेकिन अब भारतीय हॉकी के हालात थोड़े बदले हैं. प्रदर्शन भी अब पहले के मुकाबले अच्छा हो रहा है. खिलाड़ी अब हॉकी से जुड़ने के लिए आगे भी आ रहे हैं. कुल मिलाकर देखा जाये तो हाल के दिनों में हॉकी इंडिया ने भी भारतीय हॉकी के हित में कई बड़े कदम उठाये हैं. क्रिकेट की तरह हॉकी में भी कई बदलाव किये गये हैं. हॉकी इंडिया लीग से भारतीय खिलाड़ियों को अब अलग पहचान मिल रही है. भारतीय हॉकी के प्रदर्शन से अब एक उम्मीद की नई किरण जगी है. उम्मीद है कि भारतीय हॉकी का सुनहरा दौर एक बार फिर जगमगाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

ऐ दिल... की सफलता से ख़ुश हैं ऐश्वर्या राय बच्चन

कहा जा रहा है कि दीवाली पर प्रदर्शित करण जौहर की फिल्म को भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली है. कहानी में कोई ऐसा नयापन देखने को नहीं था जिसकी चर्चा की जाए. लेकिन इस फिल्म की औसत सफलता से इसकी नायिका ऐश्वर्या राय बच्चन को जरूर सफलता मिल गई है. अपनी वापसी के बाद दो असफल फिल्में जज्बा और सरबजीत देने वाली ऐश्वर्या के करियर में ऐ दिल है मुश्किल एक पड़ाव साबित हुई है. इस फिल्म की सफलता के बाद निर्माता निर्देशकों में ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए फिर से उम्मीदें बढ़ा दी है. ऐश को लगने लगा है कि दर्शकों में अब भी ऐश्वर्या राय बच्चन का क्रेज बाकी है. करण जौहर के निर्देशन में बनी ऐ दिल है मुश्किल में उनका किरदार बमुश्किल 20 मिनट का है, जिसमें करण जौहर ने उन्हें बहुत ही सुन्दरता के साथ सेल्यूलाइड के परदे पर पेश किया है. उनकी ख़ूबसूरती ने दर्शकों को अपने साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है और यही ख़ूबसूरती अब उनके घर के बाहर निर्माताओं की लाइन लगवाने में मदद करेगी.■

फिल्मी ख़बरें

डॉन का कमबैक

शाहरूख खान की फिल्म डॉन और डॉन-2 की सीरीज सभी को इतनी पसंद आई थी कि आज भी लोग इसके डायलॉग अक्सर बोलते हैं. इससे पहले 70 के दशक में आई फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन ने जबरदस्त भूमिका निभाई थी. अमिताभ की यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर खिताब भी दिया गया था.

वहीं डॉन-2 में शाहरूख ने भी काफी दमदार अभिनय किया था. दर्शक चाहते हैं कि डॉन-3 भी बने, तो आपको बता दें कि आपका इंतजार ख़त्म हो गया. डॉन-3 के लिए लंबे समय से शाहरूख के फैंस नज़रें टिकाए बैठे थे कि फिल्म को लेकर कोई घोषणा हो. अब यह इंतजार भी ख़त्म हो गया है, फरहान द्वारा निर्देशित फिल्म डॉन-3 शाहरूख की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और फरहान और रितेश सिधवानी के एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस होगी.■

कंगना रनौत का नया शिकार बनी प्रियंका

कहते है कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली कड़वी बातें कभी वापस नहीं ली जा सकती. यह बात कंगना पर भी एक दम फिट बैठती है. बॉलीवुड में उन हीरोइनों में कंगना रनौत भी शामिल हैं, जो जब भी मुंह खोलती है तो हंगामा हो ही जाता है. हाल ही में ऋतिक रोशन से लेकर उनके पिता राकेश रोशन को अपनी जुबान के तीखे तीरों से घायल कर चुकी कगना के निशाने पर अब कोई और आ गया है. कगना ने इस बार अपना नया शिकार प्रियंका चोपड़ा को बनाया है.

कंगना ने प्रियंका के बारे में कुछ ऐसा कह दिया, जो शायद प्रियंका को चुभ सकता है. कंगना ने कहा कि प्रियंका की हंसी सबसे ज्यादा फेक यानि नकली लगती है और इसके लिए उन्हें एक अवॉर्ड मिलना चाहिए. अब बैठे बिठाए दूसरों की नाराज़गी मोल लेने का कंगना को शौक सा बन गया है. अब देखते है कि कंगना की इस बात को लेकर प्रियंका आने वाले समय में क्या जवाब देती है.■

क्या आप जानते हैं अजय देवगन के बारे में ये बातें?

एक्टर नहीं डायरेक्टर बनना चाहते थे अजय देवगन

समय के साथ-साथ अजय की चमक बढ़ती जा रही है, मीडिया से बच कर रहने वाले अजय अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं. इसलिए बहुत कम लोगों को उनके बारे मे पता है कि वो निजी जीवन में कैसे इंसान हैं.

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन वो पहले स्टार हैं, जिन्होंने सबसे पहले सिक्स सीटर अपना पर्सनल जेट प्लेन खरीदा था. इससे पहले बॉलीवुड के किसी स्टार के पास अपना पर्सनल प्लेन नहीं था.

प्रवीण कुमार

वर्ष 1991 में आई रोमेंटिक व एक्शन से भरपूर सुपरहिट फिल्म *फूल और कांटे* से बॉलीवुड में कदम रखने वाले इंडस्ट्री के सिंघम अजय देवगन अपनी गंभीर एक्टिंग के लिए आज सबसे बेहतरीन कलाकारों में गिने जाते हैं. कहते है कि अजय की आंखे इतनी नशीली है कि अभिनय के दौरान कई बातें वह अपनी इन आंखों के जरिए बयां कर देते है, जो अच्छे से अच्छे एक्टर भी नहीं कर पाते. इसलिए गंभीर अदाकारी करने में जो महारथ अजय देवगन को हासिल है वह किसी और अभिनेता को नहीं है. अजय देवगन को बॉलीवुड में दो दशक से भी ज्यादा समय हो चुका है और वह अब भी अपने साथी कलाकरों और नए अभिनेताओं को अभिनय के मामले में कड़ी टक्कर देते आ रहे हैं.

90 के दशक के मशहूर डायरेक्टर्स के चक्कर लगाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन तभी अजय देवगन के पिता वीरु देवगन ने उन्हें फिल्म *फूल और कांटे* ऑफर कर दी. असल में अजय देवगन के पिता ही चाहते कि वो एक एक्टर बनें और हुआ भी ऐसा ही, लेकिन आज अजय देवगन एक अच्छे एक्टर होने के साथ एक डायरेक्टर भी हैं जो उनका सपना भी था. हाल ही में अजय ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म *शिवाय* को भी डायरेक्ट किया है जो दर्शकों को बहुत पसंद आ रही हैं.

समय के साथ-साथ अजय की चमक बढ़ती जा रही है, मीडिया से बच कर रहने वाले अजय अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं. इसलिए बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता है कि वो निजी जीवन में कैसे इंसान हैं.

लेकिन कुछ बाते ऐसी भी होती है जो कुछ समय के लिए छुपाई जा सकती है पर समय आने पर उनका खुलासा होनो स्वाभाविक है. आइए जानते हैं, अजय देवगन के बारे में कुछ ऐसे रोचक किस्से जो उनके फैन्स को कम ही पता होंगे.

- क्या आप जानते हैं कि अजय देवगन पहले एक डायरेक्टर बनना चाहते थे. उन्होंने इसके लिए 90 के दशक के मशहूर डायरेक्टर्स के चक्कर लगाना भी शुरू कर दिया था...

- पूरी दुनिया में अजय देवगन के नाम से फेमस इस कलाकार का असली नाम विशाल देवगन है. बताया ये जाता है कि जब अजय फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रहे थे, तब बॉलीवुड में काफी कलाकार आये थे जिनका नाम विशाल था इसलिए उन्होंने अपने करीबियों के सुझाव पर अपना नाम बदल कर अजय रखा, जिसे आज दुनिया अजय देवगन के नाम से जानती है.

- ख़बरों की माने तो एक समय करिश्मा कपूर के लिए अजय देवगन ने रवीना टंडन का साथ छोड़ दिया था. इससे नाराज़ होकर एक बार रवीना टंडन ने मीडिया में कह दिया था कि, अगर कभी उन दोनों की शादी हो भी जाती है तो उनके बच्चे जेब्रा की तरह पैदा होंगे. रवीना टंडन के इस कमेंट से अजय देवगन काफी नाराज़ हुए थे और फिर कभी उन्होंने एक साथ काम नहीं किया.

- फिल्मी पर्दे का ये सुल्तान मिर्जा बॉलीवुड के शहंशाह को एक सम्पूर्ण अभिनेता मानता है. अपने एक इंटरव्यू में पूछने पर उन्होंने बताया था कि वो अमिताभ बच्चन को सबसे बेहतरीन कलाकार मानते हैं.

- आपको पता है जब पहली बार काजोल ने अजय देवगन को देखा था तो उन्हें वो पसंद नहीं आये थे, लेकिन काजोल को उनकी आंखे बहुत पसंद आयी थी. जब दोनों ने साथ काम करना शुरू किया और मुलाकातों का दौर शुरु हुआ तब काजोल उनके प्यार में पड़ती चली गयीं और आज दोनों को बॉलीवुड की सबसे ख़ूबसूरत जोड़ियों में से एक माना जाता है.

- बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन वो पहले स्टार थे, जिन्होंने सबसे पहले अपना पर्सनल सिक्स सीटर जेट प्लेन खरीदा था. इससे पहले बॉलीवुड के किसी स्टार के पास अपना पर्सनल प्लेन नहीं था.

- आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अजय देवगन को सीरियस या एक्शन फिल्मों से ज्यादा कॉमेडी फिल्में पसंद हैं. जबकि अजय देवगन को हमेशा से एक एक्शन स्टार के रूप में जाना जाता था. अजय ने कॉमेडी फिल्मों का सिलसिला काफी समय बाद शुरू किया जब उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ कोलेबरेशन किया था.■

feedback@chauthiduniya.com

फोर्स-2 जॉन और सोनाक्षी का ज़बरदस्त एक्शन

साल 2011 में आई जॉन अब्राहम की फिल्म *फोर्स* ने धमाल मचा दिया था. फिल्म में शानदार एक्शन, स्टोरी, इमोशन वह सब कुछ था जो फिल्म को हिट करवाने के लिए काफी था. इस बार 18 नवंबर 2016 को फोर्स-2 रिलीज हुई है. जिसमें जॉन अब्राहम और सोनाक्षी सिन्हा जबरदस्त एक्शन करते हुए नज़र आएंगे.

फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक्शन है, जो आपको रोमांचित कर देगा. फिल्म से जुड़े सूत्रों की मानें तो फिल्म में आठ भव्य और नायाब एक्शन से भरपूर दृश्य हैं, जो दर्शकों को शुरू से लेकर आखिरी तक बांधे रखेंगे.

इस फिल्म में जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका हैं. उन्होंने जहां पहले भाग में अपने हाथों से बाइक उठाई थी, वहीं दूसरे भाग में वह मर्सिडीज कार उठाते नज़र आएंगे. सोशल मीडिया पर फिल्म का ट्रेलर पहले ही हिट हो चुका है. अपने एक्शन से जॉन और सोनाक्षी ने फिल्म में जान डाल दी है.■

अब्बास-मस्तान के साथ फिर काम करेंगे अक्षय कुमार

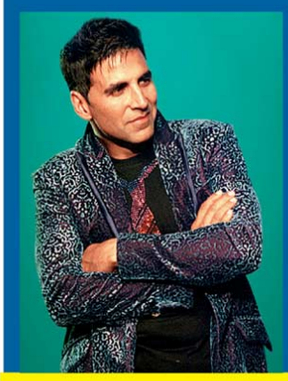

बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी अक्षय कुमार को पहली बड़ी सफलता और पहचान फिल्म *खिलाड़ी* से मिली थी, जिसका निर्देशन अब्बास-मस्तान ने ही किया था. इनकी वजह से ही अक्षय को खिलाड़ी कुमार के नाम से पहचाना जाता है. खिलाड़ी के बाद इन्होंने अजनबी और एतराज में एकसाथ काम किया. दोनों ही फिल्मों ने अच्छी कमाई की थी.

निर्देशक जोड़ी ने कहा, हमने एक साथ तीन फिल्में की हैं और सभी एक दूसरे से अलग थीं. हम फिर से एक साथ काम करने की योजना बना रहे हैं. इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म *मशीन* को लेकर अब्बास-मस्तान काफी उत्साहित हैं. इस फिल्म से अब्बास के बेटे मुस्तफा बतौर अभिनेता बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखेंगे.

इस फिल्म पर विशेष ध्यान देने के सवाल पर दोनों ने कहा, हम जब भी फिल्म बनाते हैं, तो उस पर ध्यान देते हैं और मेहनत करते हैं, जो हमने इस फिल्म में भी की है. फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और बाकी काम किया जा रहा है. हम अगले साल इसकी अच्छी रिलीज की उम्मीद कर रहे हैं. हम उसे बड़े स्तर पर लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं. इस रोमांटिक थ्रिलर फिल्म में कियारा अडवाणी भी मुख्य भूमिका में नज़र आएंगी.■

ऋतिक पर मंडरा रहा है ये बड़ा ख़तरा!

ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म *काबिल* का ट्रेलर इंटरनेट पर रिलीज़ होते ही छा गया, लेकिन यहां एक शॉकिंग ट्विस्ट है. दरअसल, काबिल के ट्रेलर को इस तरह रिलीज़ करना मेकर्स के प्लान में नहीं था. प्रोड्यूसर राकेश रोशन ट्रेलर 26 अक्टूबर को एक इवेंट में रिलीज़ करना चाहते थे, लेकिन 25 अक्टूबर की शाम को ये इंटरनेट पर लीक हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे ही काबिल की टीम को इस लीक का पता चला, उन्होंने इसे ऑनलाइन शेयर करना शरू कर दिया, ताकि लीकेज का इंपेक्ट कम हो जाए. इसी के चलके ऋतिक ने भी अपने ट्वीटर एकाउंट से ट्रेलर का यू-ट्यूब लिंक शेयर किया था.इस पूरे इंसिडेंस ने प्रोड्यूसर राकेश रोशन को भी शॉक कर दिया और उन्होंने फिल्म की रिलीज़ तक लीकेज को रोकने के लिए पुख्ता इंतज़ाम करने शुरू कर दिए हैं.

फिल्म काबिल को संजय गप्ता ने डायरेक्ट किया है. यह फिल्म ऋतिक रोशन के करियर के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी पिछली कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया. मोहनजोदड़ो तो उनकी करियर की डिजास्टर मूवी मानी जा रही है. इस लिहाज से ऋतिक के लिए फिल्म काबिल का हिट होना बहुत जरूरी है. फ़िल्म काबिल में ऋतिक के साथ यामि गौतम लीड रोल में हैं. फ़िल्म में दोनों के किरदार ब्लाइंड दिखाए गए हैं. रोनित रॉय और रोहित रॉय निगेटिव रोल्स में नज़र आएंगे.■

मोहनजोदड़ो ऋतिक के करियर की डिजास्टर मूवी मानी जा रही है. इस लिहाज से ऋतिक के लिए फिल्म काबिल का हिट होना बहुत जरूरी है.